

प्रापिकार से जकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 23]

नई बिहलो, शनिवार, जून 8, 1996/ज्यव्ह 18, 1918

No. 231

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 8, 1996/JYAISTHA 18, 1918

इ.स. भाग में भिन्न पृष्क इंक्या वी जाती है जिससे कि यह अजग संकासन के कप में

रसाजा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत तरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़तर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश भीर अधिब् चताएँ Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण त्रिभाग) नई दिल्ली, 23 मई, 1996

काल्या । 576. — केन्द्रोय सरकार एतद्हारा दंड प्रक्रिया संहिता. 1973 (1974 का प्रधिनियम सं० 2) की धारा 24 की उपधारा (8) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री बी० हनुमा रेड्डी और एम० श्री रामाभूषि, अधिकत्ताओं को, मेणन न्यायालय, ओंगोल, जिला प्रकाणम, श्रान्ध प्रदेश में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना हारा श्रन्वेषित प्रयश्च संस्थित मामला सं० ग्रारसी-1(एस)/96/सीबी शाई/एसगीई/एमप्राईटी मद्राम (श्री मागृटा मुख्या रामा रेड्डी हत्या कांड) तथा उपसे पंजित ग्रयवा श्रानुषैणिक किमी श्रन्य विषय का संचालन करने के लिए, विशेष लोक ग्राभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[मं० 225/90/96-ए०वी०खी०-II] एस० सौन्दर राजन, श्रवर सचिव MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd May, 1996

S.O. (576.—In xercise of the powers conferred by subsection (8) of Section 24 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints of S/Shri B. Hanuma Reddy and M. Sree Rama Murthy, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting case No. RC. 1(S)/96/SPE|CBI|SIT Madras (Shri Magunta Subba Rama Reddy murder case) and any other matter connected therewith or incidental thereto, investigated or instituted by he Delhi Special Police Establishment in the Session Court, Ongole, Prakasam District. Andhra Pradesh.

[No. 225/90/96-AVD, 1]]
S. SOUNDAR RAJAN, Under Secy.

निर्ता मंद्राहास

(राजस्य विसंग)

कनक्ता, 5 फरवरी, 1996

आयकर

कारपार 1577.—सर्वमायारण को एनक्ष्या सूचित किया जाना है कि निम्निविधित संगठन को, आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन बिहित प्राधिकारी हारा निस्तिरिधित मनौं पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन एन्मोदित किया गया है:——

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा विकास्त्रिका ।
- (ii) यह अपन वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विलरण अन्येक विक्ताद वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक मचिव, वैज्ञानिक य बौधोंगिक संवुर्णधान विसाम, ''प्रौद्योगिकी भवन'' न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येन एर्प के 31 अन्दूबर तक लेखापरीक्षित वाधिक लेखा की प्रति (क) आयकर
 महानिदेशक (छूट), (ख) सनिव वैज्ञानिक तथा
 औद्योगिक प्रनुर्धान विमाग और (ग) आयकर
 प्रायुक्त/आयकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राबिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर
 प्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई
 रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखापरीक्षित आय-स्थ्य हिमाय को भी प्रस्तुत करेगा।

ंसंगठन का नाम : साह, इण्डास्ट्रीयल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सा, 15/171, गौतम बुद्ध राजवय, मरणार्थ, वाराणसी-221007

यह ग्रिधसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की भ्रवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त गर्त (1) "संध" जैसा संवर्ग के लिए लागु नहीं होगा।
 - 12. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देणक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में संगठन पड़ता है तो माध्यम में आयकर महानिर्देणक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आयदेवन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आदेदन-पत्त की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं० 1516/एफ सं०म०नि०/ग्रा०क० (छूट)/यू०पी०-2/ 35(1)(ii)/39] ग्रार० सिंह, उप निर्देशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Calcutta, the 5th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1577.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return or its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sah Industrial Research Institute
Sa, 15/171, Gautam Buddha Rajpath,
Sarnath, Varanasi-221007.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96

- Notes.—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial-Research.

[No. 1516]F. No. DG.IT(E)/UP-2/35(1)(ii)[39-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 5 फरवरी, 1996

श्रायकर

का०प्रा० 1578. — सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन कों, आयकरं ब्रिध-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के ब्रिधीन बिहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गतीं पर "संस्थान" के संवर्ग के ब्रिधीन श्रमुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन भ्रत्मंधान कार्यों के लिए भ्रलग लेखा बहियां रखेगा । और

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यो का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक मचिव, वैज्ञानिक व जीद्योगिक अनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन'' न्यू मेह्गीकी रोड, नई दिन्त्री-110016 को भेजेगा.
- (iii) यह प्रत्येक वर्ग के 31 धवट्वर तक लेखागरीक्षिन वर्गिक लेखा की प्रति (क) प्रायकर
 महानिर्वेणक (छ्ट). (ख) मिनव बैजानिक तथा
 औद्योगिक अनुसंबान विभाग और (ग) आपकर
 आयुक्त/आयकर महानिर्वेणक(छूट) जिनके क्षेत्रीधिकार
 में उक्त संगटन पड़ता है और ध्रायकर अधिनियम,
 1961 की धारा 35(1) में वी गई रिमर्च किया
 गया संबंधिन छूट के बारे में लेखा-परीक्षित
 आयव्यय हिसाब को भी प्रस्तुन करेगा।

संगठन का नाम

गोधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टाडीज, पोस्ट ऑक्स नं० 1116, राजधाट, वाराणसी-221007 (यू०पी०)

यह श्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 में 31-3-96 तक की श्रवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त गर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।
 - 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमांबन की श्रवधि बढ़ाने के लिए श्रायकर आयुक्त/श्रायकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेता-धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम सं श्रायकर महानिर्देशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में श्रायेदन करें, श्रनुसीदन की श्रवधि बढ़ाने के संबंध में किए श्रावेदन-पद की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं० 1517/एफ०सं०म०नि०/म्रा०क० (छृट)/यू०पी०-3/ 35(1)(iii)]

यार० सिह, उप निदेशक

Calcutta, the 5th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1578.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Annual Return or its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Gandhian Institute of Studies, Post Box No. 1116, Raighat, Varanasi-221001 U.P.



This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes.—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1517|F. No. DG-IT(E)/UP-3/35(1)(iii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 5 फरवरी, 1996

ग्रायकर

का०भ्रा० 1579.—सर्वमाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, ग्रायकर प्रधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गर्ती पर "संघ" के संवर्ग के श्रधीन श्रन्मोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (ii) यह त्रपने बैजानिक धनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सनिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक धनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन'' त्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 श्रक्ट्बर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिर्देशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक भनुसंधान विभाग और (ग) श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-विकार में उक्त संगठन पड़ता है और श्रायकर श्रिधिनयम, 1961 की धारा 35(1) में वी गई

रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-गरीक्षित ग्राय-व्यय हिसाब को भी ग्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : वि मीनिगं, ज्योलोंजीकल एण्ड मेटार्लजीकल इस्टीटयूट ऑफ इंडिया 29, चौरांगी रोड, कलकत्ता-700016 ।

यह ग्रिधिसूचना दिनांकः 1-4-95 से 31-3-98 तक की भ्रविध के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त मर्त (1) "संघ" जमा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 - 2. मंगठन को मुझाब दिया अना है कि वे अनुमोदन की प्रविध बढ़ाने के लिए आयजर आयुक्त/आयकर निर्वेणक (छूट) जिनके क्षेत्रा- धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिर्वेणक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की प्रविध बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पब की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं० 1518/एफ सं०म०नि०/आ०क० (छूट)/डब्स्थू. बी-49/ 35(1)(ii)/92]

श्रार० सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 5th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1579.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
- (ii) It will furnish the Annual Return or its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Mining, Geological and Metallurgical Institute of India, 29, Chowringhee Road, Calcutta-700016.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-98

Notes.—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax. Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1518]F. No. DG-IT(E) WB-49/35(1)(ii)[92-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 5 फरवरी, 1996

श्राधक∀

कारुप्रार 1580.—सर्वेसाधारण को एनद्द्वारा सूचिन किया जाना है कि निम्निनिखिन संगठन को, प्रायकर प्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपयारा (1) के खुण्ड (ii) के लिए ग्रायकर नियम के नियम 6 के प्रधीन विहिन प्राधिकारी हारा निम्निनिखित शर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के प्रधीन ग्राविकारी हारा निम्निनिखित शर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के प्रधीन ग्राविकारी हारा किया किया गया है:—

- (i) संगठन श्रन्मधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंघान संबंधी कार्यों का एक व्यापिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक अ आंग्रोगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 कर्इ तक लेखा-परीक्षित वाधिक लेखा की प्रित (क) ग्रायकर महानिर्देशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथ जौखोगिक ग्रनुसंधान विभाग और (ग) ग्रायकर आयुक्त/ आयकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में नेखा-परीक्षित ग्राय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : विकलांग केन्द्रा रूराल रिसर्च सोसाथटी, 13, लुकर गंज, इलाहाबाद-211001 (यू०पी०)

यह प्रधिभूचना दिनांक 1-4-95 में 31-3-96 तक की भवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त भर्त (1) "संघ" जैसा संघर्ग के लिए: लागू नहीं होगा ।
 - 2. संगठन को सुझाय दिया जाता है कि वे प्रमु-मोदन की श्रवधि बढ़ाने के लिए ब्रायकर श्रायुक्त/ब्रायकर निर्देशक (छट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में संगठन पड़त' है के माध्यम गें

श्रायकर महानिर्देशक (छुट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में भावदन करें, ग्रेन्मोदन की श्रवधि बढाने के संबंध में किए श्रावेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं० 1519/एक०भ्रं०म०नि०/ग्रा०क० (छुट)/यू०पी०-1/ 35(1)(ii)/89]

ग्रार्० सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 5th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1580.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :---
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan', New Mehruali Road, New Dolhi-110016 for Research, every financial year by 31st May of each year;
 - It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions). (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION Viklang Kendra Rural Research Society, 13, Lukergani, Allahabad, U.P.-211001

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
- The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions). Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application

for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1519]F. No. DG-IT(E)[UP-1]35(1)(ii)[89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ताः, 5 फरवरी, 1996

आयकर

का०आ०1581.---सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचिन किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधि-निर्धिम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्रधिकारी द्वारा निम्नलिखित गतौ पर ''महाविद्यालय'' के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:---

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के निए अनग बहियां रखेगा .
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वाधिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रध्येक वर्ष के 31 मई तक सम्बद, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन'' न्यु मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भ जेगा. और
- (iji) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टबर तक लेखा-परीक्षीत वाषिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक सथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आर्यकर महानिदेशक (छुट) जिनके क्षेत्र।-धिकार में उक्त संगठन पडता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छट के बारे मे लेखा-परीक्षीत आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: भारतीय वैज्याक सनन्याय अलि इंडियां आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, श्री आयुर्वेद भहाविद्यालय, हन्मान नगर, नागपर--440009

यह अधिसूचना धिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त गर्न (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नही होगा।
 - 2. संगठन को सुमाव दिया जाता है कि वे अन्मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिर्देशक (छट,) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अविधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पन्न की विभाग को प्रस्तूत करना है।

(মৃত 1520/एफ सं०म०नि०/आ०क० (छुट) /एम० 48/ 35(1)(ii)/89] आर० सिंह, डप निदेशक

INCOME TAX

S.O. 1581.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "College" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawau', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Bhartiya Vaidyak Samanyaya Samuti's All India Ayurved Institute, Shri Ayurved Mahavidyalaya, Hanuman Nagar, Nagpur-440009,

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-98

Notes.—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

> (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calculta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1520|F. No. DG-IT(E)/M-48/35(1)(ii)]89-II(E)] R. SINGH, Dy. Director

कलकता, 5 फरवरी, 1996

आयकर

का० आ० 1582. --- सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विद्वित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गर्नो पर "संस्थान" के संबर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया हैं:~--

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा **ब**हियां रखेगा ।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान रांबंधी कार्यों का एक बाधिक विचरण प्रत्येक विक्तीय वर्ष के लिए ्र प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सविब, वैशानिक व अंग्रोनिक अनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन''

न्य मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा. और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर नक लेखा-परीक्षीत वार्षिक क्षेत्रा की प्रति(क) आयकर महानिदेशक (छुट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक अथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आर्येकर् महानिदेशक (छट) जिनके क्षेत्र।धिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आधकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छट के बारे में लेखा-परीक्षीत आय-च्यय हिंसाध को भी प्रस्तृत करेगा।

संगठन का नाम

एसोसिर्वणन फोर की बेलफेबर आफ परसन विथ ए मेंटल हैण्डीकेप महाराष्ट्र, टर्नर मोरिशन हौस (बेंसमेंट). 16, बेंक स्ट्रीट, मुम्बई-400023.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-97 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

दिप्पणी: 1. उपर्युक्त गर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागु नहीं होगा ।

> 2. संगठन को मुझाय दिया जाता है कि वे अन्-मोदन की अवधि बंदाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छुट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छुट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेषन करें, अनुभोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

सिं० 1521/एफ०सं०म०नि०/आ०क० (छूट)/एम० 38/ 35(1)(ii)/89] आर० सिंह, उप निवेशक

Calcutta, the 5th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1582.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tux Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return or its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-140016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax

(Exemptions), having jurisdiction over the organization, by the 31st October each war, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act. 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Association for the Welfare of Person with a Mental Handicap in Maharashtra, Turner Marrison House (Basement), 16, Bank Street, Bombay-400023.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-97.

- Notes.—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-fax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[F. No. 1521|F. No. DG-IT(E)/M-38/35(1)(iii)|89-IT(E)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 5 फरवरी, 1996

आयकर

का० आ० 1583.—सर्वेमाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्निलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्निलिखिन मनौ पर ''संस्थान'' के संवर्ग के अधीन अनुभोदित किया गया है:——

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक बापिक विवरण प्रत्येक विलीय वर्ष लेए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, नेक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिक न'' न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेणक (छुट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेणक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-स्थ्य हिमान को भी प्रम्तुन करेगा।

राष्ट्रना का सम

नेशनल एकाडीमी ऑफ साईन्स, 5, लाजपत राय रोड, न्यू कटरा, इलाहाबाद-211002

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 में 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संध" जैसा संवर्ग के लिए लागु नहीं होगा।
 - 2. संगठन को मुझान दिया जाता है कि ने अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्त को विभाग की प्रस्तुत करना है।

[सं० 1522/एफ सं०म०नि०/आ०क० (छूट)/यू०पी०-17 35(1)(ii)/90] आर० सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 5th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1583.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Ircome Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
- (ii) It will furnish the Annual Return or its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-J10016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act. 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

National Academy of Science, 5, Lajpat Rai Road, New Katra, Allahabad-211002.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes.—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Com-

missioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary. Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1522|F. No. DG-IT(E) (UP-17/35(1)(ii) |90-IT(E)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 6 फरवरी, 1996

आयकर

कां०आ०.1584. ---- मर्बसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित मती पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोधित किया गया है:----

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मंद्र तक सचिव, वैज्ञानिक व ओद्योगिक अनुसंधान विभाग, ''प्रौच्योगिकी भवन'' त्यू मेहरीकुर, रोड़, कुई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महासिदेशक (छूट), (ख) सिवव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंघान विभाग, और (म) आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गुजरमल तोदी सार्द्धम फाउण्डेबान, मी/ओ. मोदी खेंड लिमिटेड, सोदी नगर-201201. डिल्ट-गाजियाबाद

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की अर्वाब के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त मर्त (1) "संघ" जैसा संधर्ग के लिए लागु नहीं होगा ।
 - 2. संगठन को सुझाव विया जाता है कि वे अर्नु-भीदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-श्विकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को

तीत प्रतियों में आबेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्न की बिभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं० 1523/एफ०सं०म०नि०/आ०क० (छूट)/यू०पी०-13/ 35(1)(ii)90]

आर० सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 6th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1584.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Annual Return or its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Guiar Mal Modi Science Foundation, C/o. Modi Thread Limited, Modinagar-201201, Dist. Ghaziabad.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes.—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1523|F. No. DG-IT(E)/UP-13/35(1)(ii)|90-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 6 फरवरी, 1996

आयकर

कारुआर . 1585. — सर्वसाधारण को एतद्दारा सुचित किया जाता है कि निम्निसिखित संगठन को, आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिक(री हारा निम्नजिखित शर्नो पर ''विक्यविद्यालन'' के संवर्ग के अधीन अनुभोदित किया गया है :--

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखः बहियां रखेगा ;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यी का एक वापिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक स्वित, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंबान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन'', न्यु मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखापरीक्षित वाधिक लेखा की प्रति (क) आयकर
 महानिदेशक (ष्टूट), (ख) सचिव कैंग्रानिक तथा
 औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर
 आयक्त/आयकर महानिदेशक (ष्टूट) जिनके केंद्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर
 अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई
 रिसर्च किया गया संबंधित ष्टूट के बारे में लेखापरीक्षित आय-व्यय हिमान को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नरेन्द्र देथ यूनीवर्मिटी आफ एग्रीकलचर एण्ड टेक्नोलॉर्जा पी० ओ० कुमारगंज फैजाबांद-224229

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-94 से 31-3-96 तक की अर्बाध के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैमा मंबर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 - 2. संगठन को सुझाब दिया जाता है कि वे अनुभोदन की अब्धि बढ़ाने के लिए आयकर अध्युक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रनियों में आवेदन करें, अनुभोदन की अब्धि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[मं० 1524|nৃफ मं०म०नि०|आ०क०(छूट)|यू०पी०-7| 35(1)(ii)|89]

आर्० सिह, उप निदेशक

Calcutta, the 6th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1585.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of

Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Narendra Deva University of Agriculture and Technology, P.O. Kumarganj, Faizabad-224229.

This Notification is effective for the period from 1-4-94 to 31-3-96.

- Notes—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1524]F. No. DG-IT(E)/UP-7/35(1)(ii)[89-IT(E)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 6 फरवरी, 1996

आयकर

का०आ०. 1586. — मर्थसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखिन णार्ती पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोधित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वापिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक संचिव,, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन'', त्यू मेहरौली रोड, नई विल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अब्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) मचित्र वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961

की धारा 35(1) में वी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-य्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नोर्दर्न इंडिया टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिशएन, सेक्टर 23, राजनगर गाजियाबाद-201002 (यु०पी०)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 में 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त मर्त (1) "मंत्र" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।
 - 2. संगठन को मुझाय दिया जाता है कि वे अनु-मोदन की अविध बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में गंगठन पड़ता है के माध्यम में आयकर महानियेणक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेषन करें, अनुभोदन की अविध बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुन करना है।

[सं॰ 1525/एफ॰सं॰म॰नि॰/आ॰क॰ (छूट)/यृ॰पी॰-10/ 35(1)(ii)90, आ॰क॰(छूट)]

आर० सिह, उप निदेशक

Calcutta, the 6th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1586.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Northern India Textile Research Association, Sector 23, Raj Nagar, Ghaziabad-201002, U.P.

This Notification is effective for the period from 1-4 95 to 31-3-96.

Notes—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1525/F. No. DG-Tr(E)/UP-10/35(1)(ii).90[IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 9 फरवरी, 1996

श्रायकर

का श्रा 1587.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रिटीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर संस्थान" के सबर्ग के श्रिधीन श्रन्मोवित किया गया है :---

- (1) संगठन श्रन्संधान कार्यो के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा ;
- (2) यह श्रपने वैज्ञानिक अनुसंधाना संबंधी कार्यो का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व अधिशोधिक श्रनुसंधान विभाग, ''प्रोद्योगिकी भवन'' न्यू मेहर्नानी रोड, नई विल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) मचिय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनु-मंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त, आयकर महा-निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार मे उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बहें में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

न्य् ट्रेणन सोसाईटी श्राफ इंडिया , ने निल इंग्टीटयूट श्राफ न्यट्रेणन.

पी. ओ. जमाई ओस्मानिया, हेदराबाद - 7 (ए. पी.)

यह स्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की स्रवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1 उपर्युक्त मर्त (1) "संध" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को गुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अविध बढ़ाने के लिए श्रायकर आयुक्त आयकर निर्देणक (छूट) जिल्के क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्या से श्रायकर महानिर्देणक (छूट), कत्लगत्ता को तीन

प्रतियों में भ्रावेदन करें, श्रनुमोदन की प्रविध बढ़ाने के संबंध में किए ग्रावेदन-पत्र की विभागकी प्रस्तुत करना है।

[सं. 1526/एफ.सं.म.नि.आ.क. (छूट)/ एपी-13/35(1)(ii)/90 आ०के (छुट)]

श्रार सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 9th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1587.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mchrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Nutrition Society of India, National Institute of Nutrition, P.O. Jamai Osmania, Hyderabad-7 (A.P.)

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1526/F. No. DG-IT(E)/AP-13/35(1)(ii)|90-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 9 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. थ्रा. 1588:— मर्वसाधारण को एतद्दारा मूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित

प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गर्तो पर ''संस्थान'' के संवर्ग के श्रधीन भ्रतुमोदित किया गया है :---

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यो के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा;
- (ii) यह प्रपने वैज्ञानिक ग्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सिजव, वैज्ञानिक व औद्योगिक ग्रनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी ग्रवन'' न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सनिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रनुसंधान विभाग और (ग) ग्रायकर श्रायकत / ग्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और श्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में की गई रिसर्च किया गया संबंधिन छूट के बारे में लेखा परीक्षित श्राय ब्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नन फिरॉस मटेरियल्स टेक्नोलाजी डेवलपमेन्ट सेन्टर (एन. एफ.टी.डी. सी..) पी. ओ. कंचनबाग, हैंदराबाद-500258

यह प्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की प्रविध के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :--- 1 उपर्युक्त शर्त (1) "संध " जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

> 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर श्रायुक्त/ आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकरता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, श्रनुमोदन की श्रवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तत करना है।

> > [सं. 1527 (एफ.सं.म.नि/घा.क./छूट/ ए.पी.~12/35(ii) 90 आ०क० (छुट)] ग्रार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 9th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1588.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annuel Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Non-Ferrous Materials Technology Development Centre (NFTDC), P.O. Kanchanbagh, Hyderabad-500258.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

Notes:—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1527]F. No. DG-IT(E)/AP-12/35(1)(ii)|90-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director

कलकन्ता 9 फरवरी, 1996

स्रायकर

का. आ. 1589--- सर्वेसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिध-नियम, 1961 की घारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन बिह्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर विश्वविद्यालय के संवर्ग के अधीन श्रनुमोवित किया गया है:---

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यो के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनु-संधान विभाग ''प्रोद्योगिकी भवन'' न्य मेहरौली रोड, नई विल्ली —110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) प्रायकर महानिवेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा आँखोगिक प्रनुसंधान विभाग और (ग) प्रायकर प्रायुक्त प्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और सायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का न।म

श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट श्राफ हायर लिनग प्राशांथीनिलीयाम 5151-34 श्रनन्तपुर डी. (ए. पी.)

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की श्रवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:-1 उपर्युक्त गर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को मुझाथ दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं . 1528/एफ.सं.म.नि.श्रा.क. (छूट)/ए पी-5/35/(1) (ii) 89] श्रार० सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 9th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1589.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Prasanthinilayam-515 134, Anantapur Dt. (A.P.).

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Fxemptions), having jurisdiction over te organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Stcretary. Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1528|F. No. DG-IT(E)|AP-5/35(1)(ii) /89/IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता 9 फरवरी, 1996

श्रायकर

- का. ग्रा. 1590----- पर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नालिखित संगठन की, ग्रायकर अधि-नियम 1961 की धारा 35 की उरवारा (1) के खण्ड (ii) के लिए ग्रायकर नियम के नियम 6 के भ्रवीन विहिन प्राधिकारी द्वारा निम्नालिखित भर्ती पर "संस्थान " के संवर्ष के भ्रधीन भ्रमभोदित किया गया है :---
- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यो के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह प्रपत्ने वैज्ञानिक प्रनुसंधान संबर्धा कार्यों का एक वाधिक विवरण प्रत्येक विसीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रनुसंधान विसाग, प्रोदयोगिकी भवन, त्यु मेहराली शेड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूवर तक लेखा परीक्षित द्यार्षिक लेखा की प्रतिः (क) ग्रायकर महानिदेशक (क्रूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रनुसंधान विभाग और (ग) भ्रायकर भ्रायुक्त भ्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठत पड़ता है और ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित भ्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम निजामय इंस्टीटयूट प्राप्त भेडिकल साईन्स पंजागुटा हैसराबाद 500482 ए पी इंडिया ।

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की भवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:--1 उपर्युक्त गर्त (1) ''संघ'' जैसा संवर्ग के लिए लागु नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव विया जाता है कि वे अनुमोदन की अविधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकरता को तीन प्रतियों में आवेदन करे, अनुमोदन की अविध बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्न की विभाग की अस्तृत करना है।

[सं. 1529 /एफ सं. म. नि. /ग्रा.क.(छूट) /ए. पी. -8/35 (1)(ii)/89]

अप्रार सिंह उप, निदेशक

Calcutta, the 9th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1590.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35

- of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 3ist May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions). (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Niazm's Institute of Medical Sciences Panjagutta, Hyderabad-500 482 A. P. India.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1529/F. No. DG-IT(E)/AP-8/35(1)(ii)]89-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Secy.

कलकत्ता, 13 फरवरी 1996

प्रायकर

- का. आ. 1591.-सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शतों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:---
- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यो के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सिषय, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनु-संधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई विस्ती ~110016 को भेजेगा और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 ग्रस्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक ग्रनुसंधान

विभाग, और (ग) श्रायकर आयुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : दी इंस्टीट्यूट ग्राफ पास रिसर्च एन्ड एक्सन (ग्राई. पी. ग्रार० ए०), 81, गगन बिहार, दिल्ली -110051

यह ग्रधिमूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की ग्रबधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:-1 उपर्युक्त शर्त (1) "संध" जैसा संवर्ग के लिए लागु नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाय दिया जाता है कि वे अनुमोदन की श्रविध बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/ श्रायकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम में आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में श्रावेदन करें, अनुमोदन की अविध बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1530 /एफ सं. म .नि/म्रा क० (छृट) /एन डी - 10/ 35 (1)(iii) /89]

ब्रार० सिंह, उप निर्देशक

Calcutta, the 13th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1591.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary. Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan' New Mehrauli Read, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Institute of Peace Research and Action (IPRA), 81, Gagan Vihar, Delhi-110 051.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax (Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1530/F. No. DG-IT(E)/ND-10/35(1)(iii)|89-IT(E)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 13 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. श्रा. 1592 ---सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिष्ठिन्यम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर "संस्थान" के संवर्ण के श्रधीन श्रनुमोदित किया गया है:---

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह स्रपने वैज्ञानिक स्रनुसंधान भंबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सिचय, वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 श्रक्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचित्र वैज्ञानिक तथा औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, और (ग) श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और श्रायकर श्रिधिनयम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित श्राय-च्यय हिसाय को भी प्रस्तुत करेगा।

नंगठन का नाम : ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीटयूट ग्राफ रिसर्च रिहबीलीटेणन फोर दी मेन्टाली हैन्डीकेच्ड विवेकानन्द नगर, दिलसुरवनगर, हैदराबाद — 500660.

यह अधिमूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:---1 उपर्युक्त गर्त (1) ''संध'' जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

> मंगठन को सुझाय दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अविध बढ़ाने के लिए आयकर

श्रीयुक्त/श्रायकर निधेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से श्रायकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में श्रावेदन करें, श्रनुगोदन की श्रवधि बढ़ाने के संबंध में किए श्रावेदन पह की बिगाग को प्रमुन करना है।

[संख्या 153] / एफ सं. म. नि / श्रा. क०(छूट)/ ए. पी.—14 / 35 (1) (ii) /91]

श्रार० सिह, उप निदेशक

Calcutta, the 13th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1592.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary. Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (in) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Thakur Hari Prasad Institute of Research and Rehabilitation for the Mentally Handicapped Vivekananda Nagar, Dilsukhnugar, Hyderabad-500 660.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Fremptions). Calcuttn through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Storetary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1531/F. No. DG-IT(E)/AP-14/35(1)(ii)]91-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director

कलकना, 13 फरवरी, 1996

ग्रायकर

का. था. 1593. — सर्वसाधारण को एतद्धारा मूचित किया जाता है कि निम्निसिखित संगठन को, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये श्रीयकर नियम के नियम 6 के श्रिधीन विहित

प्राधिकारी द्वार विभ्वतिष्ठित भत्ती पर "मंग्यान" के संदर्ग क अधीन अनुभोवित दिव्या गया है:—

- (1) संगठन ग्रनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह ग्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यो का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व आँधोणिक प्रनुसंधान विभाग, प्रांधोगिकी भवन, त्यू गेहरोली रोड, नई विल्ली-110016 को मेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 श्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महर्निदेशक (लूट), (ख) सचित्र, वैज्ञानिक तथा आँधोगिक अन्संधान विधाग, और (ग) शायकर प्रायुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेताधिकार में उक्त सगठन पड़ता है और आयकर श्रिनित्रन, 1961 हो धारा 35(1) में दी गर्छ रिसर्च किया गया संबंधित छूट के वारे में लेखा-परीक्षित श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

मंगठन का नाम

नेशनल फैसीलिटी फोर अनिमल टीस एण्ड सेल कलचर (एन.एफ.ए.टी.सी.सी.) 'जोपासना' नीयर वाउज इंजी एन.टी.डी. गौद रोड. कोयळड पुना-411029.

यह श्रधिसूचना दिनोकः 5-4-95 से 31-3-97 तक की ग्रवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. अपर्जुक्त शर्त (1) 'गंव' जैसा संवर्ग के लिए लागु नहीं होगा।

(2) संगठन को सुझाय दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अविधि बढ़ाने के लिये आयवार आयुक्त, आयानर निदेशक (छूट) जिनके केला- धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकता को तीन प्रतियों में आवेसन करें, अनुभोदन की अविधि अकृते के संगंध में किये आवेदन-पत्न को विभाग को प्रस्तृत करना है।

[पं. 1532/एफ.सं. म.नि./ग्रा.कः. (१८८)/ए०-पी० II/35(1)(ii)/90]

श्रार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 13th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1593.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the nurpoles of clause (i) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1951 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mchrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year."
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Fax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

National Facility for Animal Tissue & Cell Culture (NFATCC) "Jopasana" Near Vauaz Fings, Ltd., Paud Road, Kothrud, Pune-411 029.

This Notification is effective for the period from 5-4-95 to 31-3-97.

- Notes:(1): Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1532/F. No. DG-FT(E)/M-186/35(1)(ii)/96-FT(E)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकसा, 15 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. था. 1594.—सर्वसाधारण को एतद्शरा सृचित किया जाता है कि निमालि वित संगठन को, श्रायक प्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये ग्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहिन प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गर्ती पर "संव" के संवर्ग के भधीन श्रन्मोदित किया गया है :——

- (1) संगठन ध्रनुसंधान कार्यों के लिये ध्रलग लेखाबहियां रखेगा।
- (2) यह श्रपने वैज्ञानिक श्रन्सधान संबंधी कार्यों का एक बाधिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक श्रन्सधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अन्त्वर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिर्देशक (छूट), (ख) सचिन, वैज्ञापिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) श्रायकर श्रायुक्त श्रायकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेताधिकार में उक्त संगटन पड़ता है और श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गर्ड रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परिक्षित श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुन करेगा।

संगठन का नाम

सीसाइटी फोर हेन्य आर्ह्ड, रिसर्च एण्ड एडुकेशन इंडिया, (शेयर इंडिया) मीडिस केन्द्र, मरीवर कॉम्पलेक्स, मेक्टेटिएट रोड, हैंदराबाद-500004.

यह श्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संबर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाय दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अविध बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके केवा-धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम मे अवकर मठानिर्देशक (छूट), कानकता को तीन प्रतियों में पावेदन करें, अनुमोदन की अविध वटां के पबंच में किये आवेदन-पद्य को विभाग की प्रस्तुत करना है।

[सं. 1533/०क.सं. म.नि./श्रा.क.(छ्ट) एको-11/35(t)(ii)/90]

ग्रार, भित्र, उप निदेशक

Calcutta, the 15th February, 1996

INCOME-TAX

S.O. 1594.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of subsection (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific accounts for its research activities;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;

Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientiflo & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Society for Health Allied.

Research and Editeation India,
(Share India) Medi Citi Centre,
Sarovar Complex, Secretariat Road Hyderabad500004.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- NOTES: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1533]F. No. DG-IT(E)[AP- Π [35(1)(ii)]90-IT (E)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 15 फरवरी, 1996

ग्रायकर

का आ. 1595.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये आककर नियम के नियम 6 के श्रिधीन विहित प्राधिकारी हारा निम्नलिखित शर्ती पर "संघ" के संवर्ग के श्रिधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह श्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विकरण प्रत्येक विसीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सिषव, वैज्ञानिक व औद्योगिक धनुसंधान विभाग, ''प्रौधोगिकी भवन,'' "न्यू मेहरौली रोड़, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सिचव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग और (ग) श्रायकर श्रायुक्त/ग्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में वी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित ग्राय-श्र्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इंटरनेशनल एडवांसड रिसर्च सेन्द्र फोर पाउडर मेटालर्जी एण्ड न्यू मटिरियलस (ए. प्रार.सी. इंटरनेशनल) एग्र.र. सी. प्रोजक्ट धार.सी.आई. रोड, बालापुर विलेज, रंगा रेडी डिस्ट्रीक्ट, हैदराबाद-500005

यह भ्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की भ्रवधिः के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त मर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा। 1292 G1/9€—3. (2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निवेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा- धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिवेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये मानेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1534/एफ.सं. म.नि./म्रा.क. (छूट)/ए.पी.-18/35(1)(ii)/92]

श्रार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 15th February, 1996

INCOME-TAX

S.O. 1595.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of subsection (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (i) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax|Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARC International) ARC Project, RCI Road Balapur Village, Ranga Reddy District, Hyderabad-500 005.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

NOTES: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1534|F. No. DG|IT(E)|A.P.-18|35(1)(ii)|92-IT(E)]
R. SÎNGH, Dy. Director

कलकत्ता, 15 फरवरी, 1996

ग्रायकर

का.ग्रा.1596.—सर्वसाक्षारण को एतव्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्तिलियन संगठन को, श्रायकर ग्रिसिनयम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये ग्रायकर निथम के नियम 6 के ग्रिधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्तिलिखित शर्ती पर "संस्थान" के मंवर्ग के ग्रिधीन श्रनुमोदित किया गया है:——

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिये ग्रालग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन'', न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 की भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वापिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परिक्षित आय-क्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

संवाद फाउण्डेशन, 58/4ी, कृष्णा निवास, वास्केशवर रोड, बाम्बे-400006

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1-2-96 से 31-3-98 तक की ग्रविध के लिये प्रभावी है।

- ्टिप्पणी : 1. उपर्युक्त भर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागृ नहीं होगा।
 - 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अविध बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निवेशक (छूट) जिनके क्षेष्ठा-धिकार में संगठन पड़ता है के साध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अविध बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्न विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1535/एफ.सं. म.नि./थ्रा.क.(छूट)/ एम-187/35(1)(1ii)/96] थ्रार. सिंह, उप निदेशक Calculta, the 15th February, 1996

INCOME-TAX

- S.O. 1596.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of subsection (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientiflo & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Samvaad Foundation. 58/B, Krishna Niwas, Walkeshwar Road, Bombay-400 006.

This Notification is effective for the period from 1-2-96 to 31-3-98.

- NOTES: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1535|F. No. DG|IT(E)|M-187|35(1)(iii)|96-IT(E)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 16 फरवरी, 1996

श्रायकर

का आ 1597 — सर्वसाधारण को एतद्दारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड(ii) के लिये श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रिधीन विहित श्रिधिकारी द्वारा निम्नलिखित णतौ पर "संघ" के संवर्ग के श्रिधीन श्रिन श्रिमी की प्रायक किया गया है :—

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिये धलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के खिये प्रत्येक

वर्ष के 31 मई तक सिषव, वैज्ञानिक व श्रीद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन'' "न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, श्रीर

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अवसूयर तक लेखा-परीक्षीत, वापिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिदेणक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा श्रीद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, श्रार (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेणक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उतत संगठन पड़ता है श्रीर श्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-ध्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

फीजीकल रिसर्च लैंबोरेटोरी, नवारंगपुरा, ग्रहमदाबाद-380009

यह ग्रिथिसूचना दिनांक 1-4-94 से 31-3-95 तक की ग्रवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. छपर्युक्त गर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाय दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अविध बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिषेणक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अविध बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1536/एफ.सं. म.नि./ग्रा.क. (छूट)/ कल./जी.-27/35(1)(ii)]

श्रार. सिंह, छप निदेशक

Calcutta, the 16th February, 1996

INCOME-TAX

S.O. 1597.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of subsection (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the

organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Physical Research Laboratory, Navarangpura, Ahmedabad-380009.

This Notification is effective for the period from 1-4-94 to 31-3-85.

NOTES: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1536]F. No. DG[IT(E)|CAL[G-27]35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

नलनता, 19 फरवरी, 1996

श्रायकर

का.आ.1598.— सर्वसाधारण को एतद्हारा सूचित किया णाता है कि निम्नलिखित संगठन को, धायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड(iii) के लिये धायकर नियम के नियम 6 के भधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गती पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन धनुसंधान कार्यों के लिये ध्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह ग्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वाधिक विषरण प्रत्येक विसीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व ग्रौद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन, त्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, श्रौर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 श्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सिचव वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, ग्रौर (ग) श्रायकर श्रायुक्त/ग्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है ग्रौर श्रायकर श्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई। रिसर्च श्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षीत श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गांधी लेबर इंस्टीट्यूट, बसतेज रोड, अहमवानाद+380052-

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की श्रवधि के लिये प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संध" जैसा संबर्ग के लिये लागू नहीं होगा।
 - 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे धनुमोदन की प्रविध बढ़ाने के लिये प्रायकर आयुक्त/धायकर निवेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्रायकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में खाबेदन करें, अनुमोदन की खबध बढ़ाने के संबंध में किये ग्राबेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

·[सं. 1537/एफ∵सं. म∵नि./ग्रा.कः.(छूट)/ कल./फीं–5/35(1)(iji)] श्रार.ःसिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 19th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1598.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan', New Mchrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year, and
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industiral Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Gandhi Labour Institute, Thaltej Road, Ahmedabad-380052.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calculta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1537|F. No. DG|IT(E)|CAL|G-5|35(1)(iii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 19फरवरी, 1996

श्रायकर

- (i) संगठन ग्रनुसंधान कार्यों के लिये भ्रलग लेखा बहियां रखेगा,
- (ii) यह ग्रदने वैज्ञानिक ग्रनुसंधान संबंधी कायों का एक वार्षिक विचरण प्रत्येक विज्ञीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक ग्रनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, उई दिल्ली-16 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, और (ग) श्रायकर श्रायुक्त/ग्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ना है और श्रायक श्रायक यम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्ग किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षीत श्रायकथ्य हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

न्नाल इंडिंग हार्ट फाउड़ेशन, 4874 (फास्ट पंत्रीर), श्रन्सोरी रोड, 24,दरियागंज, नई विल्की-110002

यह अधिसूचना दितांक 1-4-95 में 31-3-98 तक की प्रविध के लिने प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्यकः गर्त(1) ''संघ'' जैस सर्वा के लिये सागू नहीं होगा
 - संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे आ मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आसकर आयुक्त/आयकर निदेश (छट) जिनके क्षेत्राधिकार में

मंगठन पड़ना है के माध्यम से श्रायकर महानिदेशक (कृट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में श्रावेदन करें, श्रनुमोदन की श्रवधि बढ़ाने के संबंध में किये श्रावेदन-पक्ष की 6 प्रतियां विभाग को प्रस्तत कना है।

[सं. 1538/एफ.सं. म.नि./श्रा.क.(छुट)/ कल./एन.डी.-39/35(1)(ii)]

ग्रार.सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 19th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1599.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mchrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year:
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION: :

All India Heart Foundation, 4874 (First floor) Ansari Road, 24, Daryaganj, New Delhi-110002.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-98.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval

should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1538|F. No. DG|IT(E)|CAL|ND-9|35(1)(ii)] R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

श्रायक'र

का. आ. 1600-- मर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है किम्सलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्सलिखित भर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के श्रधीन अनुमोदित किया गया है:--

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वाधिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सिये प्रत्येक वर्ष के 31 मर्ड तक मचिव, बैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रीद्योगिकी भवन, "न्यू मेहरौँली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 ग्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षीत वापिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग और (ग) श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गर्ड-रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षीत श्राय-व्यय हिमाब को भी प्रस्कृत करेगा।

संगठन का नाम

सैन्टर फोर बाटर रिसोरसेस डेबलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट, कुन्न(मनगलम, कोजीकोड, केरल-673571

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-91 सक की ग्रविध के लिये प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त णर्स (1) "संध" जैसा संधर्ग के लिये लागू नहीं होगा ।
 - 2. संगठन को सुझाथ दिया जाता है कि वे भ्रनुमोदन की ग्रवधि बढ़ाने के लिये ग्रायकर भायुक्त/ श्रायकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से श्रायकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों मे ग्रावेदन करें, ग्रनुमोदन की ग्रवधि बढ़ाने के संबंध में किये ग्रावेदन-पत्न की जिन्मी की प्रतियों विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1539/एफ.सं. म.नि./श्रा.क(छट)/ कल./के-2/35(1)(ii)] ग्रार. सिंह, उप निदेशक

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

INCOME TAX

S.O. 1600.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Rescarch, 'Technology Bhawan', New Mchrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Centre for Water Resources Development & Management, Kunnamangalam, Kozhikode, Kerala-673571.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-91.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary. Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1539]F. No. DG]IT(E)[CAL|K-2|35(i) (ii)] R. SINGH, Dy. Director

प्रायकर

का. आ. 1601.— मर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये भ्रष्तग लेखा बहियां रखेगा,
- (2) यह ध्रपने वैज्ञानिक भ्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक वित्ररण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक ध औद्योगिक भ्रनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन "न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखापरीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) ध्रायकर
 महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा
 औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) ध्रायकर
 प्रायुक्त/श्रायकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और श्रायकर
 प्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी
 गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के
 बारे में लेखा-परीक्षीत श्राय-व्यय हिसाब को
 भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: सेन्टर फॉर बाटर रिसोरसेस अवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट, कुन्नामनगलम, कोजीकोड, केरल-673571

यह श्रिधसूचना दिनांक 1-4-91 से 31-3-94 सक की ग्रविध के लिये प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त गर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।
 - 2. संगठन को सुझाव विया जाता है कि वे अनुमोदन की सुझाव बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को भीन प्रतियों में आवेदन करें, प्रनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां विभाग की प्रस्तुत करना है।

[सं. 1540/एफ सं. म.नि./ग्रा.क. (छूट)/कल/के-2/35(1)(ii)] ग्रार. सिंह, उन निर्देणक

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

INCOME TAX

S.O. 1601.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Centre for Water Resources Development & Management, Kunnamangalam, Kozhikode, Kerala-673571.

This Notification is effective for the period from 1-4-94 to 31-3-96.

Notes: (1) Condition (1) above will not apply to 1-4-91 to 31-3-94.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1540]F. No. DG]IT(E) |CAL](K-2) [35(1) (ii)]
R. SINGH, Dy. Director

आय-कर

का. आ. 1602.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा मितित किया जाता है कि निम्नालिपित गंगठन को, प्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (II) के लिये श्रायकर नियम के नियम 6 के स्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर "स्थान" के संवर्ग के श्रधीन श्रनुमोदित किया गया है :--

- (i) संगठन अनुसंधात कार्यों के लियें ग्रालग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व अधियोगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, श्रीर.
- (iii) यह प्रयेत्क वर्ष के 31 श्रम्त्वर तक लेखा-परिक्षीत बांपिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिर्देशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक श्रनुसंधान विभाग श्रौर (ग) श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्रा कार में उक्त संगठन पड़ता है श्रौर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तत करेगा।

संगठन का नाम : सेन्टर फॉर वाटर रिसोरसेस डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट, कुन्नामनगनम, कोजीकोड, केरल-673 571

यह प्रधिसूचना दिनांक 1-4-94 से 31-3-96 तक की प्रविध के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/ध्रायकर निर्देणक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेणक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, ध्रनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तृत करना है।

[सं. 1541/एफ सं.म.नि./ग्रा.क. (छूट)/कल/के-2(35)(1)(ii) श्रार. सिष्ट, उप निवेशक

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

INCOME TAX

S.O. 1602.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industiral Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Centre for Water Resources Development & Management, Kunnamangalam, Kozhikode, Kerala-673571.

This Notification is effective for the period from 1-4-94 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1541|F. No. DG|IT(E)|CAL|(K-2)|35(1)(ii)] R. SINGH, Dy. Director

श्रायकर

का. ग्रा. 1603:—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाना है कि निम्नलिखित संगठन को, ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (II) के लिये ग्रायकर नियम के नियम 6 के ग्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के ग्रधीन श्रनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन भ्रनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंघान संबंधी काथों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंघान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) प्रायकर महा-निदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग और (ग) श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर, महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़्सा है और श्रायकर ग्रंधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षीत ग्राय-व्यय हिसाब की भी प्रस्तुन करेगा।

संगठन का नाम: नेशनल इंस्टीट्यूट श्रौफ डिजाइन, पलवी, श्रहमदाबाद-380007

यह श्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 नक की श्रविध के लिये प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1 उपर्युक्त गर्ता (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये । लागू नहीं होगा।
 - (2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे ग्रायुक्त को अवधि बढ़ाने के लिये ग्रायकर श्रायुक्त श्रायकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से ग्रायकर महानिदेशक (छूट), कचकता को तीन प्रतियों में श्रावेदन करें, ग्रानुमोदन की ग्रायधि बढ़ाने के संबंध में किये ग्रावेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1542/एफ.सं. म.नि./श्रा.क.(छूट)/कल/जी-23/35(1)(ii) ग्रार. सिंह, उप निदेशक Calcutta, the 19th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1603.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industiral Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

National Institute of Design, Paldi. Ahmedabad-380007.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1542|F. No. DG|IT(E)|CAL|G-23|35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकसा, 19 फरवरी, 1996

श्रीयकर्

का. आ. 1604:— सर्वसाधारण को एतद्वारा स्चित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को प्रायकर प्रधिनियम" 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी हारा निम्नलिखित शर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन श्रनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिये श्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अन्तूबर तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ध्रायकर
 महानिवेशक (छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक
 तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग)
 श्रायकर ध्रायुक्त/ध्रायकर महानिवेशक (छूट)
 जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है
 और ध्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा
 35(1) में वी गई रिसर्च किया गया संबंधित
 छूट के बारे में लेखा-परिक्षित ग्राय-व्यय हिसाब
 को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: डा. विकराम ए. सराबाई ए. एम. ए. मेमोरियल ट्रस्ट, बैंक घाँफ इंडिया बिल्डिंग, III-फ्लोर, भद्रा, ग्रहमदाबाद-380001

यह अधिसूचना दिनांक 1~4~95 से 31~3~96 तक की अवधि के लिए प्रभाषी है।

- रिप्पणी: (1) छपर्युक्त णर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।
 - (2) संगठन को सुझाय दिया जाता है कि वे अनुमोदन की श्रविध बढ़ाने के लिये श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से श्रायकरमहानिर्देशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में भावेदन करें, श्रनुमोदन की श्रविध बढ़ाने के संबंध में किये श्रावेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. ! 543/एफ . सं . म.नि./भ्रा.क. (छूट)/कल/जी-12/35(1)(ii) आर. सिंह, उप निदेशक

INCOME TAX

S.O. 1604.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delbi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions) (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax (Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Dr. Vikram A. Sarabhai AMA Memorial Trust, Bank of India Building, IIIrd Floor, Bhadra, Ahmedabad-380001.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1543|F. No. DG-IT(E) |Cal(G-12)|35(1) (iii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

आयकर

दा.शा. 1605 सर्वमाधारण को एतदहारा स्चित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आगकर श्रिधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के लण्ड (ii) के लिए आययर नियम के नियम 6 के श्रिधीन बिह्न प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित णतीं पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन असोन असोदित किया गया है:——

- (i) मंगठन अनुमंधान कार्यों के लिए झलग लेखा बहियां रखेगा
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक नार्षिक विषयण अन्येक वित्तीय वर्ष के लिल् प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक मचिब, बैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन, "न्य मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 श्रव्यूवर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग और (ग) श्रायकर ग्रायुक्त/शायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में उनत संगठन पड़ता है और श्रायकर श्रिधितयम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित ग्राय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : जैं यम दास पडेल साइन्डीफिक रियर्च फाउण्डेशन, 705, एरोज अपार्टमेटस, 56 नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019

यह श्रधिसूचना दिनांक 1-ा-94 में 31-3 96 तक की श्रवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी : 1. उपर्यका णर्त (1) ''संघ'' जैसा संवर्ग के लिये नाम नहीं होगा।
 - 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे यनुमीदन की अवधि बढ़ाने के लिए यायकर आयुवत/श्रायकर नितेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के मान्यम से प्रायकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, श्रनुभोदन की श्रवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पज की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं.1544/एक सं. म.नि./प्रा.क.(छूट)/कल/एन.डी.17/35(1)(ii)] श्रार. सिंह उप निदेशक

INCOME TAX

S.O. 1605.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the estegory "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions) (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax (Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Jayramdas Patel Scientific Research Foundation, 705, Eros Apartments, 56, Nehru Place, New Delhi-110019.

This Notification is effective for the period from 1-4-94 to 31-3-96.

- Notes: (1) Cendition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1544]F. No. DG-IT(E) |Cal(ND-17)|35(1)

(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

यायकर

का. शा. 1606 . — न्यर्थसाधारण को एतद्दार। सूचित किया जाता है कि निम्नालिखत संगठन को प्रायकर श्रीधिनयम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये अधिकर नियम के निराम 6 के भ्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निश्नलिखित शतीं पर "संघ" के संवर्ग के श्रिधीन श्रनुमोदित किया गया है —

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये प्रलग लेखा वहियां रखेगा।
- (ii) यह श्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व आंद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भक्त "त्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 श्रक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग और (ग) ग्रायकर ग्रायुक्त/ श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और श्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: इंस्टीट्यूट श्रांफ कीडनी डेजीसेस एण्ड रिसर्च संन्टर, बी.जे. मेडिकल कॉलेज एण्ड सिविस हॉस्पीटल कैम्पस, श्रहमदाबाद-380016

यह ग्रिधसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्यक्त शर्त (1) 'संघ'' जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 - 2. सगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे या प्रामुगीयन की भ्रविध बढ़ाने के लिये ग्रायकर आयुक्त/श्रायकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से ग्रायकर महानिवेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में ग्रावेदन करें, ग्रानुमोदन की ग्रविध बढ़ाने के सबंध में किए ग्रावेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1545/एफ.सं. म.नि./ग्रा.क./(छूट)/ कल/जी-1/35(1)(ii)]

ग्रार. सिंह, उप निदेशक

INCOME TAX

- S.O. 1606.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions) (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax|Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Institute of Kidney Diseases & Research Centre, B. J. Medical College & Civil Hospital Campus, Ahmedabad-380016.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1545]F. No. DG-IT(E) |Cal(G-1)|35(1)(ii)] R. SINGH, Dy. Director कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

ग्रायकर

का. था. 1607.---सर्वंसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विह्त प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गतीं पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिथे श्रलग लेखा बहियां रखेगा !
- (ii) यह श्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग ''प्रौद्योगिकी भयन'', न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 श्रंबतूबर तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर
 महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा
 औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, और (ग) श्रायकर
 ग्रायुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और श्रायकर
 श्रिधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी
 गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के
 बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-ध्यय हिसाब को
 भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: गनेश साइंटीफिक रिसर्च फाउण्डेशन, 64-65, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015

यह ग्रधिसूचना विनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की श्रविध के लिये प्रभावी है।

- टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा मंवर्ग के लिये लागृ नहीं होगा।
 - 2. संगठन को सुझाय विया जाता है कि बें अनुमोदन की अविध बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निवेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की भवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1546/एफ.सं. म.नि./धा.क.(छूट)/ कल०/एन.डी. 13/35(1)(ii)]

ग्रार. सिंह, उप निवेशक

INCOME TAX

S.O. 1607.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road. New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Ganesh Scientific Research Foundation, 64-65, Najafgarh Road, New Delhi-110015.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1546]F. No. DG-LT(E) |Cal(ND-13)|35(1) (1i)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. आ. 160 8.— सर्वसाधारण को एतद्द्वारा स्थित किया किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, धायकर श्रिधिनयम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी हारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के श्रधीन श्रनुमोदित किया गया है:

- (1) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिये श्रलग लेखा बहिया रखेगा।
- (2) यह श्रपने वैज्ञानिक श्रन्संधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव। वैज्ञानिक व औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग प्रौद्योगिकी भवन "न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्षके 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक भ्रन्संधान विभाग और (ग) भ्रायकर भ्रायक्त/ श्रायकर महानिर्देशक (छुट) जिनके क्षेत्राधिकार पड़ता है और भ्रायकर श्रधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बार में लेखा-परीक्षित श्राय-ठ्यय हिसाब को भी प्रस्त्त करेगा।

संगठन का नाम

श्रमूल रिसर्च एण्ड डेवलवमेंट एसोसिएशन, श्रमूल डेरी, श्रानन्द-388 001, गुजरात ।

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-396 तक की ग्रवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संध" जैसा संबर्ग के लिये लागु नहीं होगा।

> 2. संगठन को सुझाय विया जाता है श्रनमोदन की प्रवधि बढ़ाने के लिये मायकर भायक्त/भायकर निर्देशक (छुट) क्षेत्राधिकार में संगठन पड़सा है के माध्यम से ब्रायकर महानिर्देशक (छुट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में श्रावेदन करें; ग्रनमोदन संबंध स्रवधि बढाने के श्रावेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1547(एफ.सं. म.नि./धा.क.(छूट)/कल./ श्री. 36/35(1)(ii)] धार. सिंह, उप मिदेशक

INCOME TAX

- S.O. 1608.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax (Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Amul Research & Development Association, Amul Dairy, Anand-388001, Gujarat.

This Notification is effective for the period from 1-1-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1547]F. No. DG-IT(E)|Cal(G-36)|35(1) (ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

क्ष (सकार)

- का. ता. 1609 .— मदनाया न की एतत्वाण मृजित किया, जाता है कि तिस्तिलिखित संगठत की, ब्रायकर अजितियम, 1961 की खारा 35 की जन्मारा (1) के खंड (ii) के लिए ब्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधि-कारी द्वारा निस्तिलिखित शर्ती पर "संघ" के संवर्ग के अधीन ब्रमु-मोदित किया गया है:—
- (i) संगठत प्रनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अने वैक्षानिक अनुनंबान मंबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विद्धारित वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, थंजानिक व श्रांद्योगिक अनुसंधान विमाग, "प्रोद्योगिकी भवन", न्यू महरीला रोड, नई दिल्ला-- 110016 को भेजेगा, श्रीर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अवत्वर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट). (ख) सिचय वैशानिक गया घोडोंगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर प्रायुक्त/आयकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उकत संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई पूरिसर्च कियाकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षीत आय-व्यय हिमाब की भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सरदार पटेल रीन्यू एबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुतभा विध्यानगर-388120

यह प्रधिपूचना दिनाक 1-4-95 में 31-3-96 तक की अयिथि के लिए प्रभावी है।

- रिषणों : 1. उपर्युवन शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 - 2. संगठन की मुझाब दिया जाता है कि वे अनुमांबन की अविध बढ़ारी के लिए आयकर आयुक्त/आराभार निदेगक (छ्ट) जिन्हीं क्षेत्रा- धिकार में संगठन पहुता है के माध्यम से आयपार महानिदेशक (छूट), अनकता को तीन प्रतियों में आबेदन करें, अनुमोदन की अविध बढ़ाने के मंत्रेध में किए आबेदर पत्न की विमाग की प्रस्तुत करना है।

[सं. 1548/एफ. सं. भ.नि./म्रा.क. (छूट)/
कल/जी-35/35(1)(ii)]
म्रार. सिंह, उप निदेशक

INCOME TAX

S.O. 1609.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary. Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delbi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE GRGANISATION

Sardar Paiol Renewable Energy Research Instituto Vallobh Vidya Nagar-388120.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-2-96.

Notes: (1)Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Sperctary, Department of Scientific & Industrial Research.

INC 1548 F. No. DG | IT(E) | Cal G-35 | | 35(1)(ii) | R. SINGH, Dy. Director

कलकला, 19 फरवरी, 1996

आयकर

ा. आ. 1610.—प्तर्वशाधारण को एतदहारा सूचित किया जाता है कि निस्तिलिखित संगठत को, अध्यकर श्रिधित्यम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित शाधिकारी हारा निस्तिविधित गर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन धन्पोदित विध्या गया है: → •

- (i) संगटन अन्संधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैशानिक अनुसंधान संबंधी वार्यी का एक वार्षिक विजरण प्रत्येक कितीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैशानिक व श्रीबोधिक अनुसंधान विभाग, ''प्रीवाधिक अवन'' त्यु महुशीली रोड, नई दिल्ली-- 110016 की भेजेगा, श्रीप
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अस्तूबर तक लेखा-पर्शक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) मचिष वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग श्रौर (ग) श्रायकर स्नायुक्त/स्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है श्रौर श्रायकर ग्राधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संज्ञित छूट के बारे में लेखा परीक्षित श्राय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

पुटबेयर डिजाइन एण्ड डैवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ए-8, येवटर-9, नोएडा-201301.

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 में 31-3-96 सक की अर्थाध के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी : 1. उपर्युक्त मर्त (1) "संघ" जैसा संखर्ग के लिए लाग् नहीं होगा।
 - 2. संगठत को सुझाब दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के साध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में शानेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत की विभाग को प्रस्तुत करना हैं।

[सं. 1549/एफ.सं. म.नि./श्रा.क.(छूट)/ कल./जी-68/35(1)(ii)]

श्रार. सिह, उप निदेशक

Calcutta, the 19th February, 1996 faura (Paralleland)

INCOME TAX

- S.O. 1610.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of syb-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110616 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Footwear Design & Development Institute, A-8, Sector-9, NOIDA-201301.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes.—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-lax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1549] F. No. DG-IT(E)|Cal (G-68)|35(1)(ii)}
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1996

श्रीयकर

- का. आ. 1611:—सर्वसाधारण को एतस्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखिन शर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के श्रधीन श्रनुसोदित किया गया है:—
- (i) संगठन ग्रनुसंधान कार्यों के लिए सलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह ग्रवने वैज्ञानिक ग्रनुसंघान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक मचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक धन्मंधान

विमाग ''प्रौद्योगिकी भवन'' न्यू महरौती रोड, नई दिल्ली, 110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) प्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सिवब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रमुसंधान विभाग और (ग) श्रायकर श्रायुक्त श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और श्रायकर श्रधिनियम 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-स्थाय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

जैन विश्वा भारती, पी.श्रो. लदनून, डिस्ट-नगौर-341 306, राजस्थान

यह प्रधिमूचना दिनांक 1-4-94 में 31-3-96 तक की श्रवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :— 1. उपर्युक्त गर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लाग नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमीदन
की श्रविध बढ़ाने के लिए श्रायकर श्रायुक्त,
श्रायकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में
संगठन पडता है के माध्यम से आयकर महाजिदेशक (छूट), कलकत्ना को तीन प्रतियों में
श्रावेदन करें, श्रनुमोदन की श्रविध बढ़ाने के
मंबंध में किए श्रावेदन पत्र की विभाग को
प्रस्तुत करना है।

[सं. 1550/एफ. सं. म.नि./ग्रा.क. (छूट)/कल/आर-3/ 35(i)(iii)]

ग्रार मिह, उप निदेशक

Calcutta, the 19th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1611.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of subsection (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, the 31st October, each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Jain Vishwa Bharati, P.O. Ladnun, Dist-Nagaur, 341306, Rajasthan.

This Notification is effective for the period from 1-4-94 to 31-3-96.

- Notes (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply to triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income (Exemptions), Calcutta through Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1550]F. No. DG-JT(E)[Cal|R-3|35(1)(iii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. श्रा. 1612--सर्वमाधारण को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, भायकर नियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए प्रायकर नियम के नियम 6 के प्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गर्ती पर ''संस्थान'' के संवर्ग के अधीन ग्रन्मोदित किया गया है :---

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा:-
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक संधान विभाग प्रोद्योगिकी भवन न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 ग्रक्तूबर तक लेखा परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिदेशक (छट) (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक श्रन्संधान विभाग और (ग) श्रायकर श्रायुक्त / श्रायकर महानिदेणक (छट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और त्रायकर श्रधिनियम 1961 की धारा 35(i) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षीत श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तत करेगा।

संगठन का नाम: साइंस एण्ड टैक्नोलोजी इंटरफेरेनर्स पार्क, गुरू नामक इंजीनियरिंग कॉलेज, गिल रोड, लोबीयाना-141006

सक यह श्रधिसचना दिनाक 1-4-95 में 31-3-96 की अवधि के लिए प्रमावी है।

लिए टिप्पणी:- 1. उपर्युक्त शर्त (i) संघ जैमा संवर्ग के लाग नहीं होगा।

> 2. संगठन को मुझाव दिया जाता है कि वे धनु-मोदन की प्रविध बढ़ाने के लिए भायकर भायकर धारकर निर्वेशक (छुट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से क्रायकर माहनिर्देशक (छुष्ट) कलकत्ताको तीम प्रतियों में ग्रावेदन करें, ग्रसभोदन की प्रावधि बहुति के संबंध में किए श्रावेदन पत्न की विभाग की प्रस्तुत करना है।

> > [सं. 1551/एफ. सं. म. नि./म्रा.क. (छूट)/ कल/पी-5/35(1)(ii)]

> > > ग्रार भिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996 INCOME TAX

- S.O. 1612.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" ject to the following conditions:-
 - The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions). (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c)

1292 GI/96-5.

Commissioner of Income TaxiDirector of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October, each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Science & Technology Enterpreneur's Park. Guru Nanak Engineering College, Gill Road, Ludhiana-141006.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1551|F. No. DG-JT(E)|Cal|(P-5)| 35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. थ्रा. 1613 सर्वेसाधारण को एतदहारा स्वित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को श्रायकर श्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन बिहित प्राधिकारी हारा निम्नलिखित शतीं पर "संस्थान" के संवर्ग के श्रधीन श्रनुमोदित किया गया है:——

- (i) स्गठन श्रनुसंधान कार्यों के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सिचय, यैज्ञानिक व श्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन "न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली— 110016 को भेजेगा, श्रौर

(iii) यह परयेक वर्ष के 31 पलटूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) प्रायक्तर महानिवेशक (छ्ट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा प्रोशीगिक प्रवृद्धधान विभाग और (ग) प्रायकर प्रायुक्त/प्रायकर महानिवेशक (छ्ट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आधकर घांधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधिन छुट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रम्तुत करेगा।

संगठन का नाम: क्रिश्चियन मेडिकन कालेज, लोदीयाना सोसाइटी, ब्राउन रोड, लोदीयाना, पंजाब-141 008

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1~4-95 में 31-3-96 तक की श्रविध के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैमा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनु-मोदन की श्रवधि बढ़ाने के लिए श्रायकर श्रायुक्त/ श्रायकर निर्देणक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से श्रायकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में श्रावेदन करें, श्रनुमोदन की श्रवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए श्रावेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है।

> [सं. 1552/एक .सं. म. नि./म्रा.क. (छूट)/ कल./पी-8/35(1)(ii)]

> > थार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

INCOME-TAX

- S.O. 1613.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Scertary, Department of Scientific and Industrial Reseach, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) I will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Christian Medical College, Ludhiana Society. Brown Road, Ludhiana, Punjab-141008.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

NOTES:

- (1) Condition (1) above will not pply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1552]F. No. DG-IT(E)|Cal(P-8)|35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. आ. 1614-सर्वसाधारण की एतदक्षारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विह्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित णतों पर "संघ" के संवर्ग के श्रधीन श्रनुमोदित किया गया है:---

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिए श्रनग नेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विक्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचित्र, वैज्ञानिक व श्रौद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन, न्यू महरौत्री रोड, नई दिल्ली— 110016 को भेजेगा, श्रौर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 श्रवट्यर तक लेखा— परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा श्रीद्योगिक स्रनुसंधान विभाग श्रीर (ग) श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है श्रीर श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित श्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: हस्तीमल संचेती रिसर्च फाउण्डेणन, 16, शिवाजी नगर, पूना-411 005

यह श्रिधसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-95 तक की श्रविध के लिए प्रभावी हैं।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त अतं (1) "संध" जैगा गवर्ग के लिए लागू नहीं होगा। 2. संगठन को सुझाब दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक (छूट) जिनके छोद्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करं, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पद्र की विभाग को प्रस्तुन करना हैं।

[सं 1553/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम-92/35(1)(ii)] ग्रार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1614.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary. Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Meharauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of andited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Hastimal Sancheti Research Foundation,

16, Shivajinagar, Pune-411005: This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

INo. 1553|F. No. DG-IT(E)|Cal(M-92)|35(1) (ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलभता, 22 फरवरी, 1996

आयकर

- का. थ्रा. 1615—सर्वसाधारण का एसद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर ग्रधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर संस्थान के संवर्ग के अधीन श्रनुमोदित किया गया है:—
- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए धलग लेखा बहियां रखेगा :--
- (ii) यह प्रपनं वैज्ञानिक प्रनुसंधान संबंधी कायों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक संचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन, न्यू मेहराँली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक नेखा परीक्षीत वाधिक लेखा की प्रति (क) प्राथकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रनुसंधान विभाग और (ग) श्रायकर श्रायुक्त | सायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है आर प्रायकर प्रधिनयम, 1961 की धारा 35(i) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षीत समय क्याय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का काम : पीपल्स इंस्टीट्यूट फाँर डेबलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग, सी-1/1414, बसम्त कुंज, नई दिल्ली 110037

यह श्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की श्रविध के लिए प्रभावी है।

टिप्पयी:-- 1- उपर्युक्त मर्स (i) संघ जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

> संगठन को सुझाब दिया जाता है कि वे अनुमोदन की श्रवध बढ़ाने के लिए श्रास्थकर आयुक्त/

ग्रायकर निदेशक (छ्ट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम में श्रायकर माहनिदेशक (छ्ट) कलकता को तीन प्रतियो में श्रावेदन करें, ग्रानुमोदन की श्रवधि बढ़ाने के संबंध में किए ग्रावेदन पत्र की सिभाग को प्रस्तृत करना है।

> [सं. 1554/एफ. स. म.नि./ग्रा.क. (छूट)/ कल.एन.डी.-33/35(1)(iii)]

> > श्रार सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1615.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate book of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Meharauli Road, New Delhi-10016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October cach year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of andited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

People's Institute for Development and Training, C-I|1414, Vasant Kunj, New Delhi-110037.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

INo. 1554 F. No. DG-IT(E) Cal(ND-33) 35(1) (iii)

R. SINGH, Dy. Director

कनकरना, 22 फरबरो, 1996

ग्रायकर

- का. का. 1616.—सर्वसाधारण की एतद्हारा यूनित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन की, श्रायवार श्रिधिनिसम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii), के लिए खायकर नियम के नियम के के ऋधीन विहिन प्राधिकारी हारा निम्नलिखित णतीं पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन श्रमुमोदित किया गया है:—
- (i) गंगठन श्रनुसंधान कार्यों के रिग् अलग लेखा बहिया रखेगा।
- (ii) यह रापने वैज्ञानिक शनुसंधाना संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विनीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचित्र, वैज्ञानिक व औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, ''प्रोद्योगिकी भवन'' न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 की भैजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्राबर तक विधा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) सायकर महाविद्रेशक (छूट), (ब) अचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक श्रनुसंबान विभाग और (ग) श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उपन संगठन पड़ता है और श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिक्षर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-स्थय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: वी इंस्टीट्यूट श्रॉफ नार्टर्ड एकाउंटेन्टम श्रांन ३ डिया, बी.पी.नं. 7100, इंदराप्रस्था भागे, नई दिल्ली-110002

यह श्रिधसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:-- 1 उपर्यक्त गर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए नागू नहीं होगा। 2. संगठन को सुझाय दिया जाता है कि वै अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आधकर अध्युवन/
आधकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पढ़ता है के माध्यम से आयकर गहानिदेशक (छूट), कानकाता को तीन प्रतियो में आयेदन वारें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लंबध में किए आवेदन-पह की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1555/एफ. सं. म. नि./प्रा.क. (छूर)/ कल/एनडी-46/35(1)(iii)] ग्रार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996 INCOME TAX

- S.O. 1016.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Institute of Chartered Accountants on India, B-P-No. 7100, Indraprastha Marg, New Delhi-110002.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further eytension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1555|F. No. DG-IT(E)|Cal|ND-46|35(1) (iii)]

R. SINGH, Dy. Director

आधनार

कलकता, 22 फरवरी 1996

का.श्री. 1617—सर्वमाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को. जायकर अधिनियन, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये श्रायकर नियम के नियम 6 के अबीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित मती पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :---

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिये ग्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वाधिक विवरण प्रत्येक विसीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक अधौद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रांद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, ग्रांर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) स्रायकर महानिवेशक (छूट), (ख) सचिव, वैशानिक तथा श्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग; ग्रीर (ग) स्रायकर प्रायक्त श्रीयाकर महानिवेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उत्रत संगठन पड़ता है और श्रीयकर श्रधिनियम, 1961की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परक्षित श्रीय-ध्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: इंबिरा गांधी नेशनल सेन्टर फाँरदी श्रर्द्स, जनपथ, नई विल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1→4-96 से 31-3-96 तक की अवधि के लिये प्रभावी हैं।

- दिष्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागु नहीं होगा।
 - सगऊन को सुभाव दिना पाला है कि ले अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिने आयगर

स्रायुक्त/श्रायकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से श्रायकर महानिदेशक (छूट), कलकता की तीन प्रतियों में श्रावेदन करे, अनुमोदन की सबध बढ़ाने के संबंध में किया श्रावेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1556/एफ. सं. म. नि./ग्रा.क. (छूट)/कल/एन. डी.-22/35 (1) (ii)]

भार, सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996 INCOME TAX

- S.O. 1617.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan," New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions) (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indira Gandhi National Centre for the Arts, Janpath, New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions). Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisatios. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1556|F. No. DG-IT(E)|Cal|ND-22|35(1) (iii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 फरवरी, 1996

का. थ्रा. 1618. — सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिये श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रिधीन विहित प्राधिकारी दारा निम्नलिखित शर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के श्रिधीन श्रनुमोधित किया गया है:—

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिये यसग लेखा बहियां रेखेगा।
- (ii) यह प्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विसीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व श्रीद्योगिक अनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन'' न्यू मेहरौली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, ग्रीर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) मिलब, बैजानिक तथा श्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, श्रीर (ग) आयकर श्रायुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है श्रौर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में वी गर्ट रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-क्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: इंडियन कौसिल ग्रॉफ मेडिकल रिसर्च, ग्रंसारी **नग**र, पी.नी.नं. 4508, नर्ड दिल्ली-110029

यह प्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की ग्रयधि के लिये प्रभावी है।

- टिप्पणी : 1. उपर्युक्त गर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।
 - संगठन को सुझाब दिया जाता है कि बे श्रनुमोदन की श्रवधि बढाने के लिये श्रायकर

भागुक्त/मागगर िश्चिगक (कुट) लिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम में आध्यकर महानिवेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अविध बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पन्न विभाग को प्रस्तृत करना है।

[सं. 1557/एफ सं. म.नि./ब्रा.क./(छूट)/ कल/एन.डी.-59/35(1)(ii)] ग्रार. सिंह. उप निवेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1618.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research. 'Technology Bhawan New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar, P.B. No. 4508, New Delhi-29.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdeition over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1557 F. No. DG-IT(E)|Cal|ND-59|35(1) (ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कतकता, 22 फरवरी, 1996

भ्रायकर

का. श्रा. 1619—सर्यसाधारण को एतदबारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित णहीं पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन असीन श्रम्मोदित किया गया है:—

- (i) संगटन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
 - (ii) यह ध्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वर्भिक विवरण प्रत्येक विक्तीय वर्ष के जिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ''प्रोद्योगिकी भवन'' स्यू महरौली रोड, नई दिल्ली — 110016 को भेजेगा, और
 - (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा— परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) प्रायकर महानिदेणक (छूट), (ख) सिचन तैसातिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) ग्रायकर प्रायुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में उक्त संगठन पड़ता है और श्रायकर ग्राधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के जारे में लेखा परीक्षित प्राय-व्यय हिसात्र को भी प्रम्तुत करेगा।

संगठन का नाम: नेशनल इन्होरेंस अकाडेमी, वालेवादी, बाउर रोड, एन.आई.ए. पी. श्रो., पुना-411045

यह अधिसूचन (दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 नक की प्रमिधि के लिए प्रभावी है।

टिष्पणी : 1. उपर्युक्त मर्त (1) "रांघ" जैना संबर्ध के लिए लागू नहीं होग ॥ 2. संगठन को सुझाब दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अविधि बढ़ाने के लिए आयकर आय्क्त/ सायकर निर्देणक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम के आयकर महानिदेणक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियां प्रावेदन करें, प्रनुमोदन की प्रविध बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1558/एफ.सं. म.नि./ग्रा.क.(छूट)/ कल/एम-149/35(1)(iii)]

श्रार सिह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1619.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the "category institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

National Insurance Academy, Balewadi, Bauer Road, NIA P.O. Pune-411045.

This Notification is effective for the period from 1-4-1995 to 31-3-1996.

NOTES:

- (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

INo. 1558|F. No. DG-IT(E)|Cal. (M-149)| 35(1)(iii)|

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 फरवरी 1996

अधिकर

का. आ. 1620 - सर्विषाधारण को एतद्हारा मूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर, "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदन किया गया है:—

- (i) संगठन श्रन्सधान कार्यों के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विस्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सलिल, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग प्रोडोगिकी भवन त्यू महरौली रोड, नई दिल्ली — 110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिर्देशक (शृष्ट), (ख) सचिब, बैज्ञानिक तथा आँखोगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर श्रायुक्त/ श्रायकर महानिर्देशक (शृष्ट) जिनके क्षेत्राधिकार में उका संगठन पड़ा है और श्रायकर अधिनियम, 1961, की धारा 35 (i) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित शृष्ट के बारे में लेखा परीक्षित श्राय-व्यय हिमाब को भी प्रम्मुत करेगा।

मंगठन का नाम: लेडी अन्सुया सिधानिया मैडिकल रिसर्च सोसाइटी, जय केय नगर, लोटा-324003

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-35 के 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्गुवत शर्त (1) "संघ" **जैमा संब**र्ग के लिए लाग् नहीं होगा । 2. रांगठल को मुझाउ रिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि वहाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पहला है के साध्यम में आयवार प्रहानिर्देशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन गढ़ा को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1559/एफ सं स.नि./प्रा.क. (छूट)/ कल/प्रार-1/35(1)(ii)] श्राण. भिह, उप निर्देशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1620.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Lady Ansuya Singhania Medical Research Society, Jay Kay Nagar, Lota-324003.

This Notification is effective for the period from 1-4-1995 to 31-3-1996.

NOTES:

- (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income-tax (exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1559|F. No. DG-IT(E)|Cal-(R-1)|35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकता, 22 फरवरी, 1996

श्रायकर्

का. आ. 1621—सर्वेसाधारण को एतद्द्वारा मृचित किया जाता है कि निम्नेलिखित संगठन को, ग्राथकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये ग्रायकर नियम के नियम 6 के ग्रधीन विह्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नेलिखित गर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के श्रधीन श्रनुमोदिन किया गया है :——

- (i) संगठन भन्संधान कार्यों के लिये श्रलण लेखा अहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक असंनुधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सिचव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) प्रायकर महानिर्देशक (छूट),(ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रमुसंधान विभाग और (ग) प्रायकर प्रायकत/ प्रायकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और प्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया सर्वधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षीत प्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तत करेगा।

संगठन का नाम: दी फिपीकल रिसर्च फाऊण्डेशन, एल-22, होज खास इनक्लेब, नई दिल्ली-110016

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 में 31-3-96 तक की ग्रवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा। 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अविध बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिद्देशक (छट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अविध बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पक्ष की विभाग को प्रस्तत करना है।

[सं. 1560/एफ .सं. म.नि./म्रा.क. (छूट)/ कल./एन.डी.-58/35(1)(iii)] ग्रार. सिंह, उप निर्देशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1621.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

The Fiscal Research Foundation, L-22, Hauz Khas Enc. New Delhi-110016.

This Notification is effective for the period from 1-4-1995 to 31-3-1996.

NOTES:

(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1560|F. No. DG-IT(E)|Cal. ND-58|35(1)(iii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. श्रा. 1622 — सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन की, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये श्रायकर नियम के नियम 6 के स्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "कालेज" के संवर्ग के श्रधीन श्रनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन प्रनुसंधान कार्यों के लिये प्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह प्रभने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व श्रीछो- गिक प्रनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 की भेजेगा, श्रीप
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) धायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा प्रीचोगिक प्रनुस्थान विभाग भीर (ग) भायकर धायुक्त/भायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ना है भीर भायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षीत ग्राय-व्यय हिसाब की भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: स्थामी मानसिंह एस. मेडिकल कॉलेज, (एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज), जयपुर, राजस्थान । यह प्रधिमृचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की श्रवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त गर्त (1) "रांघ" जैसा संबर्ग के लिये लागु नहीं होगा।

शंगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुगादन की अविध बढ़ाने के लिये आयकर आयुवन/प्रायकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर गहानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अविध बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1561/एफ.सं. म.नि./आ.क.(छूट)/ (कल./आर.-5/35(1)(ii)] आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

- S.O. 1622.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "College" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activitions.
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under subsection (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Sawai Mansingh S. Medical College, (S.M.S. Medical College), Jaipur, Rajasthan.

This Notification is effective for the period from 1-4-1995 to 31-3-1996,

NOTES:

- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categoriesd as 'association'.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1561]F. No. DG-IT(E) |Cal (R-5)|35 (1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. थ्रा. 1623 — सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्निलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रिधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्निलिखित शर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के प्रधीन श्रनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लिखा बह्यां रखेगा।
- (ii) यह अपने बैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्या का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विनीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रीद्योगिकी भवन, त्यू महरोगी रोष, नई दिल्ली-110016 को भेजगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अन्त्र्वर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सिचव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर प्रायुक्त । आयकर महानिदेशक (छट) जिनक क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35(i) में दी गई रिसर्च किया जाए संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षीत स्राय व्यय हिसाब को भी प्रस्तत करेगा ।

संगठन का नाम :

हरि णंकर सिथानिया एलासटींम एण्ड टायर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयकेय ग्राम, पी.ओ. टायर फैक्टरी-313342, कंकोजी डिस्ट, राजसमन्द, राजस्थान

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की ग्रवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:-- 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को मुझाय दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अविध बढ़ाने के लिए श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को, तीन प्रतियों में श्रावेदन करें, अनुमोदन की श्रवधि बढ़ाने के संबंध में श्रावेदन-पत्न विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1562/एफ.सं. म.नि./आ.क.(छूट)/ कल/आर-13/35(1)(ii)] श्रार सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

- S.O. 1623.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure

Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAFE OF THE ORGANISATION

Hari Shankar Singhania Elastomer and Tyre Research Institute, Jaykayghram, P.O. Tyre Factory-313342, Kankroli Dist., Rajsamand, Rajasthan.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as 'associations'.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

INo. 1562|F. No. DG-IT(E)|Cal(R-13)/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 फरवरी, 1996

श्रायकर

कां. आ. 1624 — सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नितिखित संगठन को, आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्निलिखित णतीं / पर ''संग्थान'' के संवर्ग के अधीन अनुसोदित किया गया है:——

- (i) संगठन अनुसंधाना कार्यों के लिए अलग लिखा विह्यां रखेगा,
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वाधिक विवरण प्रत्येक विलीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के अ। मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्यो- िपक अनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन, त्य मेहरौंजी रोड, नई दिल्ली-110016 की भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेगापरीक्षीत वार्षिक लेखा की जीत (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा श्रीद्योगिक अनुसंधान विभाग श्रीर (ग) आयकर आयुक्त/श्रायकर महा-

निवेशक (छूट) जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है स्रोर स्रायकर स्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षीत स्राय व्यय हिसाब को भी प्रस्तत करेगा।

संगठन का नाम

नेशनल ग्रकाडेमी ग्रॉफ इंजीनियरिंग, सेन्ट्रल सोइल एण्ड मटेरियलस रिसर्च स्टेशन कम्पलैक्स, ग्रोल्फ पलामी मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-1100016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की भ्रवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:-- 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैमा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

> 2. संगठन को सुझाय दिया जाता है कि वे अनुमोदन को अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदे-शक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिवेशक (छूट), कलकरता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में आवेदन पक्ष विभाग को प्रस्तुत करना है।

> > [सं. 1563/एफ.सं. म. नि./ग्रा.क. (छूट)/ कल./एन.डी-56/35(1)(ii)] ग्रार सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

- S.O. 1624.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Re an of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having

jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

National Academy of Engineering, Central Soil & Materials Research Station Complex Olof Plame Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions). Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1563[F. No. DG-IT(E)]Cal(ND-56)/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director कलकत्ता, 22 फरवरी, 1996

श्रायकर

का.चा. 1625.—सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए प्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन बिहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित एतीं पर "संस्थान" के संबर्ग के प्रधीन श्रनुमोदित किया गया है:——

- (i) संगठन भ्रनुसंधान कार्यों के लिए भ्रालग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यां का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिब, वैज्ञानिक व श्रीबोगिक श्रनुसंधान विभाग, "प्रोद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्राय-कर महानिदेशक (छुट), (ख) मचिष वैज्ञानिक तथा श्रीद्योगिक श्रनसंधान विभाग श्रीर (ग) श्रायुक्त/प्रायकर महानिदेशक (छट) श्रायकर जितके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा है ग्रीर 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित के बारे में लेखा-परीक्षीत हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: इंडियन सोसाइटी श्रॉफ इन्टरनेशनल लॉ, 7-8, सिध्या हौस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की भ्रविध के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझात दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/ आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महा- निर्देशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1564/एफ.सं. म.नि./आ.क.(छूट)/ कल./एन.डी.-8/35(1)iii)] श्रार. सिंह, उप निर्देशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

- S.O. 1625.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary. Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;

(iii) It will submit to the (a) Director General (Exemptions), Inco.ae Tax (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Indian Society of International Law, 7-8, Scindia House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1564 F. No. DG-IT(E)|Cal(ND-8)/35(1)(iii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. आ. 1626.—सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर अधि-नियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गतौ पर "संस्थान" के संवर्ग के श्रधीन अन्मोदिन किया गया है:—

- (i) संगठन प्रान्संधान कार्यों के लिए प्रालग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कायों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव,

- वैज्ञानिक व श्रौद्योगिक श्र<mark>नुसंधान विभागः</mark> ''प्रोद्योगिकी भवन'' न्यू मेहरोली रोड, नई विल्ती 110016 को भेजेगा, श्रौर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) म्राय-महानिदेशक कर् (ভূट), (理) वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक श्रनसंधान विभाग (ग) त्रायकर श्राय्क्त/श्रायकर म<mark>हानिदेशक</mark> ग्रीर जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है श्रौर श्रायकर श्रधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिक्षर्च किया गया संबंधित छुट के बारे में लेखा-परीक्षीत स्राय व्यय हिसाब को भी प्रस्तृत करेगा।

संगठन का नाम: नेशनल इंस्टीटंयूट श्रॉफ इम्मोनोलॉजी, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की अबधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी : (1) उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागु नहीं होगा।
 - (2) संगठन को सुझात्र दिया जाता है कि वे धनुमीदन की प्रविध बढ़ाने के लिए श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पढ़ता है के साध्यम से ग्रायकर महानिर्देशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में ग्रावेदन करें, श्रनुमोदन की श्रविध बक्षाने के संबंध में किए श्रावेदन-पत्र की खभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1565/एफ. सं. म.नि./श्रा.क.(छूट)/ कल./एन.डी.-34/35(1)(ii)] श्रार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd February, 1996

- S.O. 1626.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- of Ingome Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

National Institute of Immunology, Shaheed Jit Singh Marg, New Delhi-110067.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Note: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1565|F. No. DG-IT(E)|Cal(ND-34)/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता. 22 फरवरी, 1996

ग्रायकर

का. या. 1627.—सर्वसाधारण को एतदहारा सूचिन किया जाता है कि निस्नलिखिन संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 को उपधारा (1) के खंड (ii) लिए भ्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित भर्तों पर "संघ" के संवर्ग के श्रधीन भ्रनुमोदित किया गया है :-

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विषरण प्रत्येक वित्तीय वर्षे के लिए प्रत्येक वर्षे के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व श्रीद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन "त्यू महरौली रोड़, नई दिल्ली — 110016 को भेजेगा, श्रौर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अन्तूबर तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेबा की प्रति (क) आयकर
 महानिदेशक (छूट); (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा
 ग्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग श्रौर (ग) प्रायकर
 प्रायुक्त, प्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है ग्रौर श्रायकर
 ग्रिक्षित्तमम, 1961 की धारा 35 (1) में दी
 गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में
 नेखा परीक्षित ग्राय-ज्याय हिसाब को भी प्रस्तुत
 करेगा।

संगठन का नाम: सिद्धु मल रिसर्च फाउण्डेशन, सिद्धुमल बिल्डिंग, 40 गली राजा केदार नाथ, चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006 ।

यह ग्राधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की यवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त णर्त (1) "संत्र" त्रीसासंत्रर्ग के लिए लग नहीं होगा।

> 2 सं ाठन को सुझाब दिया जाता है कि वे अनु-मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त |आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के साध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कतकत्ता को तीन प्रतियों में शादेदन करें, अनुपोदन को प्रश्चित्रकों के संबंध में किए आवेदन पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है।

> > [सं. 1566/एक.सं. म.नि./आर.क. (छूट)/ कल./एन.डी-7/35(1)(ii)] थार. सिंह, उम निदेणक

Calcutta, the 22nd February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1627.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the

purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretacy, Department of Scientific & Industrial Research; 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- It will submit to the (a) Director General (iii) (Exemptions), Tax Income (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Siddho Mal Research Foundation, Siddhomal Building, 40, Gali Raja Kedar Nath, Chawri Bazar, Delhi-110006.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary. Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1566]F. No. DG-IT(E) |Cal(ND-7)/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

क्तनकत्ता, 22 फरवरी, 1996

प्रायकर

का.आ. 1628 — सर्वेसाधारण को एतदहारा मूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित श्रिधिकारी हारा निम्नलिखित गर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के श्रधीन श्रन्मोदित किया गया है —

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिए श्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह प्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक जिल्लीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व श्रीद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिकी भवन'' न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली — 110016 को भेजेगा, ग्रौर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक नेवा को प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक ग्रमुसंधान विभाग ग्रौर (ग) ग्रायकर ग्रायुक्त/ ग्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है ग्रौर श्रायकर श्रधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संवधित छूट के बारे में लेबा परीक्षित ग्राय-व्यय हिसाब का भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: सेन्टर फॉर श्रर्थ साइन्स स्टडीज, पी.बी. नं. 7250, थूरोभिकल पी.ग्रो. स्रिवेन्द्रम-695 031

यह म्रधिसूधना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की म्रबधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" भैसा संवर्ग के लिए लागु नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयंकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकसा को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1567/एफ.सं. म.नि./ग्रा.क.(छूट)/ कल./के.8/35(1)(ii)]

थ्रार. सिंह, उप नि**देशक**

Calcutta, the 22nd February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1628.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawau', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - (iii) It will submit to the (a) Director General Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Centre for Earth Science Studies, P.B. No. 7250, Thuruvikkal P.O. Trivandrum-695031,

This Notification is effective or the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension

of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1567]F. No. DG-IT(E)|Cal(K-8)/35(1)(ii)|

R. SINGH. Dy. Director

कलकत्ता, 27 फरवरी, 1996

आयकर

का.आ. 1629 ----सर्वेमाआरण को एतव्हारा सूचित किसा जाता है कि निक्निलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियस ६ के खंडोन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्निलिखन मती पर "संघ" के संबंध के अधीन अनुसोदित किया गया है :--

- (i) संगठन ग्रन्संधान कार्यों के विए धलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह प्रपने वैज्ञानिक धनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रस्मेक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्मेक वर्ष के 31 मई तक सिंबत वैज्ञानिक व औद्योगिक धनुसंधान विभाग, प्रांचोगिक प्रयन, 'ग्यु मेहरीली रोड, नई विल्ली-110016 को भेडेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रनतूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रनुसंधान विभाग और (ग) आयकर ग्रायुक्त/माय-कर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उत्त मंगठन पड़ना है और श्रायकर ग्राधिनियम, 1961 की घारा 35 (1) में वी गर्ध रिसर्च किया गया संबंधित छूटके बारे में नेखा-परीक्षित ग्राय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: इंडियन नेशनल साइन्म श्रकाडेमी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002।

यह प्रधिसूचना विनोक 1-4-95 में 31-3-95 नक की प्रविधि के लिएप्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युत्तम शर्म (i) "सध" जैसा एंटर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 - 2. संगठन को सुक्षाव दिया जाता है कि ये अनुमौचन की स्वविध बढ़ाने के लिए श्रायकर ायुक्त/श्रायकर निमादेक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में सगान पड़ता है के माध्यम से श्रायकर महानिदेशक (छूट), काकला को तीन प्रतियों में श्रावेदन करें, धनुमोदन की श्रविध दढ़ाने के संबंध में किए श्रावेदन-पन्न की विभाग को पस्तुन करना है।

[सं. 1568/एफ सं. म.नि./आ.क.(छूट)/ कल./एन.डी.-76/35(1)(ii)]

ग्रार, सिंह, उप निद्येणक

Calcutta, the 27th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1629.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the

category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road. New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION ·

Indian National Science Academy, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1 Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Rsearch.

¹No. 1568|F. No. DG-IT(E)|Cal(ND-76)/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 27 फरवरी, 1996

भ्रायकर

का. प्रा. 1630: — सर्वसाधारण को एतदुबारा सूचित किया जाता है कि निम्निसिखन संगठन को, प्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए प्रायकर नियम के नियम 6 के प्रधीन विहित प्राधिकारी हारा निम्निलिखित गर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के प्रधीन प्रन्मीदित किया गया है: →

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने बैजालिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विशोध वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" स्पू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भैजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 म्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) प्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव नैक्षानिक तथा औद्योगिक म्रनुसंधान विभाग और (ग) मायकर मायुक्त/ शायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और भायकर मिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में की गई रिसर्च किया गया संबंधित छुट के बारे में लेखा परिक्षित श्राय-क्याय हिमाब की भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: तापाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मनीपाल-576119. कर्नाटक

यह माधिसूचना दिनांक 1-4-95 में 31-3-95 तक का मनिध के लिए प्रभावी है।

- िष्यणी: 1. अपजुबतः गर्त (1) "मंघ" जैसा मंबर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 - 2. संगठन को मुझाब विया जाता है कि वे धनुमोबन की धविध बढ़ाने के लिए धायकर धायुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से धायकर महानिवेशक (छूट), कनकत्ता को तीन प्रतियों में धायेवन करें, धनुमोदन की धविध बढ़ाने के संबंध में किए प्रावेधन-पक्ष की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1569/एफ.सं. म.नि./ग्रा.क.(छूट)/ कल./के.टी.-43/35(1)(iii)] ग्रार. सिंह, उप निश्येक

Calcutta, the 27th February, 1996

- S.O. 1630.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Ta Pai Management Institute, Manipal-576119, Karnataka.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions). Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1569|F. No. DG-IT(E)|Cal(KT-43)/35(1)(iii)]

R. SINGH. Dy. Director

कॅलकत्ता, 27 फरवरी, 1996

ग्रायकर

का.धा. 1631: — मर्बसाधारण को एतब्दारा सूचित किया जाता है कि निम्निलिखित संगठन को, प्रायकर ध्रिधिनियम 1961, की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए घायकर नियम के नियम 6 के प्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्मिलिखित शर्ती पर "मंघ" के संबर्ध के प्रधीन धृतुमोदित किया गया है:—

(1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अता तेखा बहियां रखेगा।

- (2) यह प्रपने वैज्ञानिक प्रमुसंशान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्यक वर्ष के 31 पर्द तक सिख्य, वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" "न्यू मेहरीली रोड, नर्ष दिल्ली-110016 को भेजेगा.; और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 धक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वाषिक लेखा की प्रति (क) धायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रतुसंधान विभाग और (ग) धायकर धायकर प्रहानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और धायकर घिषियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में तेजा-परीक्षित धाय-ख्या हिसाय को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: इंडियन कौंसिल श्रांफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कृषि भवन, डा. राजेन्द्रा प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

यह ग्राधसूचना दिमांक 1-4-95 में 31-3-96 तक की ग्रवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी : 1. उपर्युक्त भर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 - 2. मंगठन को मुझाब दिया जाता है कि वे अनुसोदन की भवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निवेशक (छट) जिल्को क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिवेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आयदक करें, अनुमोदन की प्रविध बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुत करना है:

[सं. 1570/एफ.सं. म.नि./म्रा.क.(छूट)/ कल./एन.डी.-78/35(1)(ii)]

🕆 ग्रार सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 27th February, 1996

- S.O. 1631.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific &

Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations:
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1570|F. No. DG-IT(E)|Cal(ND-78)/35(1)(ii)]

R. SINGH. Dy. Director

कलकसा, 27 फरवरी, 1996

भ्रायकर

का. था. 1632: — सर्वसाधारण को एतव्ढारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, भाषकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए भायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्मलिखित गंती पेर "गंघ" के संवर्ग के श्रधीन अमुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन भनसंधान कार्यों के लिए भलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैशानिक धनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रस्थेक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्थेक वर्ष के 31 मई तक संशिव वैशानिक व श्रीद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौटोगिकी भवन" व्य मेहरौली रोड, नई विकानि 110016 की भेजेगा, भीर

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेका-परीक्षित वार्षिक लेखा की हैं प्रति (क) आयकर महानिर्देशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा श्रीद्यांगिक श्रनुसंक्षान विभाग श्रीर (ग) आयकर श्रायुक्त, भ्रायकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है श्रीर आयकर प्रधिनियम, 1961 की क्षाग 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-च्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: पोना मिडिकल रिसर्च फाउण्डेशन 40, शासन रोड, पुना-411 001

यह प्रधिसूचना विनोक 1-2-96 से 31-3-98 तक की प्रविध के लिए प्रभाषी है।

- टिप्पणी . 1. उपर्युक्त शर्म (1) 'मंघ' जैमा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 - मंगठन को सुझाब दिया जाता है कि ये अनुमोबन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त, आयकर निर्वेशक (घूट) जिनके को साधिकार में मंगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिर्वेशक (घूट), कलकला को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोबन की घबधि बढ़ाने के सबंध में किए आवेदन पढ़ की विभाग की प्रस्तुत करना है।

[सं. 1571/एफ. सं. म.नि./ग्ना.क.(छूट)/ कल./एम-191/35(1)(ii)] ग्रार. सिंह, उप निवेशक

Calcutta, the 27th February, 1996

- S.O. 1632.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan'. New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Sectionary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the

31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Poona Medical Research Foundation, 40, Sassoon Road, Pune-411001.

This Notification is effective for the period from 1-2-96 to 31-3-98.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1571|F. No. DG-IT(E)|Cal(M-191)/ 35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 27 फरवरी, 1996

यायकर

का. था. 1633: — सर्वेसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्निलिखित संगठन को, श्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iij) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के धार्था विहित प्राधिकारी द्वारा निम्निलिखित गर्ती पर "संस्थान" के संबर्ग के श्राधीन श्रनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन प्रनुसंक्षान कार्यों के लिए प्रलग लेखा बहिया रखेगा,
- (2) यह भपने वैज्ञानिक भनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रस्थेक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्थेक वर्ष के 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व श्रीद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भयन" न्यु मेहरौली रोड, नई विकली-110016 को भेजेगा, ध्रीर
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वाधिक लेखा की प्रति (क) भ्रायकर महानिर्देशक (छट), (छ) सचिव, कैज्ञानिक लया भ्रीधोगिक भ्रनुसंधान विभाग भ्रीर (ग) श्रायकर श्रायुक्त/ भ्रायकर महानिर्देशक (छट) जिनके क्षेत्राधिकार में उकत संगठन पश्ता है और भ्रायकर प्रधिनियम, 1961 की भ्रारा 35 (1) में किए गए रिसर्व कार्यों संबंधित थी गई छूट के बारे में के भ्रा-परीक्षित श्राय-स्थय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठ न का नाम : नेशनल इंस्टीट्यूट ग्रॉफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पोलिसी, 18/2, सत्यसंगवीर मार्ग, स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली- 110067

यह प्रधिसूचना विनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की प्रविध के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त मार्च (1) "संघ" जैना सर्वर्गके निर्तर्गार्धे होगा।
 - 2. संगठन की सुकाब दिया जाता है कि वे भानुमोदन की प्रविधा बढ़ाने के लिए भायकर भागुकत/भायकर निवेशक (छट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पक्ष्ता है के माध्यम से प्रायकर महामिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में भावेदन करें! भनुमोदन की श्रवधि बढ़ाने के संबंध में किए प्रावेदन-पत्र की जः प्रतियां, राखिल वैज्ञानिक व औधौगिक अनसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1572/एफ.सं. म.नि./भ्रा.क.(छूट)/ कल./एन.डी.-72/35(1)(iii)] भ्रार.सिंह, उप निवेशक्ष

Calcutta, the 27th February, 1996

- S.O. 1633.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - (iii) It will submit to the (a) Director Geneof Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of
 Income Tax Director of Income Tax
 (Exemptions), having jurisdiction over
 the organisation, by the 31st October
 each year, a copy of its audited Annual
 Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect
 of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of
 section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

National Institute of Public Finance & Policy, 18|2, Satsang Vihar Marg, Special Industrial Area, New Delhi-110067.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

- Notes: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary. Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1572|F. No. DG-IT(E)|Cal(ND-72)/35(1)(iii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 27 फरवरी, 1996

प्रायकर

का आ. 1634: — सर्वसाधारण को एनद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्निसित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विष्टित प्राधिकारी बारा निम्निलिखित णर्मी पर "पृणिवस्टि" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगटन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक जिजरण प्रस्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्येक वर्ष के 31 मई तक सचित, वैज्ञानिक व श्रीचोगिक श्रनुसंधान विभाग, ''प्रौद्योगिको भवन '' न्यू भेष्ठरौली रोड, नई विल्ली-110016 को भेनेगा, श्रीर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 घन्यूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचित्र, वैज्ञानिक तथा भौदोगिक घनुमंद्यान विभाग, भौर (ग) ग्रायकर ग्रायुक्त/ प्रायकर महानिरेणक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त मंगठन पडता है भौर धायकर मशिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में किए गए रिसर्च का ग्रीसिंगित दी गई छूट के बारे में लेखा-परीक्षित श्राय-स्थय हिमाब की भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: विरला इंस्टीट्यूट आँफ टैक्नोलॉजी एण्ड साईन्स, पीलानी-333031, राजस्थान

यह प्रधिसूचना दिनांकः 1-1-95 में 31-3-96 तक की अवधि के लए प्रभावी हैं। 5555 5555 555

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्स मर्ल (1) "गंद" नैसा संवर्ग के लिए लाग महीं होगा।
 - 2. संगठन को पुछाब दिया जाला है कि वे अनुसोदन की अविधि बढाने के लिए आयक्त धायुक्त, आयफर निवेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ना है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करे। अनुसोदन की अविधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन करे। उनुसोदन की अविधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की छ प्रतिवां सिचव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनस्थाम विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1573/एफ.सं. म.नि./म्रा.क. (छूट)/ कल! /म्रार-7/35(1)(ii)] ग्रार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 27th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1634.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Birla Institute of Technology & Science, Pilani-333031, Rajasthan.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta, through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1573|F. No. DG-IT(E)|Cal(R-7)/35(1)(ii)]

B. SINGH, Dy. Director

कलकना, 27 फरवरी, 1996

आयकर

- को. आ. 1635. सबसाधारण को एत्द्रारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रीधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंग्ड (ii) के लिए आयकर नियम के निराय है. के अधीन विहित प्रीधिकारी द्वारा निम्नलिखित शेर्तापर 'संस्थान' के संवर्ग के श्रीन श्रीन
- (i) संगठन अनुनवान कार्यों के लिए भारत लेखा बहियां रखेना ;
- (ii) यह प्राने बैझानिक अनुसंवान संगंधी काय का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विसीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव," बैझानिक व औद्योगिक यनुसंधान विभाग, "प्रोद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूनर तक लेखा-परीक्षित वाणिक लेखा भी प्रति (क) आयुक्तर महानिदेशक (छूट), (ख) मधित्र, बैज्ञानिक तथा औद्योनिक अनुसंधात विभाग और (ग) आयकर आयुक्त, आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रधिकार में उत्तत संगठन पड़मा है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के वारे में लेखा परीक्षित आय ज्या हिसाब को भी परमुत करेगा।

संगठन को नाम: नगरी आई रिसर्च फाउण्डेशन, सी.एच. नगरी म्यूनिसिपल आई हॉस्पीटिल इलिसबीज, अहमदाबाद-38 0006

पहुअधिम्तता दिनार 1-4-95 से 31-3-96 तक की धनधि के निए "भाषी हैं।

- रिटप्पभी:-- 1. उत्पृक्षत प्रति (1) "मंत्र" जैसा संबंध के लिए लागू नहीं होगा ।
 - संगठन को मुझाब दिला जाता है कि वे अनुमोदन को प्रविध बड़ाने के लिए श्रासकर

पायुका/आधार निकेशक (छूट) जिनके कैवाधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्रायक्त महा-निवेशक (छूट), कब्दकृत्मा को तीन प्रतियों में आवेदन करे, अनुमोदम की प्रविध बढ़ाने के संबंध में किए धावेदन पक्ष की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1574/एफ.सं. म.ति./प्रा.क.(छूट)/ ¹ कल./जी-46/35(1)(ii)] ग्रार सिंह, उप निदेशका

Calcutta, the 27th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1635.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax. Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:
 - (ii) It will furnish the Arnual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Nagri Eye Research Foundation, C. H. Nagri Municipal Eye Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1574|F. No. DG-IT(E)|Cal(G-46)|35(1)(ii)]
R. SINGH,Dv. Director

निलकत्ला, 28 फरवरी 1996

श्रायकर

- का. श्रा. 1636.--- मर्बमाधारण को एतस्रारा मूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर श्रिधिनयम, 1961 को धारा 35 की उपधार (1) के खण्ड (ii) के लिए श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन बिहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित णतों पर "संघ" के संधर्म के श्रधीन श्रन्मोदित किया गया है:--
- (i) संगठन श्रनुलंधान कार्यी के लिए श्रलग लेखा बहिय २ऐगा;
- (ii) यह श्रपने बैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वाषिक विवरण प्रत्येक विसीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचित्र, वैज्ञानिक व औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, ''प्रोधौगिकी भवन'' न्यू मेहरौती रोड, नर्ज दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 प्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) ग्रायकर महानिदेशक (ह्रूट), (ख) सचित्र, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक ग्रनुसंधान विभाग और (ग) ग्रायकर ग्रायुवत श्रायकर महानिदेशक (ह्रूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगटन पड़ता है और श्रायकर श्राधिनियम, 1961 की धारा 35(2) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधीत ह्रूट के वारे में लेखा परीक्षित श्राय व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नामः मलादी रिसर्व सेन्टर, नं.-52 जवाहर लाल नेहरू रोड, एक्काथूणाग, मट्रास-97।

यह अधिसूचना दिनांक 2-3-95 में 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:- 1. उपर्युक्त णर्व (i) "संघ्र" जैसा संवर्ग के लिए ाम नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाब दिया जाता है कि बे अनुसीदन की प्रविध बढ़ाने के लिए अध्यकर धायुक्त/प्रायकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम में ग्रायकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में ग्रावेदन करें, श्रवुमोदन की ग्राविध बढ़ाने के संबंध में किए बावेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तत करना है।

[सं. 1575 /एफ.सं.म.नि./थ्रा.क. (छूट)/कल/टी.एन.-55/ 35(1)(ii)] श्रार सिंह. उप निदेशक

Calcutta, the 28th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1636.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road. New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
 - (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Malladi Research Centre, No. 52, Jawaharlal Nehru Road, Ekkathuthangal, Madras-97.

This Notification is effective for the period from 2-3-95 to 31-3-98.

- Notes: (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax

1292 GI/96--8

(Exemptions). Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1575|F. No. DG-IT(E)|Cal. (TN-55)|35(1) (ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकता, 28 फरवरी, 1996

भ्रायकर

, का. था. 1637.—सर्वमाधारण को एतद्द्वारा मृधित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन की, आयकर श्रीधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये श्रायकर नियम के नियब 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर "संम्थान" के पंदर्ग को अधीन अनुमोदित किया गया है:——

- (1) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान मंबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विलीस वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सम्बिव, वैज्ञानिक ज औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ''प्रांद्योगिकी भवन'' स्यू महरोली रोड, लई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अवत् बर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) भायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक भनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिश्वरेंक (छूट) जिनके क्षेत्रा-धिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित भ्राय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुन करेगा।

संगठन का नाम : दिल्ली लाइब्रेरी नेट वर्क (ची.ई.एल .एन .इ.टी.), 40,नैंवस मृलार मार्ग, नई दिल्ली 110003

यह प्रधिसूचना दिगांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की भवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त मर्त (1) "संघ" जैसा संदर्ग े लिये लागू नहीं होगा। 2. संगठन को सुझाय दिया जाता है कि वे अनुमोदन की प्रविध बढ़ाने के लिये प्रायकर आयुक्त/प्रायकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में मंगठन पड़ता है के माध्यम में आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की प्रविध बढ़ाने के संबंध में किये श्रावेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1576(एक.सं. म.नि./ब्रा.क.(छ्ट)/कत./ एन. डी.-122/35(1)(ii)]

भ्रार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 28th February, 1996

INCOME TAX

S.O. 1637.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions). (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Delhi Library Network (DELNET). 40, Max Mueller Marg, New Delhi-110003.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1576]F. No. DG·IT(E) |Cal(ND-122)|35(1)

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 28फरवरी, 1996

ग्राधिकर

का. ग्रा. 1638—सर्वमाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, श्रायकर श्रिधितयम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये ग्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के श्रिधीन श्रनुमांदित किया गया है:——

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के निये अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह श्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विश्वीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सिचव, वैज्ञानिक व औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्षके 31 अक्तूबर तक लेखा-परिक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिर्देशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/ आयकर महानिर्देशक (छूट) जिगके क्षेत्राधिकार में उक्त मंगठन पड़िता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारेमें निखा-गरीकिन आय-अगथ हिसाव को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाग

कमला नेहरू मेमोरियल हाःपीटल, इसीम पुर रोड, इलाहाबाद-211002.

यह श्रधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की श्रवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त गर्त (1) 'मंध'' जैसा संबर्ग के लिये लागू नहीं होगा। 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि बे अनुमोदन की अविध बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निर्वेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की श्रविध बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्न की विभाग को प्रस्तुन करना है।

[संख्या 1577/एफ.सं. म.नि./श्रा.क.(छूट)/कल./ एन.डी.-98/35(1)(ii)]

श्रार, सिंह, उप निवेशक

Calcutta, the 28th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1638.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Kamala Nehru Memorial Hospital, Hashimpur Road, Allahabad-211002.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions). Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1577|F. No. DG-IT(E)|Cal (ND-98)|35(1) (ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 28 फरवरी, 1996

श्रायकर

का. आ. 1639—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को श्रायकर श्रिधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रिधीन विहित श्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर "संध" के संवर्ग के श्रिधीन श्रनुमोवित किया गया है:——

- (i) संगठन श्रनुसंधान कार्यों के लिये श्रलग लेखा बहियां रखेगा,
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक भ्रनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव' वैज्ञानिक व औद्योगिक भ्रनुसंधान विभाग ''प्राँद्योगिकी भवन'' न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) आवकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षीत आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तत करेगा।

संगठन का नाम

खोरा की बाला फाउण्डेशन वी.एफ.एफ/2 दिन खुग इंबस्ट्रियल इस्टेट, जीटी कर्नस रोड, दिल्ली-110033

यह ग्रधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-96 तक की ग्रवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्स (1) "संघ" जैसा संघर्ग के लिये लागूनही होगा। 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके को लाधिकार में संगठन पड़ता है के साध्यम में आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।
[संख्या 1578/एफ.सं. म.नि./आ.क.(छूट)/एम./डी.—11735(1)(ii)]

ग्रार. मिह उप निदेशक

Calcutta, the 28th February, 1996 INCOME TAX

- S.O. 1639.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax (Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Khorakiwala Foundation, BFF|2, Dilkush Industrial Estate, G. T. Karnal Road, Delhi-110033.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-96.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director Ceneral of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1578|F. No. DG-IT(E)|ND-117|35(1)(ii)] R. SINGH, Dy. Director

कलकता 28 फरवरी, 1996

<u>स्राथकर</u>

का. भा. 1640—सर्वमाधारण को एतद्द्वारा स्चित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये श्रायकर नियम के नियम 6 के श्रधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर "संस्थान" के संवर्ग के श्रधीन श्रमीन श्रमीन श्रमीन श्रमीन श्रमीन श्रमीन श्रमीन श्रमीन श्रमीन स्मारी है:——

- (i) संगठन भ्रनुमंधान कार्यों के लिये भ्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह प्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी की यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विनीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व श्रीचोशिक अनुसंधान विभाग, "प्रोचोशिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई विल्ली-110016 को भेजगा, श्रीर
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 श्रक्तूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) श्रायकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, श्रौर (ग) श्रायकर श्रायुक्त/श्रायकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है श्रीर श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परी(क्षत श्राय-ख्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

के.के. बिरला ऐकाडमी, सूर्यी किरण बिल्डिंग (5 तल्ला) 19 कस्तूरवा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

यह अधिसूचना दिनांक 23-12-95 से 31-3-96 तक की प्रविध के निये प्रभावी है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "सघ" जैसा सवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।
 - रांगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदम की श्रवधि बढ़ाने के लिये श्रायकर

भ्रायुक्त/भ्रायकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से भ्रायकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में भ्रावेदन करें, अनुमोदन की भ्रावधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

> [संख्या 1579/एफ.सं. म.नि./ग्रा.क. (छूट) | कल | एन.डी. - 52 | 35 | (1) (ii)] श्रार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 28th February, 1996

INCOME TAX

- S.O. 1640.—It is hereby notified or general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
 - (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
 - of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

K. K. Birla Academy, Surya Kiran Building (5th floor), 19 ,Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

This Notification is effective for the period from 23-12-95 to 31-3-96.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1579]F. No. DG-IT(E) |Cal(ND-52) |35(1) (ii)]

R. SINGH, Dy. Director राजस्व विभाग (श्रादेण)

नई दिल्ली, 17 मई, 1996 स्टास्प

का० न्ना० 1641:— भारतीय स्टाम्प म्रिधितियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) हारा प्रदत्त मितियों का प्रपोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस मुक्क को माफ करनी है जो स्टेट बैंक भ्राफ सौराष्ट्र, भावनगर हारा 15 मार्च, 1996 को म्राबंटित किए गए एक-एक लाख करए भूल्य के मान्न 50 करोड़ क्० के समग्र मूल्य के 000001 से 005000 तक की विभिष्ट संख्या वाले असुरक्षित विभोच्च पूर्णत्या प्रदत्त बांडों के रूप में विणित प्रोमिसरी नोटों की प्रकृति के बंध-पन्नों पर उक्त म्रिधित्यम के तहत प्रभार्य है।

[सं० 37/96-म्टाम्प-फा० सं०-14/1/96-बि० क०]

एस० कुमार, अवर सचिव

DEPARTMENT OF REVENUE ORDER

New Delhi, the 17th May, 1996

STAMPS

S.O. 1641.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as Unsecured Redeemable Fully Paid-up Bonds bearing distinctive numbers 000001 to 005000 of the value of rupees one lakh each aggregating to rupees fifty crodes only allotted to 15th March, 1996 by State Bank of Saurashtra, Bhavnagar are chargeable under he said Act.

[No. 37|96-Stamps-F. No. 14/1/96 ST]

S. KUMAR, Under Secy.

(भाधिक पार्य विभाग) (बैकिग प्रभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 1996

का० ग्रा० 1642:— वैंककारी विनियमन भिधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के नाथ पठिन धारा 53 द्वारा प्रदत्त एकियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की मिफारिश पर घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध सरकारी राज्यव में इस अधिसूचना के प्रका तारीख से 31 मार्च, 1998 तक सहकारी कन्द्रीय बैंक मर्या-दित, दामोह (स० प्र०) पर लागू नहीं होंगे।

[सं० 1(8)/36--ए०सी०]

बी० ए० नारायणन, भ्रवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 20th May, 1996

S. O. 1642.—In exercise of the owers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Damoh (M.P.) from the date of publication of this notification in the Official Gazette to 31st March 1998.

[F. No. 1(8)/96-AC]

B. A. NARAYANAN, Under Secy.

RESERVE BANK OF INDIA CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1643.—In the notification No. 1(9)/96-AC dated. New Delhi the 21st March, 1996, published in the Gazette of India Part II, Section 3(ii) dated 6th April, 1996 vide S.O. 1052, the word "apply" to be added in the fifth line after the words "shall not" and the word "Bondh" to be read as "Boudh" wherever it occur

[No. 07.38.05/95-96]

R. G. PANDAY, Asstt. General Manager

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण भंद्रालय

नर्ष दिल्ली, 14 मई, 1996

का० ग्रा० 1644:—केन्द्रीय सरकार का बिहित प्राधिकारी हारा निबेदित रिपोर्ट (नीचे ग्राझृति देखिए) पर विचार करने के परचात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में विणित माठल बाट और माप मानक ग्राधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माउन का अनुमादन) नियम, 1987 के उपबंधों के ग्रमुख्य है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की ग्राधीय में यथायंता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

भतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 उपधारा (7) द्वारा अवस गक्तियों का अयोग करते हुए, टाइप एस एल उब्ल्यू सी 30 सीरीज वर्ग 3 के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित इलैक्ट्रो-मेकेनिकल तुलाचौकी के माडल का (जिसे इसमें इसके पण्चात गाडल कहा गथा है) जिसका विनिर्माण सैंसर्स इंटीग्रेटेड प्रोसेन प्राटोमेणन, वंगनार द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई०एन०डी०/

09/95/12 समनदिष्य किया गता है, अनुमादन प्रमाणपन प्रकाशित करती है।

माडन (आकृति देखिए) एक मध्यम ययार्थना (यर्थाथना वर्ग 3) का तोजन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 30000 किलोग्राम और न्यनतम क्षमता 200 किलोग्राम है। सत्या-पन मापमान अंतर (ई) 10 किलोग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। भारप्राही आयताकार आकृति का है जिसका पार्श्व 9000 × 3000 मिलीभीटर है। ऐल्फा संख्यांक 3.5 मिलींनीटर आकार के 16 संप्रतीकों का एल सी डी संप्रदर्ण या 13 मिलीमीटर ऊंचे आकार का 7 खंडीय एल ई डी संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 बोल्ट 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है।

आगे, केन्द्रीय सरकार, यह घोषणा करती है कि माडल के अनमीदन के इस प्रमाण एवं के अनर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उमी मिद्धान्त के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनमोदित माङ्गल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 40 टन की अधिकतम क्षमता वाले समस्य मैक, यथार्थता और उसी तिरीज के कार्यकरण वाले लोलन उपकरण भी हैं।



फिल्सिं उब्ल्य ० एम-21 (16)/93] राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव



MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Dilhi, the 14th May, 1996

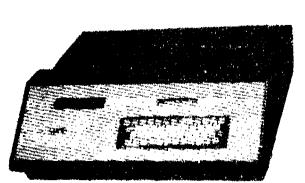
S.O. 1644.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority (see figure below) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating non-automatic electro-mechanical weighbridge of type SLWC-30 series of class III with brand name "IPA" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M's. Integrated Process Automation, 472 B2, 12th Cross, IV Phase, Peenya Ind Area, Bangalore-560058, and which is assigned the approval mark IND[00]95]12.

The model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 30000 kg and minimum capacity of 200 kg. The verification scale interval (e) is 10 kilogram. It has a tare device

with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangle shape of sides 9000×3000 milimetres. The alpha numeric LCD display of character size 13 milimetre height indicates the weighing result. The instrument optrates on 230 volts, 50 Herts alternate current power supply.

Further in exercise of the powers conferred by subsection (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 40 time manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.





[File No. WM 21(16)/93] RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

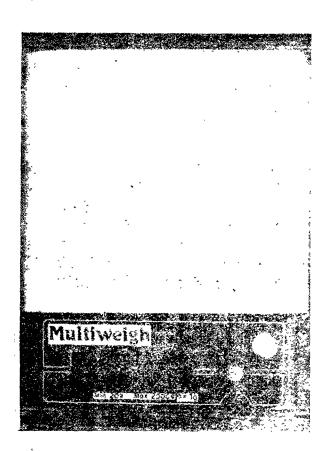
नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का०आ०. 1645. — केन्द्रीय सरकार का बिह्त प्राधिकारी द्वारा निवेदित रिपोर्ट (नीचे आकृति देखए) पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में विणत माइल बाट और माप मानक अधिनयम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माइल का अनुसोदन) जियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थना बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 उपधारा (7) द्वारा प्रवत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए मस्टी-के-एस टी एस 2000 टाइप के स्वतः सूचक गैर-स्व- चालित तोलन उपकरण के माडल का (जिसे इसमें इसके पण्चात् माडन कहा गया है) जिसका विनिर्माण में सर्स इंटी-ग्रेटेड प्रोमस आटोमेशन, डिवाइस साइट नं० 17, एस आर वाई नं० 43/1, हस्मरगटटा गाड, बंगलीर द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिहन आई०एन०डी०/09/94/43 समनुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्न प्रकाणित करती है।

माडल (आकृति देखिए) एक गध्यम (यर्थाथता वर्ग 3) का तीलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 2 किलोग्राम और न्युनतम क्षमता 20 ग्राम है। सत्थापन मापमान अंतर (ई) 1 ग्राम है। इसमें एक देथर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण देयर प्रभाव 100 प्रतिणत है। भारगाही आयताकार आकृति का है जिसका पार्श्व 150 मिलीमीटर है। यह 13 मिलीमीटर आकार का चार खंडीय संप्रतीक प्रकाण उत्सर्जन हायोड संप्रदर्श तील परिणाम उपविणत करता

है । यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है ।



[फा॰सं॰ डब्ल्यू॰ एस 21(49)/92] राजीव श्रीत्रास्तव, संयुक्त सांचव

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1645.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic weighting instrument of type Multi weight-LTS 2000 (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Integrated Process Automation Devices, Site No. 17, SRY No. 43/1, Hassergatta Road, Bangalore, and which is assigned the approval mark IND109/94/43;

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 2 kilogram and minimum capacity of 20 gram. The verification scale interval (e) is 1 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of square shape of side 150 millimetre. The four segment LED display of character size 13 millimetre 1292 GI/36—9.

indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.



[F. No. WH-21(49)/9] RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

(नागरिक पूर्ति विभाग) नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का०आ० 1646. — केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 36 की उपधारा (7) और (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंद्वालय की अधिसूचना संख्यांक का०आ० 2751 तारीख 29 सितम्बर, 1994 का आंशिक उपांतरण करते हुए उक्त अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नालिखत संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 के हिन्दी पाठ में,

 (i) "एम-25" अक्षर और अंकों से पूर्व निम्नलिखित शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:---

"एम एस-7"

(ii) "एम-75" अक्षर और अकों के स्थान पर "एम एस-75" अक्षर और अंक रखे जाएंगे। [फाइल सं० डब्ल्यू 21(63)/95] राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1646.—In exercise of the powers conferred by subsections (7) and (12) of Section 36 of the Standards of Weights and Mearures Act, 1976 (60 of 1976), and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution number S.O. 2751 dated the 29th September, 1994, the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification, namely:—

In the said notification, in paragraph 3,

(i) before the letter and figures 'H-25', the following words and figures shall be inserted, namely:—

"MS-7"

(ii) for the letter and figures "M-75" the letters and figures "MS-75", shall be substituted.

[File No. WM-21(63)/95] RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

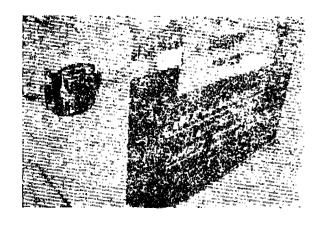
नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का॰आ॰.1647.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी हारा निवेदित विपोर्ट (नीचे आवृति देखिए) पर धिचार करने के पश्चात्, रामाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में विणित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप भानक (भाडल का अनुभोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थिनियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथार्थता दर्ग 3 की "इ डस्कृ एस" टाइप के स्थतः स्वक गैर-स्थवालित यांतिक तुला चौकी के माडल का (जिसे इसमें इसके पण्यात माडल कहा गया है) जिसका विभिन्नीण मैसर्स ईगल वेइंग सिस्टप्राइ वेट लिनिटेड, नाना विलीवा चार रास्ता, एन आर शंजय न र हिम्मत नगर हाईवे, सं० 8, नरोबा, अहमताबाद द्वारा किया गया है और जिसे अनुशोदन चिहन आई०एन०डी०/09/95/35 अम्मुदिस्ट किया गया है, अनुभोदन प्रमाणपत्न प्रवाशित वारती है।

माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) यांत्रिकी तुला चीकी है जिसकी अधिकतम क्षमता 3000 जिलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 20 किलोग्राम है। सत्यापन मापगान अंतर (ई) 1 किलोग्राम है। आधार और प्लटफार्म धार्तिक है। मारग्राही आयताकार आकृति का है जिसका पार्ग्व 1500×1800 मिलीमीटर है। यह स्टीतआई तोल परिणाम उपदिंगत करता है।

आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती हैं कि माइल के अनुष्मोधन के इस प्रमाण पत्न के अंतर्गत उसी विनिर्भाता द्वारा उसी विद्वान्त के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुभोधित माइल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 3 टन, 5 टन, 20 टन, 25 टन, 30 टन, 40 टन, 50 टन, 60 टन और 100 टन की अधिकतम क्षमता वाले समस्प भैक, यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण वाले तीक्षन उपकरण भी हैं।





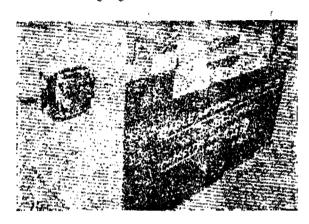
[फा॰सं॰ डब्ल्यू॰एम 21(2)/94] राजीय श्रीास्तव, संयुक्त मचित्र

New Delhi, the 14th May, 1996

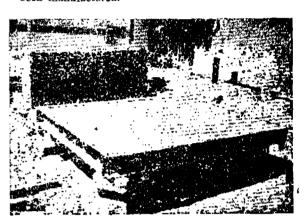
S.O. 1647.—Whereas the Centra Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report, see figure given below, is a conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60) of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government herey publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic mechanical weighbridge of type "EWS" of accuracy class III (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Eagle Weighing System Pvt. Ltd., Nana Chiloda Char Rastn, Nr. Sanjay Nagar, Himmatnagar Highway, No. 8, Naroda, Ahmedabad and which is assigned the approval mark IND 09/95/35;

The Model (seen figure) is a medium accuracy (accuracy class III) mechanical weighbridge with a maximum capacity of 3000 kilogram and minimum capacity of 20 kilogram. The verification scale interval (e) is 1 kilogram. The base and the platform are metalic. The load receptor is of rectangle shape of sides 1500×1800 millimetre. The steel yard indicates the weighing result.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said Section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance with a maximum capacity of 3t, 5t, 20t, 25t, 30t, 40t. 50t, 60t and 100t manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.



[F. No. WM-21(2)/94] RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

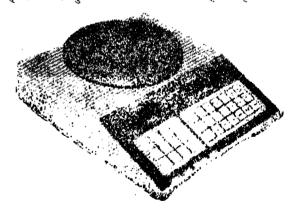
नई दिल्ली, 16 मई, 1996

काठआंठ. 1648.— केन्द्रीय सरकार की बिहित प्राधिकारी हारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में विणित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अगुभोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अगुरूप है और इस बात की संभावना है कि उक्त माडल लगातार प्रयोग की अयधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त मेला देता रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त आंधिनियम की धारा 30 उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त कित्यों का प्रयोग करते हुए, मध्यम यथार्थता वर्ग 3 के एम०टी-5 सीरीज के और आई० पी०ए० ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वाजाित इलेक्ट्रानिक टेबल टाप, पेस्टल तोजन मशीन के काडल का (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैंसर्स आई०पी०ए० डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, 464, चतुर्थ फेज, पीनिया इन्डस्ट्रीयल एरिया बंगलौर-560058 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन विहन आई०एन०डी०/09/95/23 समनुदेशित किया गया है, अनुभोदन प्रदाणपत प्रकाशित करती है:

माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यर्थायता (यर्थायता वर्ग 3) का इलैक्ट्रानिक टेबल टाप पोस्टल तोलन उपकरण हैजिसकी अधिकतम क्षमता 5 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता

20 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 1 ग्राम है।
13 मि०मी० ऊंचाई का 7 खंडीय (4 अंकों) प्रकाश उत्सर्जन
डायोड अंकीय संप्रदर्श तोज परिणाम उपदिशत करता है।
भारग्राही गोल आकृति का धात्मिक पलडा (पेन) है जिसका
व्यास 200 मि०मी० है। यह उपकरण 230 बोल्ट, 50
हर्टज के नियुत प्रवाय पर प्रचालित होता है।



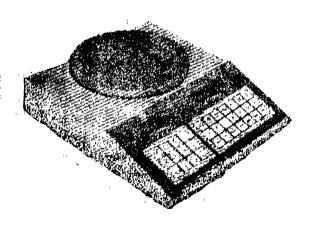
आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) हारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माउन के अनुभोदन के इस प्रमाण पत्न के अंतर्गत उसी विनिर्माता हारा उसी सिद्धान्त डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुभोदित माउन का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 2 किलोग्राम की अधिकत्तम क्षमता वाले समस्य भंज, यथार्थता और एम०टी० सिरीज के कार्य-करण वाले तौजन उपकरण भी है।

[फा०उं० डब्स्यू० एम 21(48)/94] राजीय श्रीवास्तव, संयुक्त सर्विक Now De!hi, the 16th May, 1996

S.O. 1648.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic electronic table top postal weighing machine of series MT-5" series of class III Medium accuracy and with brand name "IPA" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. IPA Devices Pvt. Ltd.. No. D1,464, IV Phase, Pcenya Ind. Area, Bangalore-560058, and which is assigned the approval mark IND/09/95/23;

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) electronic table top postal weighing instrument with a maximum capacity of 5 kg and minimum capacity of 20 gram. The verification scale interval (e) is 1 g. The 7 segment (4 digits) I.ED digital display of 13 mm height indicates the weighing result. The load receptor is a metalic pan of round shape of diametre 200 mm. The instrument works on 280 volts 50 fierz power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby dec-

lores that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of MT-2 series with maximum capacity of 2kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(48)|94] RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy

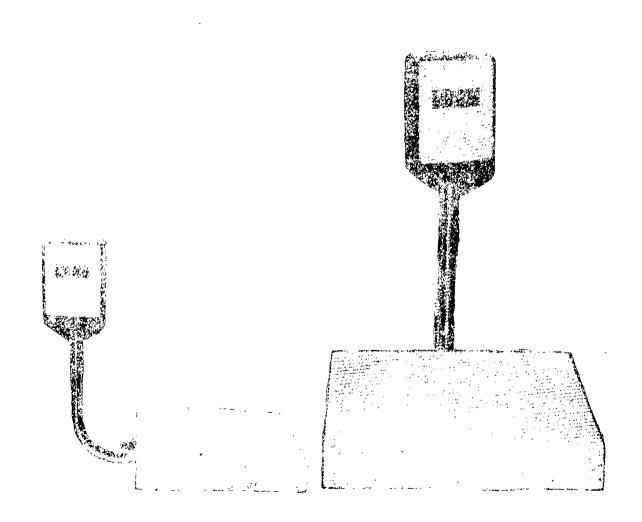
नई बिल्ली, 16 मई, 1996

कार आर. 1649. — केन्द्रीय सरकार की विश्वित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पण्चात्, सभाधात हो गया है कि उनत रिपोर्ट में विणत माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का धनुभोदन) नियम, 1987 के उनवंगों के प्रमुख्य है और इस बात की संभावना है कि उनत माउन नगातार प्रयोग की ध्रविध में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त मेया देता रहेगा।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 उपधारा (7) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गध्यम यक्षार्थता वर्ग 3 के ''टी॰यी॰सि॰ 20 कूट कीरीज के और आई पी ए'' बांड नाम बाले स्वतः सूचक गैर-स्यचालित जॉलन मगीन के माडल का (जिमे इसनें इसके पश्यात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स आई पी ए डिवासेस प्राइयेट लिमिटड, 464, चतुर्थ फेंग्र, पीनिया इर्डर्ड्रायल एरिया बंगलौर-560058 हारा किया गमा है ओर िने अनुनीयन पिह्न आई० एन॰ डी॰/09/95/24 समतुर्देशित किया गमा है, अनुमोदन प्रमाणपत्न प्रकाशित करती है;

माङान (श्राकृति देश्विए) एक मध्यम यथार्थता (यथियता वर्ग 3) का इलेक्ट्रानिक टेबल टाप लवान दोहरा तीलन उपकरण है। जिलकी श्रीधकतम क्षमता 20 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है। सभ्यापन मापमान ग्रन्तर (ई) 2 किलोग्राम तक 5 ग्राम और 2 किलोग्राम में ऊपर 10 ग्राम है। श्राधार और प्लेटफार्म मृबु इस्पात के हैं। 7 खेंडीय (4 अंकों) 13 मि०मी० ऊंचा प्रकाण उत्सर्जन डायोड संग्रदर्श 18 मि०मी० ऊंचा एस. सी. की. संग्रदेश

तील परिणाम उपदर्शित करना है। भारप्राही बगांकार ब्राकृति का धारिवक पलड़ा (पन) है जिल्हा पार्क 300 विज्ञी है । यह उपकरण 230 योल्ट, 50 हर्टज विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है।



[का०सं० डब्ल्यू०एम० 21(48)/94] राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचित्र

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1649.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in he said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

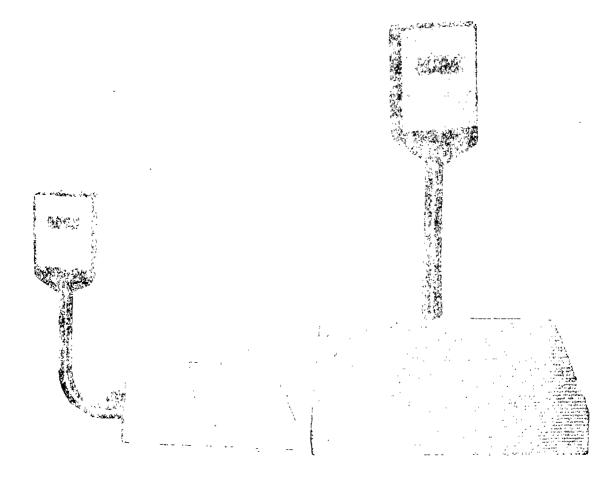
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central

Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic electronic table top loading weighing machine of series 'TBC-20 Cute' series of class III Medium accuracy and with brand name "IPA" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. IPA Devices Pvt. Ltd., 464, IV Phase, Peenya Ind Area, Bangalore-560058, and which is assigned the approval mark IND|09|95/24;

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) electronic table top loading dual weighing instrument with a maximum capacity of 20 kg and minimum capacity of 100 gram. The verification scale interval (e) is 5 g upto 2 kg and 10 g above 2 kg. The 7 segment (4)

digits) LED digital display of 13 mm height/LCD display of 18 mm height indicates the weighing result. The load

receptor is a metallic pan of square shape of side 300 mm. The instrument works on 230 volts 50 hertz power supply.



[F. No. WM-21(48)/94] RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

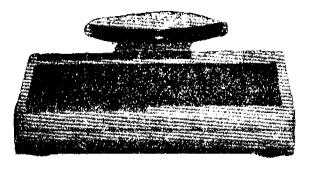
नई दिल्ली, 16 मई, 1996

काञ्या 1650. — केन्द्रीय सरकार की विहित प्रधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुन की गई रिपोर्ट पर विवार करने के समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक प्रधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुभोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि उक्त माडल लगातार प्रयोग की श्रविध में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

ग्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त ग्रधिनियम की धारा 36 उप-धारा (7) और उपधारा 8 द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यम यथार्थता वर्ग 2 का 2 जे०ई-0300 टाईप के अंकीय संप्रदर्ग वाले स्वतः सूचक और स्वचालित टेबब टाप तोलन जपकरण के भाइल का (जिते इतने इसके पश्लान माइल कहा निया है) जित का जितिमाण में कर्रा जीव एमव ग्राईव डिजीटल इतेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट निर्मिटेड, प्रत्य सदन, मैक्टर—4, क्योजी रोड, परवानू—173220, द्वारा जिला गया है और जिते अनुमोवन विन्ह ग्राईवएनवडीव/09/95/37 समतुद्दणिन किया गया है अनुभोदन, प्रमाण-पद्ध प्रकाशित करती है;

माङ्ग (आकृति वे लिए) एक उच्च यथियता (अर्थायता वर्ष 2) का टेबल टाप तोलग उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 300 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 मि० ग्राम है। सत्थापन मापमान असर (ई) 10 मि० ग्रा० है। इसमें एक टेयर युनित है जिन्नका व्यक्तनात्सक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100, प्रतिशत है। आधार और भारप्राही धात्विक हैं। भारप्राही वृत्ताकार आकृति का है जिसका अर्थव्यास 200 मि० मी० है। प्रकाश उत्थान डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपर्यात करता है। यह उपकरण 230 बोल्ट,

50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा निख्त प्रदान पर प्रकातित होता है या (बी० डी० सी० पेंटरी पर प्रचानित होता है।



श्रागे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) हारा प्रवक्त मिक्कां का प्रयोग करने हुए, यह घोषणा करनी है कि माइल के अनुगोदन के इस प्रमाण पत्न के अंनर्गत उसी विनिर्माला द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुभार बंदि उसी सामग्री से, जिससे अनुभोदित माइल का जिनिर्माण किया गया है जिनिर्मित 150 ग्राम/5 मि० ग्राम, 3000 ग्राम/100 मि० ग्राम, की अधिकतम क्षत्रना थाले और 2 एस एल सिरीज के 550 ग्राम/50 मि० ग्राम०, 1100 ग्राम/100 मि० ग्राम, 2200 ग्राम/200 कि० ग्राम 5500 ग्राम/500 मि० ग्राम, 550 ग्राम/50 कि० ग्राम, 11 किलोग्राम/1 ग्राम, 22 किलोग्राम/2 ग्राम, 30 किलोग्राम/2 ग्राम की श्रिधकतम क्षमता वाले समरूप भैक, यथार्थता और उसी सीरीज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरणभी है।

[फा०सं० डब्ल्यू० एम 21(68)/94] राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

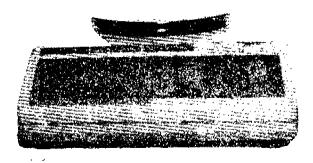
New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1650.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report, (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating non-automatic table top weighing instrument with digital display of type 2 JE 0300 of accuracy class II (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. GMI Digital Electronics Pvt. Ltd., Adhar Sadan, Sector-4, Kasauli Road, Parwanoo-173220 and which is assigned the approval mark IND 09/95/37;

The Model (see figure) is a high accuracy (accuracy class II) table top weighing instrument with a maximum capacity of 300 gram and minimum capacity of 200 milligram. The verification scale interval (c) is 10 milligram. It has a tage device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base and the load receptor are metallic. The load receptor is of circular shape of radius 200 milli-

me're. The LCD display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply or 6 V D.C. battery.



Further, in exercise of the powers conferred by Subsection (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance with a maximum capacity of 150 g/5 mg, 3000 g/100 mg, and of 2 SL series with the maximum capacity of 550 g/50 mg, 1100 g/100 mg, 2200 g/200 mg, 5500 g/500 mg, 11 kg/1 g, 22 kg/2 g and 30 kg/2 g manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(68)/94]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

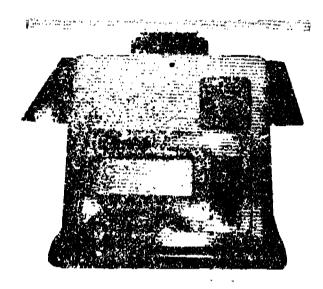
नई दिल्ली, 16 मई, 1996

का० आ०1651——केन्द्रीय सरकार की विहित्त प्राधिकारी बारा उसे प्रस्तुन की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में विणित माउल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुभोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि उक्त माडल लगातार प्रयोग की अवधि यथार्थता बनाए रखेगा और विकिन्न परिस्थितियों में उपयक्त सेवा देता रहेगा;

श्रवः, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथियता वर्ग 3 के 3 जी अगर 005 टाइप के अंकीय संप्रदेश वाले स्वतः सूजक गैर-स्वचालित प्लटफार्म तोंलन उपकरण के साइत का (जिसे इसमें इसके पश्चात माइल कहा गया है (जिसको विनिर्माण मैसर्स जी ०एम० ग्राई० डिजीटल इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिगिटड, ग्रक्षर सदन, सैक्टर-4, कसोली रोड, परवानू-173220 द्वारा किया गया है और जिसे प्रानुभोदन जिन्ह आई० एन० डी०/09/95/38 समनुदेशित विया गया है. अनुभोदन प्रमाणपत्र प्रवाधित करती है;

माउल (श्राकृति देखिए) एक मध्यम यर्थाथता (सर्थाथता वर्ग 3) का प्तेटकार्भ तंत्र्यन उपकरण है जिसकी श्रधिकतम क्षमता 5000 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है।

सत्वापन मापमान फ्रान्ट (ई) 2 ग्राम है। इसमें एक देवर युक्त है जिसका व्यकलनात्सक प्रतिधारण देवर प्रभाव 100 प्रतिशन है। प्राधार और भारप्राही धात्वक है। प्राधार और भारप्राही धात्वक है। प्राप्याही प्राधानकार आकृति का है जितका पार्क 600×500 मि० भी० है। प्रभाग उन्तर्जन डायोड संप्रदर्श तोज परिणाम उपवित्त करता है। यह उपकरण 230 वील्ट, 50 हुई: के प्रत्यावनी भाग विद्युत प्रवाद पर प्रवालित होता है था 6 वी० डी० सी० बैटरी पर प्रवालित होता है।



श्रागे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के श्रनुभोदन के इस प्रमाण पत्न के अंतर्गन उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के श्रनुसार और उसी मामग्री से, जिससे श्रनुभोदित माडल का विनिर्माण किया गया है। यिनिर्मित 2 किलोग्राम/1 ग्राम, 4 किलोग्राम/2 ग्राम, 10 किलोग्राम/5 ग्राम, और 20 किलोग्राम/100 ग्राम की श्रिधकतम झमता वाल समस्य भैक, यथार्थना और कार्य-करण वाले तोलन उपकरण भी है।

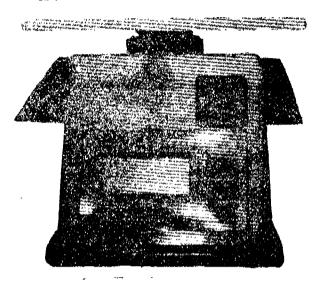
[फा॰ मं॰ डब्ल्यू॰एम 21(68)/94] राजीव श्रीवारतव, संयुक्त मचिव

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1651.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report, (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating non-automatic platform weighing instrument with digital display of type 3 GR 005 K of accuracy class III (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. GMI Digital Electronics Pvt. Ltd., Adhar Sadan, Sector-4, Kasauli Read, Parwanoo-173220, and which is assigned the approval mark IND|09/95/38;

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) platform weighing instrument with a maximum capacity of 5000 gram and minimum capacity of 40 gram. The verification scale interval (e) is 2 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base and the load receptor are metallic. The load receptor is of rectangular shape of sides 609 × 500 millimetre. The LCD display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 heriz alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by subsection (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance with a maximum capacity of 2 kg/1 g, 4 kg/2 g, 10 kg/5 g and 20 kg/10 g manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(68)/94] RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

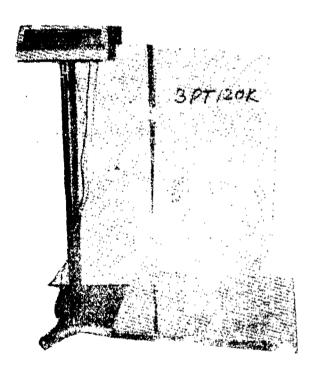
गई दिल्ली, 16 मई, 1996

का०सा०1652. — नेन्द्रीय सरकार की विहित प्राधिकारी द्वारा निषेदित रिपोर्ट नीचे आकृति देखिए पर विचार करने के पश्चात समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में विणित साडल बाट और गाप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (भाडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपवंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की धवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त मेवा देशा रहेगा;

श्रवः केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधिनियम की धारा 36 उपतारा (7) ढारा श्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यम स्थार्थना वर्ग 3 की ''के 3 पी०टी-120'' सीरीज टाइप के और 'जी एस आई-स्केट्स'' ट्रेडमार्क वाले अंकीय संप्रद स्वतः सूचक गैर-स्वचालित इन्वेट्टानिक प्लेटफार्म तोलग उपकरण के माइल का (जिसे इनमें इनके परचात माइल कहा गया है) जिसका विनिर्वाण नैपर्न थे। एस आई अंकीय इलस्ट्रोजिक्स शाइवेट जिमिटेड, आधार राइन, सेक्टर-4 ससाली रोड, परवान-1732280 ढारा किया गया है और जिसे श्रवमोदन चिह्न शाई जान जी०/

09/95/59 समनुदेणित किया गया है, ग्रन्भोदम प्रभाणपव प्रकाणित करती है।

माइल (ब्राकुति देखिए) एक मध्यम यसार्थना (तथार्थना वर्ग 3) का दोहरी हैं। प्तेटकार्ध तोलन उपकरण है जिलकी ब्रिधिकतम क्षमता 120 किलोग्राम और स्यूनतम क्षमता 200 ग्राम है। स्व्यापन मापसान अंतर (ई) 6 किलोग्राम तक, 10 और 6 किलोग्राम में उत्तर 20ग्राम है। इसमें एक देगर युक्ति है जिलका व्यक्तनात्मक प्रतिधारण देगर प्रभाव 100 प्रतिणत हे। श्राधार और प्लेटफार्म धात्विक है। भारग्राही ग्राधनाकार भेक्सन का है जिसके पार्थ 500×600 मिलीमीटर है। प्रकाण उत्मर्जन हायोग्र संप्रदर्श तोव परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 बोल्ट, 50 हुई के के प्रत्यावतीं धारा विध्न प्रदाय पर प्रवालित होता है।



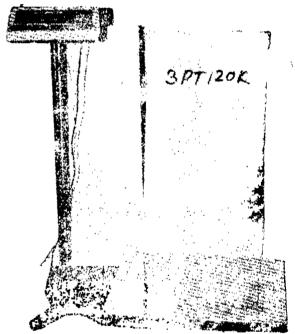
श्रागे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदम्म शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माइल के अनुसोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माइल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 30 किलोग्राम/5 ग्राम, 60 किलोग्राम/10 ग्राम, 120 किलोग्राम/20 ग्राम, 300 किलोग्राम/50/ग्राम, 600 किलोग्राम/100 ग्राम और 1000 किलोग्राम/200 ग्राम की, श्रीधकतम धमना और (ई) मान वाले समस्य मेक, यथार्थता और उसी सीरीज के कार्यकरण बाले तोलन उपकरण भी है।

[फा० सं० डब्ल्यू० एम-21(65)/94] राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1652.—Whereas the Central Government considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report, (see the figure given below), is in conformity with the provision of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic electronic platform weighing instrument with digital display of type "3-PT 120 K" series of class III medium accuracy and with the trade mark "GMI-Scales" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. GMI Digital Electronics Pvt. Ltd., Adhar Sadan, Sector-4, Sasauli Road, Parwanoo-173220, and which is assigned the approval mark IND/09/95159.

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) Dual range platform weighing instrument with a maximum capacity of 120 kg and minimum capacity of 200 g. The verification scale interval (e) is 10 g upto 6 kg and 20 g above 6 kg. It has a tare device with a 100 percent substractive retained tare effect. The base and the platform are metallic. The load receptor is of rectangular section of sides 500×600 millimetre. The LCD display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply.



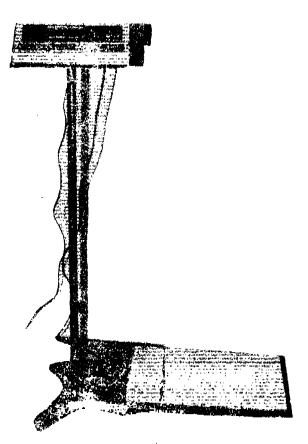
Further, in exercise of the powers conferred by subsection (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make. accuracy and performance of same series with maximum capacity and 'e' value of 30 kg/5 g, 60 kg/10 g, 120 kg/20 g, 300 kg/50 g, 600 kg/100 g and 1000 kg/200 g, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM-21(65)/94] RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

न कि. 1996

कार्यभार 1653 — केन्द्रीय भरकार का विहित प्राधिकारी हारा निवेदित रिपोर्ट (भींचे आकृति देखिए) पर विकार करंग के पण्यात, समागत हो गया है कि इक्त रिपोर्ट में विणित माइल बाट ऑप मान मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट औप माप मानक (भाइत का अन्मोदन) निगम, 1987 के उपत्रधों के यनुष्ट्रप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अविधि में यथार्थना बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थिनियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, अव लेन्द्रीय मरकार, उक्त श्राविनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदन्त णक्तियों का प्रयोग करने हुए, उच्च यथायता वर्ग 2 की "2 पी टी 060 के" मिरीज टाइप के और जीएस ग्राई ट्रेडमार्फ वाले अंकीय संप्रदर्ग वाले स्वयः सूचक गैर-स्वधानिक इलेक्ट्रोनिक प्लेटफाने वेलिन उपकरण के साइल का (जिने इसमें इसके पण्चात् माइल कहा गना है) जिसका विनिर्भाण मनर्स जी एस ग्राई अंकीय इलेक्ट्रोनिस्प प्राइवेड लिभिटेड, ग्राधार राष्ट्रमा, सैनटर-म. समौली रोड, परनान्-173220 डारा किया गया है और जिसे श्रमुमोदन चिन्ह ग्राई० एक० डी०/09/95/60 समन्दिष्ट किया गया है. भन्मोदन ग्रमाणपद्य प्रकाशित करनी है।



2 PT 060K

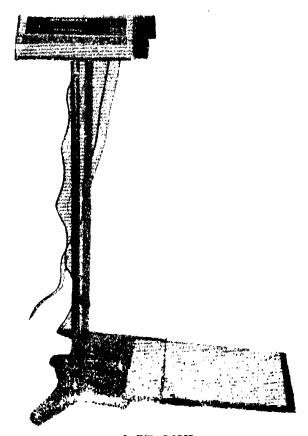
माङल (ब्राक्टित देखिए) एक उच्च (गर्याधता वर्ग 2) का प्लेटफार्म तोलन उपकरण है जिसकी श्रधिकतम क्षमता 60 किलोग्रीम और त्यूनतम क्षमता 250 ग्राम है । सत्यापन भाषपान नंतर (१) ५ गांग है। इसमें एक देवर पुनित हैं जिसका व्यक्तनातमक प्रतिधारण देवर प्रमास 100 प्रतिशत है। प्राधार और जंदफार्म धारिमक है। भारपाही प्राधताकार पेक्षम का है जिसके पार्च 500% 500 मिलीकीटर है। प्रशास उपमान दायाड सप्रदर्भ भील परिणाम उपदर्शित करना है। यह उपकरण 230 बोल्ट, 50 हर्टन के प्रत्यावनी धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचानित होता है।

[फा॰ गं॰ डक्व्यू॰एम 21(65)/94] राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त मचिव

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1653.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report, (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic electronic platform weighing instrument with digital display of type "2-P1 060 k" series of class II high accuracy and with the trade mark "GMI-Scales" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M.s. GMI Digital Electronics Pvt. Ltd., Adhar Sadan, Sector-4, Sasauli Road, Parwanoo-173220, and which is assigned the approval mark IND/09/95/60.



2 PT 060K

The Model (see figure) is a high acturacy (accuracy class II) platform weighing instrument with a maximum capacity

of 60 kg and minimum capacity of 250 g. The verification scale interval (c) is 5 g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The base and the platform are metallic. The load receptor is of rectangular section of sides 500×600 millimetre. The LCD display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply.

[File No. WM-21(65) '94] RAJIV SRIVASTAVA, II. Secy.

नई दिल्का, 21 मई, 1996

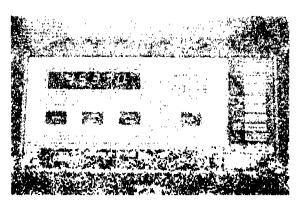
नारपार 1654 - किरोय संख्यान की विश्वित प्राधिकारी आग निर्वेदिस रिपोर्ट पर विनार करने के पश्चल समाधान है। उसता है कि उना रिपोर्ट में विणित माइल (निर्चे प्राकृति देखिए) बाट और माण मानक प्रधितियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और भाष मानक (माइल का प्रसुपेदन) निपम 1987 के उपवंधों के प्रनुस्प हैं और इस बात की संमावना है कि वह लगानार प्रयोग की प्रविधियों में अप्युक्त सेवा बेताए रुवेगा और विभिन्न परिस्थितियों में अप्युक्त सेवा देता रहेगा।

श्रव. अब केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिश्चियम की धारा 36 की उनधारा (7) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भैसर्च ऐगवी निस्टम प्रा० लिए भी-64, ओजवा इंड्सिट्स्यल एरिया, फेजे-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा विनिधित नवयं सुफ्री, अस्वत. चालिन इलेक्ट्रोनिक तुलन सेत् जिसपर वर्ग 3 यर्थायता के साथ "एणवी" टाटर और ब्रांड नाम का अंकीय प्रदर्शन होगा और जिसे ईट/09/95/39 अपुनीरन जिल्ह् समन्दिष्ट किया गया है, के अनुनीदन का प्रमाणका प्रकारित करती है।

यह माडल (आकृति देहिल्) भजन (वर्गावत वर्ग 3) का इलैक्ट्रोनिम लूलन से हि जिसकी अधिकतन अगला 50,000 किलोग्रःम और ल्लानम धमला 100 किलोग्रःम है। सत्यापन अनुमापी अवराज 5 किलोग्रःम है। इसमें आग्नेय लूलन युक्ति है जिनमें गत्रप्रिणा व्यवकलनात्मक प्रति-धारित आग्नेय लूलन प्रभाव है। भारप्राही आग्नाकार आकार का है जिसकी मुजाए 1,000 × 3000 सिलीमीटर की है। इसमें 6 सुजना लैंड प्रदर्शन से लूलन परिणाम उपद्यान होगा। यह उपकरण 230 बोल्ट/50 हुईज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रयाप पर प्रकालन होगा।

और बहु कि केली। सरकार उक्त प्राराविक उपवास (12) इस्ट प्रदेश मिलो। का प्रवास करते हुई, यह मेंस्पिक करती है कि इस माइल के अनुष्वादन के इस प्रमाण पर के अंचयन उसी मैंके, यथार्थना और निव्यादन के अन्य तुप्तन यह भी हींगे भिनकी अजिकतम क्षमता 30 दन, 40 दन, 50 दन, और 60 दन है जार जो उसी जितिनीता है सा उन्हों निद्धाली, डिजाइन और उसी भागजी से विनिधित किये दाने हैं जिनके अनुसार अनुभोदन माइल जिनिस्ति किया गया है।





(সঞ্জেনি)

[फा॰ রাঁ০ উজ্পুত শূম-21(19)/93] रাজीव श्रीवारतव, संमुक्त मधिय

New Delhi, the 21st May, 1996

S.O. 1654.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of susteined use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers contribed by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central

Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic electronic weighbridge with digital display of type and brand name "ashbee" of accuracy class HI thereinafter referred to as the Model) manufactured by M s. Ashbee System Pvt. Ltd., C-64, Okhla Industrial Area, Phase t, New Delhi-110020, and which is assigned the approved mark 1ND 09 95 39;

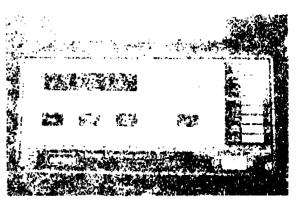
The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) electronic weighbridge with a maximum capacity of 50000 hilogram and minimum capacity of 100 kilogram. In verification scale interval (e) is 5 hilogram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained fare

effect. The load receptor is of rectangule shape of sides 14000×3000 millimetre. The 6 segment LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the sald section, the Central Government hereby

effect. The load receptor is of rectanle shape of sides also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance with a maximum capacity of 30t, 40t, 50t and 60t manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.





[F. No. WM-21(49), 94] RAHV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

भारत मौसम विज्ञान विभाग

(मौसम विशान के महानिदेशक का कार्यालय)

श द्धि पत्न

नई दिल्ली, 23 मई, 1996

का. ग्रा. 1655. — भागत के राजपत्न के भाग-II खण्ड 3(ii) में दिनांक 16-3-1991 को पृष्ठ सं० 1309—1310 पर (भाग II) सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग"—वैज्ञानिक सहायक, श्राणुलिपिक श्रेणी-2, पुम्तकालयाध्यक्ष, प्रद्यान लिपिक, हिन्दी श्रनुवादक श्रेणी-1 श्रोर श्रेणी-2, प्रणासनिक महायक, सुरक्षा निरीक्षक प्रकाशित भारत सरकार (भारत मौसम विज्ञान विभाग) की दिनांक 4-3-1991 की प्रधिसूचना सं. 790 के साथ संलग्न श्रनुसूची के कालम सं. 3, पंक्ति 4 (सभी णास्तियां श्रिधरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी) के श्रन्तगंत मुद्ध करके

"मोसम विज्ञान ग्रंपरमहानिदेशक (अनुसंधान) ग्राँर मोसम विज्ञान ग्रंपरमहानिदेशक (कृषि मौसम) पुणे स्थित कार्यालयों में मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक तथा मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक जो कार्यालयों/प्रादेशिक मौसम विज्ञान केन्द्रों के प्रधान के रूप में कार्यरत हों, ग्रंपते-ग्रंपने स्थापनों में धारित पदों के लिए" पढें यथा:---

''मौसम विज्ञान श्रपरमहानिदेशक (ग्रनुसंधान), पुणे स्थित कार्यालय में सौसम विज्ञान उपमहानिदेशक तथा मौसम विज्ञान उपमहानिदेणक जो कार्यालयो/प्रादेशिक भौसम विज्ञान केन्द्रों के प्रधान के रूप में कार्यरत हों, अपने-अपने स्थापनों में धारित पदों के लिए

2. भारत के राजपन्न के भाग II, खण्ड 3(ii) में दिनांक 25-2-1995 को पुष्ठ सं. 626 में प्रकाणित भारत सरकार (भारत मौसम विज्ञान विभाग) की दिनांक 3-2-1985 णृद्धिपन की प्रिस्त्र्वना सं. 516 के साथ पास्न प्रनुस्त्री की पंक्ति 16 धीर 30 के अंतर्गत में मुद्ध करके

"मौसम विज्ञान अपरमहानिदेशक (अनुमधान) श्रांर मौसम विज्ञान अपरमहानिदेशक (कृषि मौमन) पुण स्थित कार्यालयों में मौसम विज्ञान उत्तमहानिदेशक, तथा मौसम विज्ञान उत्तमहानिदेशक जो कार्यालयों/प्रादेशिक सौसम विज्ञान केन्द्रों के प्रजान के रूप में कार्यर हों., अपन-अपने स्थापनों में द्यारित पदों के लिए" पहें यथा:—

"मीसम विज्ञान श्रवण्महानिदेशक (श्रतुसंधान), पुणे स्थित कार्यालय में मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक तथा मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक जो कार्यालयों/प्रादेशिक मौसम विज्ञान केन्द्रों के प्रवान के रूप में कार्यण्त हो, श्रयने-श्रयने स्थापनों में धारित पदों के लिए"

> [सं. बो--00101/4/ए] बी.के. चीपड़ा, मोलग विज्ञानी श्रेड-1 (विजि.) कृत मौसम विज्ञान, महानिदेणक

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

(Office of the Director General of Meteorology)

CORRIGENDA

New Delhi, the 23rd May, 1996

S.O. 1655.—Under col. 3, Ine is (Authorities Competent to impose all penalties) in the Schedule annexed to the Govt, of India (India Meteorological Department) Notification No. dated 4-3-1991 published in the Gazetted of India, Part II, Section 3(ii) dated 16-3-1991 on PP. 1313 (Part II General Central Service-Group *C---Scientific Assistant, Stonographer Grade-II, Librarian, Head Clerk, Hindi Translator Grade-L and Grade-II. Administrative Assistant. Security Inspector)-replace "Deputy Director General of Meteorology in the Office of the Additional Directer General of Meteorology (Research) and Additonal Director General of Meteorology (Agrimet) Pune and Deputy Director General of Meteorology working as Head of the Offices Regional Meteorological Centres for posts in their respective establisments".

By

"Deputy Director General of Meteorology in the Office of the Additional Director General of Meteorology (Research), Pune and Deputy Directors General of Meteorology working as Heads of the Offices Regional Meteorological Centres for posts in their respective establishments.".

2. Under line 5 & 20 to the corrigenda annexed to the Government of India (India Meteorological Department) Notification No. 516 dated 3-2-1995 published in the Gazette of India, Part II. Section 3(ii) No. 8 dated 25-2-1995 on PP. 627 replace "Deputy Director General of Meteorology in the Offices of the Additional Director General of Meteorology (Research) and Additional Director General of Meteorology (Agrimet), Pune and Deputy Director General of Meteorology working and Head of the Offices Regional Meteorological Centres for posts in their respective establishment".

By

"Deputy Director General of Meteorology in the Office of the Additional Director General of Meteorology (Research), Pune and Deputy Director General of Meteorology working as Head of the Offices Regional Meteorological Centres for posts in their respective establishment.".

[No. V-001014V[A]

V. K. CHOPRA, Meteorologist Grade-I (Vigilance)

for Director General of Meteorology.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मई, 1996

का. थ्रा. 1656 :—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (श्रर्जन और विकास) ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के भ्रधीन जारी किन गर्द, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 12 जून, 1993 में प्रकाणित कोयला मंदालय की ग्रिधि सूचना मं. का. थ्रा. 1301, तारीख 4 जून, 1993 द्वारा इस ग्रिधिसूचना में संलग्न ग्रनुसूची में विनिद्धित्व परिक्षेत्र में भूमि और श्रिधिकारों का श्रर्जन करने के श्रथन श्राणय की सूचना दीथी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उबत श्रिधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट देदी है। और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पण्चात् और महाराष्ट्र सरकार के परामर्ग करने के पण्चात् यह समाधान हो गया है कि :---

- (क) इससे संलग्न श्रनुसूची "क" के भाग 1,2 और 3 में विणित 16.275 हैक्टर (लगभग) या 40.22 एकड़ (लगभग) माप की भूमि; और
- (ख) इससे संलग्न अनुसूची "ख" में वर्णित 535.59 हैक्टर (लगभग) या 1323.50 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन,खदान,बोर करने, निष्कासन के लिए उनकी खुदाई करने और तलाण करने, उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के समस्त अधिकार अजित किए जाने चाहिए।

श्चनः, प्रयः केन्द्रीय सरकारः उक्त श्रधिनियम की धारा 9की उपबारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह घोषणा करनी है कि :——

(क) इससे संलग्न उक्त अनुसूची "क" के भाग 1.2 और 3 में बणित 16.275 हैक्टर (लगभग) या 10.32 एकड़ (लगभग) माप बाली शमि, धार

(ख) इससे संलग्न श्रनुसूची ''ख'' में वर्णित 535.59 हैक्टर (लगभग) या 1323.50 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान बोर करने, निष्कासन के लिए उनकी खुदाई करने और বলাঞ্চ करने, उन्हे प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के समस्त प्रश्चिकार श्राजित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक मं. सी—-1 (ई)]]]/एफ. आर. 543.0993, तारीख 14 सितम्बर, 1993 का निरीक्षण कलक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कार्डासल हाउस र्ट्राट, कलकत्ता के कार्यालय में या येस्टर्न कोलफीन्ड्ग लि. (राजम्ब अनुभाग) कोल इस्टेट, सिविल लाइम्स, मागपुर---440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जासकता है।

प्रतृयुची ''क' भाग⊸⊷1

नन्द अवाक

नागपुर क्षंच

जिला--नागपुर(महाराष्ट्र)

समस्त श्रधिकार

फ.सं. ग्रामकानाम	पटयारी सकित सं	 तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर मे	टिपणिया
1. खांडलसारी	41	भिवापुर	— नागपुर	0.275	—
AF	-			0.275 है ब ट या	र (लगनग)
·		>		0.679 ए३	कड़ (लगभग)

ग्राम खांडलझारी में श्रींजन किए गए प्लाट संख्यांक :

भाग, 155/1, 155/2 भाग, 156/1--156/2 भाग।

1 में 21

-सीमावर्णनः

র 1---ছ 2

ष्ट—— 3,ष्ट—— 1 ः

रेखा ह 1 बिन्दु से आर्रभ होती है और खांडलझारी ग्राम से होकर भागत: प्लाट सं. 4/1 से 21 तक की बाहरी सीमा के साथ प्लाट सं. 4/1 से 21 तक, 156/1, 156/2, 155/1 155/2 में से होकर जाती है। उसके पण्चात् प्लाट सं. 155/1, 155/2 की बाहरी सीमा

के साथ-साथ बक्ती है और इ.4. बिन्दु पर मिलती है।

₹--4,¥--1

रेखा ग्राम खांडलझारी से होकर गुजरती है और प्लाट सं. $155/1,\,155/2,\,4/1$ से 21 तक में बढ़ती है और प्रारंभिक बिन्दू इ 1 पर मिलती है।

ग्रन्मृची "क" भाग–⊢2

नन्ध्र ब्लाक

नागपुर क्षेत

जिला---नागपुर (महाराष्ट्र)

समस्त भ्रधिकार :

奔, 4.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्वित सं.	तहमील	जिला	क्षैत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
- 1. पिरा	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	40	भिषापुर	नागपुर	6.00	भाग
			,		6.00 हैक्टर (व	
					या	
					14.827 एक	ड़ (लगभग)

ग्राम पिरावा में अधित किए गए प्लाउ मंख्याक 💠

सीमावर्णनः ज---1 च 2 :

रहा "च1" बिन्दु में ग्रारंभ होती है और ग्राम पिरावा में होकर प्लाट मं.-104/1-----104/2, -123, -124 की बाहरी मीमा के माथ-माथ जलती है और -123 बिन्दु पर

entre il with all times also terrors a

मिलती है ।

च 2---- च 3--- च 4 :

रेखा ग्राम विरावा में प्लाट सं. 124, 125क, 125ख, 123, 104/1, 104/2 में से

होकर गुजरती है और बिन्दु च-4 पर मिलती है।

च्य---च1 :

रेखा ग्राम पिरावा से होकर प्लाट सं. 104/1-104/2 की बाहरी सीमा के साथ-साथ

चलनी है और ग्रारंभिक बिन्दू "च 1" पर मिलती है।

ग्रनसूची "क" भाग 3

नन्द ब्लाक

नागपुर क्षेत्र

जिला--नागपुर (महाराष्ट्र)

समस्त ग्रधिकार

कम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी मर्किल सं .	तहँसील	সিলা	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
. पिराव	ang	40	भिवापुर	नागपुर	10.00	भाग
	الله الله الله الله الله الله الله الله				10.00 हैक्ट र	 (लगभग)
					या	
					24.711 एक	इ (लगभग

समस्त ग्रधिकार---- प्रनुसूची ''क' का कुल क्षेत्र

भाग 1+3+3=0. 275+6. 00-10. 00=16. 275 हैक्टर (लगभग)

या

40,22 एकड़ (लगभग)

ग्राम पिरावा में श्रजित किए गए प्लाट संख्यांक :

126 भाग, 127/1–127/2 भाग, 128/1–128/2, 130 भाग, 131/1–131/2 भाग, 134 भाग, 135/1–135/2–135/3 भाग ।

सीमा वर्णनः

র্য 1--ন্স 2--ন্স 3---র্ম :

रेखा "छ1" से श्रारंभ होती है और ग्राम पिराया में प्लाट मं. 135/1-135/2, 135/3, 127/1-127/2, 126 से होकर गुजरती है उसके पश्चान प्लाट मं. 128/1-128/2 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है प्लाट सं. 130, 131/1-131/2, 134/, 135/1 135/2-135/3 मे होकर गुजरती है और श्रारंभिक बिन्दु "छ1" पर मिलती है।

in the second of the second of the second

अनुसूची ''ख''

तन्द स्लाक

नागपर क्षेत्र

जिला -नागपुर क्षेत्र (महाराष्ट्र)

खनन श्रधिकार

क्र.मं. ग्रामकानाम	पटवारी सर्किल स ्.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
ست قدير و سر يدم ارسم وسد است المرد وسو المراهي وسر المرد إليون و سرائي			···	-4	
1. केसलापार	41	भिवापुर	नागपुर	110.33	भाग
2. खांडलझारी	41	भिवापुर	नागपुर	248.87	भाग
 बैम्र 	41	भिवापुर	नागपुर	76,08	भाग
4. पिरावा	40	भिवागुर	नागपुर	100.31	भाग

535.59 हैक्टर (लगभग)

_ - - -

या

ा ३२३. ५० एकड् (लगभग)

ग्राम केसलापार में श्रामित किए गए प्लाट संख्यांक :

29 में 33, 34 भाग, 35/1-35/2-35/3, 36 में 39, 40/1, 40/2, 41/1-41/2-41/3-41/4, 42/1-42/2, 44/1-44/2-44/3, 54 में 60, 61/1-61/2, 62 में 78, सङ्क भाग नाला भाग। भाग। भाग खोडलझारी में प्रजित किए गए प्लाट संख्यांक:

4. भाग, 5 भाग 6, 7, 8/1-8/2-8/3-8/4, 9, 10/1क-10/ख-1 से 21 तक

 $10/\sqrt{1}$, 11 में 14, $15/\sqrt{1-15}/2$, 16 से 25 27भाग, $35/\sqrt{1-35}/2-35/3$ भाग, $36/\sqrt{1}$, $36/\sqrt{2}$, $36/\sqrt{3}$, $37/\sqrt{1}$ से $37/\sqrt{2}$, भाग, $38/\sqrt{1-38}/2-38/3$, 39 में 41, $42/\sqrt{1}$, $42/\sqrt{2}$, 43, $44/\sqrt{1}$, $44/\sqrt{2}$, $44/\sqrt{3}$, 45, 46, $47/\sqrt{1-47}/2$, 48, 53में 56, $57-\sqrt{1}-57-\sqrt{1-57}-57-\sqrt{1-57}-57-\sqrt{1-57}$, 58, 59, $60/\sqrt{1-60}/2-60/\sqrt{3}$, $61/\sqrt{1-62}/2$, 62 में 64, $65/\sqrt{1-65}/2$, $66-\sqrt{1-66}/2$, $66-\sqrt{1-69}/2$, 67 में 69, 72 भाग, 89, 90, $91/\sqrt{1-91}/2$, 93 में 99, $100/\sqrt{1-100}/2-100/3$, 101, 102, $103/\sqrt{10}$, $103/\sqrt{10}$, $103/\sqrt{10}/\sqrt{10}/\sqrt{10}/\sqrt{10}/\sqrt{10}$, $103/\sqrt{10}/\sqrt{10}/\sqrt{10}/\sqrt{10}/\sqrt{10}/\sqrt{10}/\sqrt{10}$

ग्राम बेसूर में श्रजित किए गए प्लाट संख्यांक :

185/1-185/2-185/3, 185 से 191, $192/1\pi-192/1\pi-192/1\pi-192/1\pi-192/2$, 193 से 203, 204/1-204/2 205/1-205/2, 206, 207, 408, 409, नाला भाग।

ग्रतम विरावा में वर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

52 में 56, 57/1-57/16-57/2-57/3, 58, 59, 60/1-60/2, 61 में 63, 64का-64ख, 65/1-65/2-65/3-65/4, 66, 67/1-67/2-68 में 78, 99-100/1-100/2, 101, 102/1-102/2, 103, 105 से 110, 111/1-111/2, 113/1-113/2, 114 में 121, 214 में 216, नाला भाग, सड़क भाग।

सीमा वर्णनः

क---ख्र रेखा बिन्दु ''क'' से ध्रारंग होती है और ग्राम खांडलझारी के प्लाट सं. 25 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है, नहर को पार करती है। उसके बाद प्लाट सं. 27 से होकर जाती है, सड़क पार करती है। उसके बाद प्लाट सं. 37/1-37/2, 35/1-35/2-35/3 से होकर जाती है। उसके बाद प्लाट सं. 36/3, 36/1, 48, 53 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है और फिर भागतः ग्राम खाडेलझारी और केसलापार की सम्मिलत सीमा के साथ-साथ चत्री है।। बिन्दु ''ख्र'' पर मिलती है।

- ख-ग रेखा, ग्राम कमलावार में प्लाट सं. 78 की बाहरी कीवा के साथ-माथ घलती है, सड़क को पार करती है, इसके बाद क्लाट सं. 5.1 की बाहरी सीम। के साथ-माथ घलती :, बाला पार करती है, प्लाट सं. $4.1/1 \cdot 4.4/2 4.4/3$, 4.1/1 4.1/2 4.1/3 4.1/4, 4.2/1 4.2/2, 3.8, 2.9, 3.4 की बाहरी सीमा के साथ-माथ चलती है ग्रीर बिन्धु "ग" पर मिलती है।
- ग-घ रेखा ग्राम केसलापार में प्लाट सं. 34 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है, सड़क पार करती है, इसके बाद प्लाट सं. 32, 33, 34 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है। रेखा ग्राम केसलापार के प्लार सं. 34 में से होकर जाती है और बिन्दु "ड." पर मिलती है।
- ङ—च रेखा, ग्राम के झलकारी के प्लाट सं. 72 में से होकर जाती है, इसके बाद प्लाट सं. 69 की **बाहरी सीमा के साथ-साथ** चलती **है, नहर पा**र करती है फिर प्लाट सं. 93, 91/1⊶91/2 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है और बिन्दु 'चि" पर मिलती है।
- च-छ रेखा, ग्राम खंडालझरी में प्लाट सं. 92/1-91/2, 90, 89, 103/1क-103/1ख, 103/2क-103/2ख-103/3, 105, 104 की बाहरी सीमा के साथ-माथ चलती है प्लाट सं. 5 में नाला पार करती है, इसके बाद भागतः प्लाट सं. 4 की 4/1 से 21 की बाहरी जीमा से होकर और भागतः उसके साथ-साथ चलती है, प्लाट सं. 4/1 से 2' से 155/1-155/2 में जाती है, नाला पार करती है और खंडालझरी और पिरावा गामों की सम्मिलित ग्राम सीमा पर बिन्दु "छ" पर मिलती है।
- छ- ज रेखा ग्राम पिरावा में से होकर जाती है, नाला पार करती है फिर प्लाट सं. 120 121, 211, 109, 105, 103, 102/1−102/2, 101, 99 की बाहरी सीमा, सड़क के साथ-साथ चलती है, सड़क पार करती है, इसके बाद प्लाट सं. 78 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है और बिन्दू "ज" पर मिलती है।
- ज—क्ष रेखा ग्राम पिरावा में प्लाट सं. 78, 73, 72, 76, 69, 64%—64ख, 63, 62, 61, 55, 54, 52 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है, इसके साद ग्राम वेस्र में प्लाट सं. 207, 409, 205/1, 205/2, 204/1-204/2 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है और बिन्दु ''झ'' पर मिलती है ।
- झ-क रेखा ग्राम बेसर में प्लाट सं. 204/1-204/2, 203 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है और नाला पार करती है, फिर प्लाट सं. 189, 188, 185/1-185/2-185/3 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है और श्रारंभिक बिन्दु ''क'' पर मिलनी है ।

[सं. 43015/6/90-एस.एस.इब्ह्य] श्रीमती प्रेम लता मैनी, अवर स

MINISTRY OF COAL

New Delhi the 28th May, 1996

S.O. 1656.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1301 dated the 4th June, 1993, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (heraintifier referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section—3, Sub-section (ii), dated the 12th June, 1993, the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands and rights in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Maharashta, is satisfied that,—

(a) the lands measuring 16.275 hectares (approximately) or 40.22 acres (approximately) described in schedule
 "A", Part I, II and III appended hereto; and
 1292 GI/96—11

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 535.59 hectares (approximately) or 1323.50 acres (approximately) described in Schedule "B" appended hereto;

should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby declares that-

- (a) the lands measuring 16.275 hectares (approximately) or 40.22 acres (approximately) described in the said Schedule "A", Part I, II and III appended hereto; and
- (b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 535.59 hectares (approximately) or 1323.50 acres (approximately) in Mining Rights, described in Schodule "B", appended hereto;

are hereby acquired.

The plan bearing number C-1(E) III/FR/543-0993 dated the 14th September, 1993 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Nagpur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the Western Coalfields Limited (Royenuc Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur- 440 001 (Maharashtra).

SCHEDULE 'A' PART-I

NAND BLOCK

NAGPUR AREA

DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA)

All Rights

Serial number	Name of Village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Khandalzari	41	Bhiwapur	Nagpur	0.275	Part
				·	0.275 hec	
					or	•
					0,679 agr (approxin	

Plot numbers acquired in village Khandalzari:

—— part, 155/1—155/2 part, 156/1—156/2 part. 1 to 21

Boundary description:

E1-E2-E3-E4 Line starts from point E1 and passes through village Khandalzari partly along the outer boundary of plot number - - - in plot numbers -- - , 156/1- 156/2, 1 to 21 1 to 21 155/1-155/2, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 155/1-155/2and meets at point E4.

E4-E1 Line passes through vill .gc: Khandalzari and proceeds in plot numbers 155/1—155/2,

--- and meets at starting point 'El'.

1 to 21

SCHEDULE 'A' PART-II

NAND BLOCK

NAGPUR AREA

DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA)

All Rights

Serial number	Namo of village village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Pirawa	40	Bhiwapur	Nagpur	6.00	Part
					6.00 hec (approxi	
					or	-
					14.827 a	cres
					(approxi	mately)

Plot numbers acquired in village Pirawa:

104/1-104/2 part, 123 part, 124 part, 125/1-125/B part.

Boundary description:

F1-F2

Line starts from point 'F1' and passes through village Pirawa along the outer

boundary of plot numbers 104/1-104/2, 123, 124 and meets at point 'F2'.

F2-F3-F4

Lino passes through village Pirawa in plot numbers 124, 125A-125B, 123, 104/1-

104/2 and meets at point 'F4'.

F4-F1

Line passes through village Pirawa along the outer boundary of plot number 104/1

--104/2 and meets at starting point 'F1'.

SCHEDULE 'A' PART-III NAND BLOCK NAGPUR AREA

DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA)

All Rights

Serial rumber	Name of village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1. Pirawa	40	Bhiwapur	Nagpur	10.00	Part	
					10.00 he (approximo 24.711 (appro	mately) r

Total of All Rights area — Schedule 'A' Part-I + II + III = 0.275 + 6.00 + 10.00 = 16.275 hectares (approximately)

or
40.22 acres
(approximately)

Plot number acquired in village Pirawa:

126 part, 127/1-127/2 part, 128/1-128/2, 130 part, 131/1-131/2 part, 134 part, 135/1-135/2-135/3 part.

Boundary description:

G1--G2--G3---G4

Line starts from point 'G1' and passes through village Pirawa in plot numbers 135/1—135/2—135/3, 127/1—127/2, 126, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 128/1—128/2 in plot numbers 130, 131/1—131/2, 134 and meets at point 'G4'.

G4-G1

Line passes through village Pirawa in plot numbers 134, 135/1—135/2—135/3 and meets at starting point 'G1'.

SCHEDULE 'B'

NAND BLOCK NAGPUR AREA

DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA)

Mining Rights

Serial number	Name of village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
_ _	Kesalapar	41	Bhiwapur	Nagpur	110.33	Part
2.	Khandalzar	41	Bhiwapur	Nagpur	248.87	Part
3.	Besur	41	Bhiwapur	Nagpur	76.08	Part
4.	Pirawa	40	Bhiwepur	Nagpur	100.31	Part
					535.59 hec (approxima	tely)

(approximately) or 1323.50 acres (approximately)

Plot numbers acquired in village Kesalapar:

29 to 33, 34 part, 35/1—35/2—35/3, 36 to 39, 40/1—40/2, 41/1—41/2—41/3—41/4, 42/1—42/2, 44/1—44/2—44/3, 54 to 60, 61/1—61/2, 62 to 78, road part, Nala part.

Plot numbers acquired in village Khandalzari:

part, 5 part, 6, 7, 8/1--8/2--8/3--8/4, 9, 10/1A--10/B--10/C, 11 to 14, 15/1--15/2, 16 to 25, 27 part, 1 to 21

 $35/1 - 35/2 - 35/3 \text{ part, } 36/1, \ 36/2, \ 36/3, \ 37/1 - 37/2 \text{ part, } 38/1 - 38/2 \ 38/3, \ 39 \text{ to } 41, \ 42/1, \ 42/2, \ 43, \ 44/1, \ 44/2 - 44/3, \ 45, \ 46, \ 47/1 - 47/2, \ 48, \ 53 \text{ to } 56, \ 57A - 57B - 57C - 57D, \ 58, \ 59, \ 60/1 - 60/2 - 60/3, \ 61/1 - 61/2, \ 62 \text{ to } 64, \ 65/1 - 65/2, \ 66A - 66B - 66C, \ 67 \text{ to } 69, \ 72 \text{ part, } 89, \ 90, \ 91/1 - 91/2, \ 93 \text{ to } 99, \ 100/1 - 100/2 - 100/3, \ 101, \ 102, \ 103/1A - 103/1B - 103/2A - 103/2B - 103/3, \ 104, \ 105, \ 155/1 - 155/2 \text{ part, road part, nala part, canal part.}$

Plot numbers acquired in village Besur:

185/1—185/2—185/3, 186 to 191, 192/1A—192/1B—192/1C—192/1D—192/2, 193 to 203, 204/1—204/2, 205/1—205/2, 206, 207, 408, 409, nala part.

Plot numbers acquired in village Pirawa:

52 to 56, 57/1—57/1A - 57/2—57/3, 58, 59, 60/1—60/2, 61 to 63, 64A—64B, 65/1—65/2—65/3—65/4, 66, 67/1—67/2 68 to 78, 99, 100/1—100/2, 101, 102/1—102/2, 103, 105 to 110, 111/1—111/2, 112, 113/1—113/2, 114 to 121, 214 to 216, nala part, road part.

Boundary description:

A---B

Line starts from point 'A' and passes through village Khandalzari along the outer boundary of plot number 25, crosses canal, then proceeds through plot number 27, crosses road, then passes through plot numbers 37/1--37/2, 35/1-35/2-35/3, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 36/3, 36/1, 48, 53, then proceeds partly along the common boundary of villages Khandalzari and Kesak pur and meets at point 'B'.

ВС	Line passes through village Kesalapar along the outer boundary of plot number 78, crosses road, then proceeds along the outer boundary of plot number 54 crosses nala proceeds along the outer boundary of plot numbers $44/1-44/2-44/3$, $41/1-41/2-41/3-41/4$, $42/1-42/2$, 38, 29, 34 and meets at point 'C'.
C – D	Line passes through village Kasalapar along the outer boundary of plot number 34, crosses road, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 32, 33, 34 and meets at point 'D'.
DE	Line passes through village Kesalapar in plot number 34 and meets at point 'E'.
E—F	Line passes through village Khandalzeri in plot number 72, then proceeds along the outer boundary of plot number 69, crosses canal, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 93, 91/1—91/2 and meets at point 'F'.
FG	Line passes through village Khandalzevi along the outer boundary of plot numbers 91/1—91/2, 90, 89, 103/1A—103/1B—103/2A—103/2B—103/3, 105, 104, crosses note in plot number 5, then proceeds partly along the outer boundary of plot number 4
	—————————————————————————————————————
	and meets at common village boundary of villages Khandalzari and Pirawa at point 'G'.
G H	Line passes through village Pirawa, crosses nala, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 120, 121, 214, 109, 105, 103, 102/1—102/2, 101, 99, read, crosses road, then proceeds along the outer boundary of plot number 78 and meets at point 'H'.
H I	Line passes through village Pirawa along the outer boundary of plot numbers 78, 73, 72, 70, 69, 64A—64B, 63, 62, 61, 55, 54, 52, then proceeds through village Besur along the outer boundary of plot numbers 207, 409, 205/1—205/2, 204/1—204/2 and meets at point T.
I—A	Line passes through village Besur along the outer boundary of plot numbers 201/1—204/2, 203, crosses nala, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 189, 188, 185/1—185/2—185/3 and meets at starting point 'A'.
	[No. 43015/6/90-LSW]

[No. 43015/6/90-LSW]

Mrs. P. L. SAINI, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का० आ० 1657.—भारतीय आयुर्जिज्ञान परिषद अधिसियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारी (1) के खंड (ख) के उपबन्धों के अनुसरण में नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा डाक्टर अमरनाथ बसवंतराव शोलापुरे, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष शरीर किया विज्ञान विभाग, श्री बाऊ साहेब हीरा राजकीय मेडिकल कालिज, मालेगीव , धुले-424001, महाराष्ट्र की 14 दिसम्बर, 1995 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचिन किया गया है ।

अत. अय केन्द्रीय सरकार उन्त अविनिन्ना की घारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में मारत सरकार के वत्नालीन स्थास्थ्य मन्नालय की अधिसूचना सख्या 138, तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संगोधन करती है, अर्थात्

उपत अधिमूचना में, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन "निर्वाधित" शीर्षक के नीचे कम संख्यांक, 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों रखी जायंगी अर्थात्:—

''74. डा० ए. वी० मोलापुर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, णरीर किया विज्ञान विभाग, श्री बाऊ साहेब हीरा राजकीय मेडिकल कालेज, धुले–424001, महाराष्ट्र''

> [संख्या बी० 11013/4/96 एम० ०ई० यू०जी] एम० के. मिश्रा, डेस्क अधिकारी

गाद टिप्पणीः मूल अधिसूचना भारत के राज्यत्व में अधिसूचना संख्या का०आ० 138, दिनांक १ जनवरी, 1960 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 10th May, 1996

S.O. 1657,—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. Amarnath Baswantrao Solepure, Professor and Head, Department of Physiology, Sri Bhausaheb Hira Government Medical College, Malagaon, Dhule-424001, Maharashtra has been elected by the Senate of North Maharashtra University, Jalgaon to be a member of Medical Council of India from 14th December, 1995:

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", after serial number 73 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:—

"74. Dr. A. B. Solepure,
Professor and Head,
Department of Physiology,
Sri Bhausaheb Hira Government Medical College,
Dhule-424001,
Maharashtra."

[No. V. 11013/4/96-ME(UG)] S. K. MISHRA, Desk Officer

Foot Note.—The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S.O. 138, dated the 9th January, 1960.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1996

का. ग्रा. 1658: — केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना-2001 में निम्नलिखित संगोधन करने का प्रस्ताव हैं, जो सार्वजनिक सूचना के लिये एतद्वारा प्रकाणित किए जाने हैं। प्रस्ताबित संशोधनों के संबंध में गाँद किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाब देना हो तो वह अपनी आपत्ति/ प्रपना सुझाब इस सूचना के जारो होने को ताराख से 30 दिनों की श्रवधि के श्रंदर आयुवत-एवं-सचिव बिल्लो बिकास प्राधिकरण विकास सदन "बी" व्यक्ति आई, एन. ए. नई दिल्ली के पाम लिखित रूप में भेज सकते हैं। श्रापत्ति करने/ सुझाब देने वाले व्यक्ति को श्राप्ता अपना भी रना चाहिए।

संगोधन---

1. "उप-जोन एफ-7 (मुखदेश बिहार) में पड़ने बाल, उत्तर एवं पूर्व में जिला पार्क/कृषि भूमि मे, दिलल में एन.सी.डी. कम्पोस्ट प्लोट/वर्कशाप में, पश्चिम में एन.जा.एम.सी. वर्कणाप/मोजूदा मार्ग से घिरे, 0.32 हेश्ट्या (0.79 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" (जिला पार्क)

- से "विनिर्माणी" (सेवा केन्द्र) में बदनने का प्रस्ताव है।"
 2. "गरेला उप-नगर परियोजना येज-1 के भाग के रूप में आँग उत्तर में प्रस्तायित 80 मोटर चौड़ा सड़क से, दिलग में ग्रामीण उपयोग (कृषि भूमि) गांव टिकरी खुर्व से, पूर्व में रूलम एवं जे. के. के पुनर्वास के लिए विकसित खी. खी. छी. ए. प्रधिप्रहीत भूमि गींर पश्चिम में 40 मोटर मार्गाधिकार वाली मीजूदा राड़क श्रीर मनोरंजनात्मक (विकसित हरित पट्टी) से विरे लगभग 21 हेक्टेयर (52.0 एकड़) क्षोत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण क्षोत्र" से श्रावासीय "उपयोग' में बदलने का प्रस्ताव है।"
- 3. "पूर्व में पश्चिमी यमुना नहर से, उत्तर श्रीर पश्चिम में ग्रामीण उपयोग (कृषि भूमि) से तथा दक्षिण में 80 मीटर प्रस्तावित मार्गीधिकार वाला बवाना-नरेला सड़क (ग्रहरों विस्तार) से घिरे लगभग 39.3 हेक्टयर (97.0) एकड़ क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीग-उपयोग" से "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक मुविधाग्रों (सा.श्रार.पा.एफ.) बटालियन 6) में बदलने का प्रस्ताव है।"
- 4. प्रस्तावित संशोधन को दर्शान वाला ननशा निराजण के लिए, संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल; विकास मीनार, आई.पो. एस्टट, नई विल्लो के कार्यालय में, उक्त ग्रवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों को उपलब्ध रहेगा।

[सं.एफ. 20 (18) 95-एम.पी.] विक्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th May, 1996

S.O. 1658.—The following modification which the Central Govt. proposes to make in the Master Plan for Delhi-2001, are hereby published for public information. Any person having any objection suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, 1NA, New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections suggestion should also give his name and address:—

MODIFICATIONS:

1. "The land use of an area measuing 0.32 ha. (0.79 Acre) falling in sub-zone F-7 (Sukhdev Vihar) bounded by District Park Cultivated land in the North and East, MCD compost plant Workshop in the South and NDMC Workshop existing Road in the West, is proposed to be changed from 'recreational' (District

Parks)" to mnaufacturing (Service Centre)".

- 2. "The land use of an area, measuring about 21 ha. (52.0 acres) forming part of Narela Sub-city Project Phase-I and bounded by proposed 80 M wide Road in the North, Rural use (Agricultural land) Village Tikri Khurd in the South, DDA acquired land developed for resettlement of Slum and JJ in the East and 40M R|W existing road and Recreational (developed green strip) in the West, is proposed to be changed from 'Rural use' to 'Residential use'."
- 3. "The land use of an area measuring about 39.3 ha. (97.0 acres) and bounded by Western Yaniuna Cana; in the East Rural use (Agricultural land) in the North and West and 80M proposed R|W Bawana Narela Road (Urban Extension) in the South is proposed to be changed from 'Rural use' to 'Public & Semi Public facilities' (CRPF Pattalion 6 nos.)".
- 2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(18)95-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रक मंमालय

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का० आ० 1659 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म कारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचयट को प्रकाणित करती है, जो वेन्द्रीय सरकार को 8-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल 12011/101/88डी ए/आई आर (बी-2)] पी० जे० माईकल, उँम्बः अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1659.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Disput between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 8th May, 1996.

[No. L-12011/101/88-D.II.A|IR(B-II)] P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनसंग

केन्द्रीय आंद्योगिक न्यायाविकरण, राज, जयपुर केस नं० सी०आई० टी० 63/89

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल-12011/101/88-डी 2(ए) दिनांक 1-6-89

अध्यक्ष, यूको बैंक स्टाफ एसोमियेणन, परद्याना भवत, माधोबाग जोधपुर । प्रार्थी

बनाम

सहायक महाप्रबंधक, युको बैंक, शास्त्री नगर, जयपुर। अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीस, भी के ०एल० न्यास, आर०एच०जे०एग० प्रार्थी की ओर से : वे०एल० गाह अप्रार्थी की ओर से : श्री मान सिंह अवार्ड विनांकः 21-10-95

अवार्ड

श्रीमक प्रतिनिधि श्री जे०एल० शाह व शिपक्षी श्रीतिशि श्री मानसिंह उपस्थित हैं। दोनों पक्षों का कथन है कि श्रिवाद बाबत श्रीमक यूनियन व प्रबन्धक में समझौता हो गया है। उस समझौते के अनुतार श्रीमक्षण को भुगतान हो रहा है अतः श्रीफ पूनियन विदाद में आगे कार्यबाही नहीं करना चाहते हैं। दोनों पानों के बीच सम्पन्न सपझौते व श्रीमक यूनियन के प्रतितिधि की अभिष्यवित के अनुसार विवाद में नो-डिस्प्यूट अधिनिर्णय पास्ति करने का आदेश दिया जाता है। अधिनिर्णय पास्ति करने का आदेश मेजा जाते।

के० एल० व्यास, न्यायाधीण

नर्ष दिल्ली, 14 मई, 1996

का० आ० 1660. -- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार न्यू वैक ऑफ इंडिया (पंजाव नैशनल बैंक) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके पर्मवारों के बीच, अनुबंध में निधिष्ट अद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय मरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशिक करती है, जो केन्द्रीय मरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या: एल 12012/221/90-आई०आर० (बी-2)] अज भोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1660.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of New Bank of India (Now PNB) and their workmen, which was received by the Central Government on 9th May, 1996.

[No. L-12012/221/90-IR(B-II)] BRAJ MOHAN, Desk Officer ANNEXURE
BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOK!

PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 289/1990

Deputy General Manager, New Bank of India, 1, Tolstoy Marg New Delhi.

AND

Asstt. General Secretary, New Bank of India Employees Union, C/o New Bank of India Rawatpura, Agra.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-12012/221/90-I.R. B-2, dated 7th December, 1990, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal;

"Whether the action of the management of New Bank of India in terminating the services of S/Sh, J al Singh and Rajesh is justified? If not, to what relief the concerned workmen are ontitled?"

- 2. It is not necessary to give fact of the case as the parties namely Lal Singh & Rajesh on the one hand while Punjab National Bank on the other hand have filed compromise dated 22nd April, 1996 by which the management has agreed to give fresh employment to these workmen and the workmen have agreed to give up their back wages.
- 3. In view of the above agreement the reference has become infructous and the concerned workmen are entitled to no relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer नई बिल्ली, 14 मई, 1996

का० आ०-1661- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय मरकार यूकों बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिण्ट आंद्योगिक विवाद में औद्योगिक न्यायाधिकरण अजमेर के पंचपट को प्रकाणिन करनी है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[मंख्या एल-12012/50/95-आई०आर० (बी-2)] ग्रज मोहन, जैन्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1661.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Labour Court, Ajmer as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 9th May, 1996.

[No. L-12012/50/95-IR(B-II)] BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबंध

न्यातान्यः ----अत र तायागर एवं **औद्योगिक** न्यायाधिकरणः -ग्रायमेर

प्रकरण सं० सी०प्राई०धी०प्रार० 3/95 रेफरेंच नम्बर :---एल० 12012/50/95, दि० 25-8-95 पीठाभीन प्रधिकारी:---श्री ह्रि सिंह यू० ग्रस्नानी, प्रारुक्तिकोणस्व उपाध्यक्ष, राजस्थान (स्टेट) थैंक वर्कस धार्मनाइजेशन, 24 डी, न्यू धाई०टी० यथार्टम मासूरिया, जोधपुर

. . प्रार्थी

बनाम

मण्डल प्रवन्धक, युको बैक, मण्डल कार्यालय, जी-79. णाम्बी नगर, जोधपुर ।

. . भ्रप्रार्थी

उपस्थित:----प्रार्थी स्वयं उपस्थित श्री वी०एन० श्रीवास्तव, ग्रप्तार्थी की ओर से

श्रमार्ड

22-4-1996

 भारत सरकार ने निम्न विश्वाद इस न्यायाधिकरण को प्रधिनिर्णय हेत् प्रेधित किया है:---

Whether the action of the management of UCO Bank, Jodhpur is deducting a sum of Rs. 969.57 from the subsistance allowance of Shri Rajendra Bhandari clerk-cum-cashier and also deducting his salary for 9-4-94 and debiting a sum of Rs. 10 from his account is legal and justified? If not what relief is the said workman entitled to?

2. प्रार्थी की ओर में मण्डल प्रबन्धक युको बैंक, मण्डल कार्यालय जी-78, शास्त्री नगर जोधपुर (जिसे आगे से यूको बैंक कहा जायेगा) के विरुद्ध प्रस्तुत स्टेटमेंन्ट ऑफ क्लेम क्स्सेंप में इस प्रकार है कि उसे 11-4-94 के आदेश से अबैध अनुचित रूप में निलंबित किया गया और नियमान्तुमार उसे पूर्ण जीवन निर्वाह भता दिया जाना चाहिए था। उसके बजाय उसे परेशान व विक्टेमाईज के उद्देश्य में अप्रैल 94 के निर्वाह भन्ने में में 969.57 रूठ की कटौती कर ली गई, जो गलत है। दिनांक 9-4-94 को प्रार्थी यूठकोठ वैंक के निदेशानुमार केम में तस्तीश के सिल्जिले में जोधपुर थाने में गया था जहां उसे दिन भर बैठाये रखा और उस दिन उसे अनुचित रूप में अव्रप्तियत मानते हुए बेतन 195.20 पैसे काट लिये।

यह यूको बैंक ने 13-5-94 को प्रार्थी के खाते में बिना कारण बताये जनाधिकृत रूप में 10/-50 काट निये।

- 3. मृको वैंक हारा प्रस्तृत जबाय संक्षेप में हता प्रकार है कि प्रार्थी को विश्विक स्ता से निलंबित किया गया क और कटोती भी नियमानुसार की गई थी और परेणान और बिक्टेमाईज की कोई नियत नहीं थी ओर प्रार्थी पुलिस चौकी पर उपस्थित नहीं हुआ था। इस कारण अनुपरिथत भानतें हुए एक दिन का वे न काटा गया था।
- ा प्रार्थी ने साक्ष्य में स्वयं को पेण किया और विपक्षी की और से साक्ष्य में श्री वी०एन० श्रीवास्तव पेण हुए।
- की उभय पक्षों को सुना तथा पद्मावली का मावधानी से श्रवलोकन किया ।

6. प्रार्थी ने प्रभिने जयानों में कहा है कि उसके निर्वाह भत्ते से लोन पेटे की गई कटौती श्रवंध थी और जिस नोट के पैकेट से 10/- कि का एक नोट जाली पाया गया उस पैकेट पर उसके श्रितिरिक्त केंग श्रिधकारी श्री रागी के भी हस्ताक्षर थे। विभिन्न हाथों में वह पैकेट गया और जाली नोट डोटेक्ट नहीं हुआ, वह श्रार०बी०शाई० ज्यपुर में डोटेक्ट हुआ और श्रन्य ग्रिधकारियों को तो छोड़ दिया और प्रार्थी मे ही श्रनुवित कटौती कर ली गई। और जाली नोट डीटेक्ट करने की भी ट्रेनिंग उसे नहीं मिली थी। उसने कहा है कि वह थाने पर गया जहां एस०एव०ओ० वैंक गया होना बताया। वह काफी देर बैठा रहा और डी०वाई०एस० पी० को शिकायत की उस पर तक्तीण अधिकारी वदला गया और यूको बैंक के कहने पर ही वह थाने पर गया था, किर भी उस दिन का बेतन गलत काटा गया।

7. यू० को० बैंक के प्रिधकृत प्रतिनिधि श्री वी०एन० शीवास्तत्र ने श्रपनी साक्ष्य में कहा है कि लोन पेटे प्रार्थी के निलंबन काल में निर्वाह भते से राशि कांटी गई शी जो बैंक शैन्यूबल की धारा 21.6 के तहत Permissible है। इस गवाह को निजी जानकारी नहीं है कि प्रार्थी थाने गया था था नहीं, किन्तु उन्हें थाने से प्रवर्श एम-2 सूचना मिली थी कि प्रार्थी वहां नहीं गया था और जाली नोट पाये जाने के कारण 10/-६० की कटीती भी नियमानुमार की गई थी ि अके पीछे कोई युर्यावना नहीं थी।

- प्रार्थी निभिक्त श्री राजेन्द्र भंडारी ने निम्न प्रस्तुत किये :
 - (1) यह कि निर्वाह भत्ते में से किसी भी प्रकार से श्रन्य कटौती नहीं की जा सकती।
 - (2) पैंकेट में एक 10/- हु० का जाली नोट उसके नोटिस में नहीं शाने के कारण उसमें वसूनी करना अनुचित है, जब कि प्रन्य जिम्मेदार श्रविकारियों के विकड़ कोई कार्यवाही नहीं की गई।
 - (3) बहु थाते पर घंटों बैठा रहा था। श्रतः उस दिन का बेतन काटना भी श्रतुचित है।
- इसके बिपरीत यूको० वैंक के प्रतिनिधि ने निम्न तर्क प्रस्तुत किये हैं:

यह कि प्रार्थी 18-11-94 को सेवा में पुनः बहाल हो गया है और लौन पेटे केवल एक शाह के लिए 969.57 क० माह अप्रैल 94 में काटे गये थे जो गैन्यूयल के अनुमार विधिवत है और अन्य कटीती भी नियमों के अनुमार है और दुर्भावना जैंगी कोई बात न नी थी और न ही प्रार्थी ने अपने बयान में कही।

10. मेरी राय में एक पैकेट में से 10/ रू० का एक जाती नोट पासे जाने के कारण केवल प्रार्थी श्रमिक से इति वसुली किया जाना उत्तित नहीं है, वयोंकि जैसा कि प्रार्थी ने बताया है कि श्रधिकारी थी रामी ने भी उस पैकेट पर हस्ताक्षर किये थे। मेरी राय में लिपिक की श्रमेक्षा श्रीयकारी को जिम्मेदारी श्रियक होती है और पैकेट कई हामों में गया और कहो एक जाली नोट डोटेक्ट नहीं हुया आर 1292 G1/96—12.

आर०बी०आई० जनपुर में जहां छीटेक्ट करने की सुविधा प्रियंक होना अपेक्षित है यहां डिटेक्ट किया गया है। ग्रतः एउ ऐति कोई संमीर लायरबाही नहीं है, जिल्हों लिए केवल आर्थी श्रिमिक माल को ही जिम्मेदार ठहराया जावे।

11. प्रार्थी के इस कथन पर जिश्वाम नहीं करने का कोई उपित कारण नहीं हैं कि वह थाने पर नहीं गया हो। उनने श्रथ्य पर थाने में जाने का कथन किया है, ज'व कि विभक्षी प्रवन्ध को इस बारे में कोई निजी जानकारी नहीं है। केवल थाने से प्राप्त सूचना ही उनकी जानकारी का प्राधार है। जब कि इसकी पृष्ठभूमि यह बताई गई है कि घंटों इंतजार करने के बाद प्रार्थी ने एस०एच०ओ० की अनुपस्थिति के बारे में डी०वाई०एस०पी० से शिकायत की और परिणाम-स्वरूप नक्तीण ग्रधिकारी बदला गया। श्रतः उम दिन प्रार्थी की अनुपस्थित भानकर बेतन कटौती करना उचित प्रतीत नहीं होता।

12. जहां तक 969.57/- के की कटौती का प्रश्न है यह कटौती निर्वाह भत्ने से माह अप्रैल 94 में की गई है और माध्य से स्वब्ध है कि प्रार्थी के निवेदन पर उसके तुरस्त बाव यह कटौती बन्द कर वी गई और इस बटौती का राम्यन्ध्य विश्वति मने से नहीं होकर प्रार्थी ने बैंक से जो ऋण विधा था, उसले था और बैंक मैंन्युवल के तहत यह परमीसिबल भी है। प्रार्थी ने ऋण विधा और यह गांश उसके ऋण पेडे ाग थी जो गई बींर बह बहान सी हो गता देश सब बाता को देखते हुए गेरो राथ में इस कटौता को अनुचित नहीं कहा जा सकता।

13 श्रत: प्रेषित विवाद का श्रिधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है:---

यू० को० बैंक मण्डल कार्यालय, जी-79 मास्त्री नगर जोबपुर के प्रवत्यक द्वारा प्रार्थी के निर्वाह भन्ते से 969.57 पैसे की वसूली उचित एवं वैद्य है, लेकिन 9-4-94 के प्रार्थी के एक दिन की वेतन कटौती अनुचित है और इसी प्रकार दस क्यये की कटौती भी अनुचित है। फलस्वरूप प्रार्थी 9-4-94 का वेतन एवं दस रूपये यू० को० बैंक औधपुर से प्राप्त करने का श्रिधकारी है।

14. प्रवार्ड प्रकाशनार्थ भारत सरकार श्रम विभाग को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

> हरि सिंह यू० अस्नानी, न्यायाधीश नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का०आ०1662—-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार थूको बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्नकारों के बीब, अनुबंध में निर्धिष्ट औद्योगिक धिवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई के पंचपट को प्रकाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल--12012/364/92-आई आर (बी-II)] ज्ञज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1662.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank nd their workmen, which was received by the Central Government on 13-5-96.

[No. L-12012/364/92-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT:

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/21 of 1993

Employers in relation to the management of UCO Bank, Nagpur.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Workmen: Mr. Umesh Nabar, Advocate. For the Employer: Mr. V. P. Vaidya, Advocate.

Mumbai, dated 9th April, 1996

AWARD-PART-I

The Government of India. Ministry of Labour by its Order No. L-12012/364/92-IR(BJI) dated 1-3-1993. had referred to the following Industrial Dispute for adjudication:

- "Whether the action of the management of UCO Bank in dismissing Shri S. Venkatachari from the services of the bank is institled? If not, what relief the workman is entitled to?"
- 2 S. Venkatacharl, the workman was appointed by the UCO Bank, the management in its service. He was Asstt. Cashier at Akola. He was then transferred to Sitabuldi,
- 3. The workman pleaded that on 16-8-1989 when he was working at cash payment counter he received an urgent telephone call from one of his close relatives requesting him to come to him immediately for his personal and urgent work. The workman took permission from the manager and one Mr. A. A. Derhpande was but in charge of his counter, But on his way the workman met with an accident and so required to be hospitalised on 3-10-1989. A show cause notice was given to him for the incident dated 16-10-1989. He gave a reply to it on 5-10-1989. Thereafter he did not receive any intimation from the management so far as the incident dated 16-8-1990 is concerned.
- 4. On 6-4-1990 the workman received another Show Cause Notice from the management in relation to some of his alleged private transactions which had nothing to do with the business of the bank. It was falsely alleged that the workman misused his position as the bank cashier for securing pecuniary benefits and acting prejudicial to the interest of the bank. On 19-4-1990 he gave a reply to it. On 10-5-90 the management cautioned and warned the workman in respect of the misconduct referred in the show cause notice dated 6-4-1990.
- 5. The workman was suspended by the letter dated 16.7-90 for the alleged misconducts shown in the show cause notice dated 16.8-89 and 6.4-90. The said suspension was followed by a chargesheet dated 12-9-1990. The same charges were levelled nasinst the workman including shortage of Rs. 3 000 (Rugers Three Thousand Only) occurred on 7-5-90. It is pleaded that by any strength of imagination it cannot be said that the workman committed misconduct in terms of clause 19(5)(j) of Bi-partled settlement. The management proposed

- to hold departmental inquiry against the workman. Shri V. L. Manani was appointed as the inquiry officer. It is pleaded that after the initiation of the inquiry proceedings the workman was called by the management and promised that in case he admits his guilt the management would again allow him to go with a warning letter. It is averred that under the circumcances the applicant admitted the said charges during the course of inquiry on 12-12-1990. Thereafter the workman was dismissed by the Civl. Manager by his order dated 6-7-1991. While pussing an order the Divisional Manager considered other aspect of the matter, which did not form part of the charge. The workman was never given an opportunity to meet those allegations. It is averred that the order of dimsissal is totally illegal and improper.
- 6. The workman averred that the second charge contained in the Chargesheet dtd. 12-9-1990 could not have been the subject matter of disciplinary action. The charge relates to private transactions. It is averred that the applicant was already punished by way of warning for alleged misconduct by order dtd. 10-5-1990. Thus he cannot be given double punishment for the same misconduct. It is averred that the charge of the misconduct was of a minor and technical character. As such the punishment awarded is shockingly disproportionate. It is averred that he was victimised for his Trade Union Activities which is unjust and improper. It is submitted that the findings recorded by the inquiry officer are totally perverse.
- 7. The workman pleaded that he preferred an appeal dated 2-8-1991 before the Astt. General Manager through proper channel. The appeal was rejected without proper application of mind and in a time limit. It is prayed that under such circumstances the order of dismissal may be quashed and the workman may be directed to be reinstated in service with continuity with full back wages. He also claimed other reliefs.
- 8. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-'3'. It is averted that the dismissal order issued against the workman is perfectly legal and proper. It is as per the provisions of the Bipartied settlement. It is contended that the workman has admitted all the charges at the domestic inquiry conducted against him before the order of dismissal dtd. 6-7-1991. It is submitted that the inquiry was conducted by an independent inquiry officer. On the baris of the admission of the worker and findings submitted by the inquiry officer the bank had taken disciplinary action and issued the order of dismissal dtd. 6-7-1991. It is averted that the appeal which was filed by the worker was properly considered and then it was rejected with reasons.
- 9. The management denied that the worker was vindicted due to his trade union activities. It denied other allegations which the workman had taken in the statement of claim pertaining to the charges levelled against him. It is contenthat its initiating disciplinary proceedings is as ner the previsions of the Bipartied settlement and therefore illegal. It denied that the workman was given double punishment for one misconduct. It is submitted that the bank is awarded tunishment of dismissal only after the report of the inquiry officer which found the workman guilty of all allegations as the workman had admirted the charges. It is denied that the domestic enquiry was not as per the principles of Natural Justice. It is susserted that the punishment awarded to the workman is not illgal, disproportionate or harsh as averred by the workman.
- 10. The management pleaded that in the event the Tribunal comes to the conclusion that the inquiry is not proper, it may be given an opportunity to lead an evidence. For all these reasons it is submitted that the workman is not entitled to the relief as claimed.
- 11. The issue No. 1 is tried as a Preliminary Issue. The issue and my findings there on are as follows:

Issues

Findings

1. Whether the Inquiry
which is held against the
workman was against the
Principles of Natural
Justice?

Ńο.

REASONS

- 12. Venkatachary (Exhibit-25), the workman affirmed to prove his claim. He admitted the documents which are fitted by the management alongwith Exhibit-4'. Nobody entered into the witness box on behalf of the management.
- 13. Admittedly the worker was working on Cash payment counter in 15-6-1989. He affirmed that on that day after receiving the phone call he left the place and had gone to meent his relative. On the way he met with an accident. Thereafter he was given a show cause notice. He gave expanation to it.
- 14. Venkatachary aftirmed that again on 6-4-1990 he was given another snow cause notice which he reputed. Then he was warned by the management. He was suspended by order dated 10-/-1990. Later on he was served with a charge-sheet (Exhibit-5) dated 12-9-1990.
- 15. One Mr. Manani was appointed as the inquiry officer who issued notice to the workman informing the date and the place of the inquiry. The workman admits to have received the same. It is not in dispute that after adjourning the matter the inquiry took place on 12-12-90. On that date the worker admitted his guilt in writing. He signed the letter which is alongwith Exhibit-'16'. It is pertinent to note that the worker by his letter dated 17-10-90 (Exhibit-9) accepted the charges. It has to be stated that he athrimed the same again by the letter dated 12-12-90. No witnesses were examined nor documents were produced. The inquiry was completed on 12-12-90. Thereafter the inquiry omcer send a letter (Exhibit-16) of the same date to the disciplinary authority UCO Bank, Divl. Office, Nagpur. It states that "With reference to the above inquiry he submitted alongwith it the following in triplicate: (1) Proceedings of 12-12-1990 and (2) Letter from the Chargesheeted employee admitting the charges against him.
- 16. It is not in dispute that the worker followed the charges and had taken part in the inquiry. He did not receive the report of the inquiry officer nor any show cause notice for the proposed punishment.
- 17. Mr. Nabar the Learned Advocate for the workman argued that there was no report of the inquiry officer at all. He had not given his findings on the charges. It is therefore, the inquiry has to be said as unnatural. It is not in dispute that there is no inquiry report. The inquiry officer alongwith Exhibit-II' forwarded to the disciplinary authority only the proceedings dated 12-12-90 and a letter signed by the worker admitting the guilt. Mr. Vaidya the Learned Advocate for the management argued that under such circumstances there was nothing to be reported to the disciplinary authority. He had to only send the proceedings to the disciplinary authority and the formality to say that the charges are proved even if it is not mentioned had not caused any prejudice to the worker. I find substance in it.
- 18. Clause 19.2(E)(3) of the Memorandum of Bi-partied settlement states that the inquiry need not be held after the employee makes a Voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice. However, if the employee concerned requests of hearing regarding the nature of punishment such hearing shall be given.
- 19. I have already observed above the workman by the letter dated 17-10-90 (Exhibit-9) which he wrote to the inquiry officer clearly speaks out that the charges against him are all accepted by him without condition and reservation of any kind. He had also mentioned in this letter that to disperse with the need for conducting the inquiry there are other circumstances mentioned in the letter which need not be considered for deciding the preliminary issue. It can be said that those are relevant while discussing the point of punishment.
- 20. The inquiry officer even after receipt of this letter send another letter informing the workman the date of the inquiry and asked him to attend it. He adjourned the matter for the convenience of the worker and ultimately on December 12, 1990 the workman again accented his guilt for the charges. From the perusal of the record and from the testimony of Venkatachary it cannot be said that an opportunity was not

given to the worker. In other words this case can be stated to be without domestic inquiry. What the inquiry officer did is to forward the letter of admitting the guilt of the workman and other records. For the sake of argument if it is said that he had failed to subm's his findings namely he found the worker guilty of the charges was only a formality. It has not prejudiced the worker at all. The worker's prayer in his earlier letter is in respect of the punishment only. That finds place in his appeal. That was considered by the Appellate authority. The order which is passed by the Disciplinary authority and the Appellate authority are well rearoned. I do not find any reason to hold it as mechanical

21. Where a domestic inquiry is held it has to be seen that the workman is given full opportunity to meet the charges and defend his case. Here in this case there was nothing like that. The worker is the leader of the union. It is not his grievance that he did not follow the charks nor that he was not allowed to examine the witness or that he did not receive the documents. It is a case of punishment on admission. I, therefore, find that the arguments which is advanced on behalf of the worker that the domestic inquiry which was held against him was against the principles of natural justice has no merit. In the result I pass the following order:

ORDER

The inquiry which was held against the workman was as per the Principles of Natural Justice.

S. B. PANSE, Presiding Officer नई दिस्ली, 14 मई, 1996

का०आ०1663.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, 2 मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/168/92-आई आर (बी-2)] क्रज मोहन, ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. O. 1663.—In pursuince of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government hereby publishes the award of Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on 13-5-1996.

[No. L-12012|168|92-IR(B-II)] BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI PRESENT:

Shri S. B. Panse, Presiding Officer Reference No. CGIT-2|50 of 1992

Employers in Relation to the Management of Bank of Maharashtra

AND Their Workmen

APPEARANCES:

For the Workmen: Mr. Vinay Karmakar Representative.

For the Employer: Mr. R. G. Londhe Representative.

Mumbai, dated 3rd April, 1996

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-12012|168|92-IE(B.H), dated 30-7-1992 had referred to the following Industrial Dispute for adjudication.

- "Whether the action of the management of Bank of Maharashtra, Bombay in not allotting the post of Head-Cash'er category 'A' to Sh. V.S. Nanal and depriving him the higher Special allowance thereof w.e.f. October, 1985 to December, 1987 at Fort Branch of Bank, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"
- 2. A Bank of Maharashtra there are various allowance carrying post including Head Cashier Category 'A', Cashier-in-Charge etc. A policy circular was issued on 5-8-1974 for allotment of such a post. It was in operation till 30-4-1987. The post has to be given to the senior most elligible person from the branch and there are certain criterias mentioned in the said circular.
- 3. In the Fort Branch of Bank of Maharahstra there was a post of Cashier-in-charge. Its extension counter is at Mantralaya having he post of cashier-in-charge. At Fort Branch, Head cashier was being assisted by more than four clerks cashier, and the said post was required to be treated as a head cashier category 'A' (unit of 5 clerks and above) Thus higher allowance should have been given for that post than that of cashier in charge,
- 4. V. S. Nanal, the worker was allotted the post of cashier in charge of extension counter of Fort branch w.e.f. 2-4-85. On 29-9-85 the head cashier's post at Fort Branch became vacant. It was allot ed to Surve who was junior to him. This is in violation of the Bi-partied settlemen's and the policies. On 30-12-87 Nanal the worker was allotted the post of encoder operator which is still higher allowance pos than the head cashier category 'A' on the basis of his seniority. It is submitted that he was deprived of the higher allowances between October 1985 to December 1987. He was deprived of the said allowance post by the illegal action of the management. It is prayed that the action of the management in not allotting the post of Nanal is illegal and unjus. He also prayed for consequential reliefs.
- 5. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-3. It is submitted that when the post at Fort Branch was allotted to Surve, Nanal nor his union raised any objection. They are doing so only because Surve filed an application under section 33C (2) of the Industrial Disputes Act of 1947 before Labour Couurt, Bombay. He could get the relief as prayed for. Now Nanal wants to get the benefit of it which he is not entitled to. It is submitted that

Nanal never worker at Fort Branch and as he did not work there he is not entitled to the monetary reliefs which he wants to claim. It is prayed that under such circumstances the reference may be an swered in favour of the bank.

- 6. The Union filed a rejoinder at Exhibit-'4' and contended that they cannot raise any objection or take part in the application before the Labour Court as they were not party to it. It is averted that if any fault is committed by the bank by no posting Nanal to the said post they have to face its consequences.
- 7. The issues that fall for my consideration and my findings there on are as follows:

Issues Findings

- 1. Whether the action of the bank in not allotting the post of Head Cashier Category 'A' to Mr. Nanal and depriving him of higher special allowance w.e.f. October 1985 to December 1987 at Fort Branch of Bank is justified?
- The action is not justified.

2. If not what rel'ef the worker is entitled?

As per order,

REASONS

- 7. From the testimony of Nanal (Ex-7) the worker, Sahastrabudhe (Ex-8) the union's office bear and from the written statement it is clear that Nanal was sen'or to Surve, at Fort Branch at a relevant time He was suitable for the allowance carrying pos'. His suitability was as per the circular dtd. 5.8-1974 (Ex-5|1).
- 8. As Nanal was senior admittedly he was given the post of cashier in charge which fell vacant at Mantralaya extension counter on 2-4-1985. Thereafter the post of cashier-in-charge fell vacant a Fort Br. on 28-9-1985. It was allotted to Surve. It can be seen that at that time both these posts were carrying the same special allowance. The extension counter at Mantralaya is part and parcel of the For Branch.
- 9. Surve happened to file an application under section 33C (2) of I.D. Act in the Labour Court, claiming the special allowance of head cashier category. A. He contended that the post which he is holding
- at Fort Branch is the post of Head Cashier Ca'egory 'A' and is entitled to special allowance as per the set lement. According to him he was given a lesser special allowance than what as required to be paid. The Labour Judge as pleased to accept his contention and declare that the post which he was holding at the Fort Branch is of Head Cashier category 'A'. He is entitled to monetary reliefs as claimed. The Judgement of the Labour Court is at Exhibit-'6' dtd. 3-10-1989.

- 10. It appears that after the said decision Nanal and his union thought that they are deprived of their legitimate right by not giving he post. It is argued on behalf of the worker that the fault was committed by the management and the worker cannot be said to be at fault. I find substance in it, because in te Bi-partite settlement is very clearly described a particular post as a head cashier category 'A'. As per the seniority it should have been allotted to Nanal Having not raised a dispute by Nanal the management cannot take away his right to have that post. It is not that he denied to accept the post. If that would have been so then as per the circular he could not have put foward the grievance.
- 11. It is tried to submit that the worker had not actually worked as a Head Cashier Category 'A'. It is therefore he is not en itled to the special allowance. Infact he could not work because he was not assigned that work. It is not that he refused the same. As this is so the argument which is adduced on behalf of the bank has no merit.
- 11. So far as eligibility of Nanal is concerned it is accepted position that he was eligible and therefore he was alloted the post of cashier-in-charge initially. Later on he was alloted a still higher allowance post namely encoder operator. Naturally at a relevant time he was entitled to the post of a Head Cashier Ca egory 'A' at Fort Branch.
- 12. It is tried to argue on behalf of the bank that in view of the set lement dated 13-4-87 (Exhibit-5|2) now Nanal cannot claim the benefit. This argument has no merit. Because this se tlement came into effect form 13-4-1987. The claim raised by Nanal is on the basis of the vacancy falling vacant in October 1985.
- 13. For all these reasons I find that Nanal is entitled to the difference of special allowance between cahsier in charge which he was drawing and that of Head Cahsier for the period form 28-9-85 to December 1987. The action of the management in not alloting the post to him is illegal and unjust. I record my findings on the issues accordingly and pass the following order:

ORDER

- 1. The action of the management of Bank of Maharashtra, Bombay in no alloting the post of Head Cashier Category 'A' to Sh. V. S. Nanal and depriving him the Higher Special Allowance thereof w.o.f. October 1985 to December 1987 to Fort Branch of Bank is not justified.
- 2. The bank is directed to pay Nanal the difference of Special Allowance between 28-9-1985 to December 1987 with n one month from the receipt of the Award.
 - 3. No order as to costs.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई बिरुली, 14 मई, 1996

का०आ० 1664 — औद्योगिक विवाब आधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय

सरकार सेन्द्रल बैंक आंफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबग्ध नियोजकों और उनके वर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार आंद्योगिक अधिकरण, नानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/77/92-आई आर (बी-II)] ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1664.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Amaexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 9-5-96.

[No. L-12012|77|92-IR(B-H)] BRAJ MOHAN, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 78 of 1992

Regional Manager, Central Bank of India, Varanasi.

AND

Secretary, Central Bank Staff Association, Dipak Takis Ga*e, C. K.-37|44-C. Bans Fatak, Varanasi-221005.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-12012|77|92 dated 24-6-92, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

"Whether the action of the management of Central Bank of India in withdrawing the second stagnation increment granted to Sh Ram Achal Misra, Special Assistant, Nagar Maha Palika Branch, Vanarasi, w.c.f. 1-1-91 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled to?

2. It is not necessary to give the facts of the case as the applicant has moved an application on 3-4-96 informing that as the opposite party has meet the demand of Association, the reference is not pressed.

3. In view of the above the reference is answered against the workman. He will be not entitled any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का॰आ॰ 1665. — औद्योगिक विवाद अधिनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल--31011/11/90--आई आर (विविध)] बी० एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1665.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2. Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th May, 1996.

[No. L-31011/11/90-IR(Misc.)] B. M. DAVID, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT:

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/17 of 1991

Employers in relation to the management of Bombay
Port Trust

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Workmen-Mr. Jaiprakash Sawant, Representative.

For the Employee-Mr. M. B. Anchan, Advocate.

Mumbai, the 4th April, 1996

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-31011/11/90-IR(Misc.) dated 4th April, 1991 had referred to the following Industrial Dispute for adjudication:

- "Whether the management of Bombay Port Trust, Bombay, in relation to its Docks Department, Bombay, is justified in denying their legitimate promotion and seniority to S/Shri Bhikaji G. Babal, (2) Avinash A. Raut, (3) Tulsidas H. Behere and (4) Iqbal A. E. Hamdani, all Clerical Gr. II workmen to the post of Clerical Gr. I? If not, what relief these concerned workmen are entitled to?"
- 2. The Secretary for the Bombay Port Trust Employees Union filed a Statement of Claim for the workers at Exhibit-'2'. It is contended that these workers were appointed as Tally clerks in its docks department of Bombay Port Trust. Thereafter they were promoted to clerk Grade-II on different dates on the basis of seniority and suitability. A departmental committee found three workers fit to be promoted for the post of clerk Grade-I on 1st March, 1985 and one of them on 1st October, 1984. But the management Illegally denied the promotion to the workers on these dates and promoted junior workmen in their places contrary to the statutory terms of employment.

- 3. The union contended that the action of the management in denying the promotion of the post of clerk Grade-I to the workmen on the basis of the said dates is illegal, irregular and unjust. They prayed that these workers should be promoted to clerk Grade-I on those dates and consequential benefits with 15 per cent interest on it may be granted to them.
- 4. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-'3'. It is averred that the dispute which is raised is after a lapse of six years and is stale. It is, therefore, not tenable. It is averred that the Tribunal had no jurisdiction to decide the present reference. It is submitted that these workers are the members of the Transport and Dock Workers Union. As they are not the members of the present union and the union cannot espouse the cause for the four workmen concerned in the above reference.
- 5. The union averred that these workers were considered by the departmental promotion committee for the promotion of clerk Grade-II. They were not fit. Therefore their juniors were promoted. Later on when the departmental promotion committee found them fit they were promoted to the post of clerk Grade-II. Again when they were found suitable for the post of Clerk Grade-I they were promoted. It is submitted that the juniors to these workmen were earlier promoted to clerk Grade-II on the basis of their suitability. It is denied that the juniors were illegally promoted defeating the claim of the workmen in the present reference. It is averred that the management has not violated any rules governing the promotion policy of the B.P.T. in respect of non-scheduled staff. It is prayed that under such circumstances the reference may be answered in favour of the management.
- 6. My Learned Predecessor framed issues at Exhibit-'4'. The issues and my findings thereon are as follows:

Issues Findings

1. Whether the present reference is tenable in law?

Yes.

2. Whether the court has jurisdiction to entertain and decide the present reference?

Yes.

3. Whether the B.P.T. Employees Union has locus standi to espouse the cause on behalf of the four workmen in question?

Yes.

4. Whether the four workmen in question must be deemed to be promoted to the posts of Clerk Grade-I on and from 13-3-1986, 1-3-1985, 1-10-1984 and 1-3-1985 respectively?

No.

5. If not, to what relief they are entitled?

Does not Survive.

6. What Award?

As per order.

REASONS

7. Bhikaji Babal (Ex-12), Avinash A. Raut, (Ex-10), Tulsidas H. Behere (Ex-9 & 9A) and Ahmed Hamdani (Ex-11) are the concerned workmen in the present reference. They deposed in support their claim. Bagdish Pradhan (Ex-14) is Shed Superintendent. Hamallage Dock Department. devosed for the management. From the testimony of these witnesses and the documents which are Ex-6' and '15' the following facts can be said to be admitted. To appreciate the promotional dates and its effect. I will put in the form of a chart:

Ref. No. CGIT-2/17 of 1991

				1
No. Name	Tally Clerk	Dates Considered by D.P.C.	Clerk Grade-II	Clerk Grade-I
1. Babal	1-3-76	16-6-81, 5-2-82, 28-1-83	1-3-83	5-2-90
1A. Pote	1-3-76 (j)	_	19-10-81	3-12-85
2. Rauth	2-7-74	22-5-80, 16-6-81, 5-2-83	1-3-83	5-2-90
2A. Narvekar	-do- (j)	-	3-8-80	8-10-84
3. Behere	5-10-74	22-5-80, 5-2-82	1-3-83	5-2-90
3A. Kaushik	5-10-74 (j)		31-10-80	1-3-85
4. Hamdani	28-10-74	22-5-80, 4-2-81, 5-2-82, 16-6-82	1-3-83	5-2-90
4A. Saldana	20-11-74 (j)	_	2-10-80	1-3-85

- 8. From the above chart it is very clear that Pote, Narvekar Kaushik and Saldana who were juniors to Babal, Rauth, Behere, Hemdani respectively were promoted to clerk Grade-II earlier to the workmen concerned in the reference. It is not in dispute that departmental promotion committee considered the cases of the employees for the promotion of clerk Grade-II from tally clerk. Pradhan affirmed the date of appointment to the particular cadre and subject to suitability is the criteria for further promotion. It is not in dispute that for giving the post of clerk Grade-II and clerk Grade-I no written or oral tests is conducted. The employees are selected by the departmental promotion committee on the basis of their leave record and other confidential record. From the above chart it is also clear that these workmen were considered by departmental promotion committee in the year 1981-1982 and 1983 while giving promotions. They found them unfit. Therefore, it appears that their juniors were promoted to the clerk Grade-II.
- 9. It is tried to argue by the Learned Representative for the union that the juniors who were promoted to Grade-It and the workmen concerned were in Grade-II when the promotion to clerk Grade-I were given to these juniors. According to him while giving such promotions their seniority i.e. original seniority should have been considered. I do not find any merit in it. Because once the promotion is given the cadre is different.

The seniority is given in that particular cadre as per the dates of the promotions. From the testimony of Pradhan it reveals that while giving the promotion to clerk Grade-I also the departmental promotion committee looks the confidential record of the concerned workmen. When these workmen found fit to be promoted to clerk Grade-I the promotions were given to them in 1990. But others who were found fit for clerk Grade-I were given promotions long back i.e. in the year 1985 or so.

- 10. The promotions are given as per the seniority and suitability. From the testimony of the witness it is very clear that these workmen were not found suitable to be promoted initially. They were given chances. But meantime their iuniors who were found to be suitable were given promotions Behere admitted that seniority is maintained on the basis of promotion i.e. which I have stated above.
- 11. It is the case of the workmen that they were never informed that they are not suitable Pradhan affirmed that

the adverse remark in their confidential file was reported to the worker. He produced such a record alongwith Exhibit-15'. It is not in dispute that there is no departmental inquiry against the workmen. That does not mean that they are suitable. It is the committee which decided the matter. It is not the grievance of the union that there are malafields in the selection. There is no evidence to that effect also. Pradhan had deposed that while removing the record they have misplaced some of the files of the worker and therefore they could not be traced. There is no reason why his word has to be rejected. Mr. Samant the Learned Representative of the Union argued that under regulation 8(II) of the B.P.T. Employees Regulations 1976 withholding the promotions is a minor penalty which could be missed only after following the procedure laid down under the Regulation 14 & 15 of the said regulations. In fact the said regulation 8 has no application to the present circumstances. It is because that the promotions were not withheld for a particular reason. But it was not given to the workman as they were not found suitable at that particular time. The promotion cannot be claimed as of a right. It is by way of selection and suitability. As the committee did not find these workmen suitable for they were not promoted to the post which they claimed on those particular dates.

- 12. It is tried to argue on behalf of the management that these workmen were the members of the Transport and Dock Workers Union who by letter dated 16th July, 1987 demanded promotion of these workers as claimed in the present reference. The management replied the same on 19th August, 1987. It was informed to the union that due to the nonclearance of these clerks by the DPC their seniority could not protected and the facts of Das Gupta Award does not apply to the present case. It is argued on behalf of the management that it is therefore the Transport and Dock Workers Union had given up the demand.
- 13. It appears that subsequently the present union by its letter dated 3rd January, 1989 raised the present dispute with Asstt. Labour Commissioner. It is tried to argue on behalf of the management that these workmen are the members of the Transport and Dock Workers Union. Therefore the present union cannot raise the dispute. Mr. Sawant the Learned Representative of the workmen submitted that these workmen are their members. As the matter was not seriously disputed he had not lead evidence to that effect. It can be seen that from the testimony of the Pradhan he had nowhere stated that these workmen are not the members of the present union. It can be further seen that this contention was

not raised by the management before the Asstt. Labour Commissioner. As this is so I find that they are members of the union and the present union had right to espouse the dispute.

14. So far as Issues No. 1 & 2 are concerned it appears that the management had given up the objection so far as tenability of the reference and the jurisdiction of this Tribunal. For the sake of argument if it is said that they have not given up this contention I answered these issues in the affirmative. It is because the dispute which is referred to the Tribunal is an Industrial Dispute. It relates to the service conditions of the worker with that of the employer. Naturally the Tribunal has jurisdiction to try the same. For all these reasons I record my findings on the issues accordingly and pass the following order:

ORDER

- 1. The action of the management of Bombay Port Trust Bombay in relation to its Docks Department, Bombay is justified in denying their promotions and seniority to Shri Bhikaji G. Babal, Avinash A. Raut, Tulsidas H. Behere and Iqbal A. Hamdani all Clerical Grade-II workmen to the post of clerk Grade-I.
 - 2. No order as to costs.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का०आ० 2666—औद्योगिक विव अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-2-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29011/25/90-आई आर (विविध)]

बी० एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1666.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 off 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Centent Corporation of India Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 20-2-1996.

[No. L-29011/25/90-IR(Misc.)] B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI S. R. BANSAL, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Casé No. ID 124/90

President, C.C.I. Cement Factory, Mens Union, (INTUC), Charkhi, Dadri.

 \mathbf{v}_{s}

The General Manager, M/s. Cement Corporation India Limited, Charkhi, Ddari. Respondent.

For the Union: Bhag Singh, General Secretary.

For the Management : H. N. Mehtani.

AWARD

Central Government vide letter No. L-29011/25/90-TR(DU) dated 25-9-90 in exercise of the powers conferred by clause 'D', sub-clause (D) of the Industrial Disputes Act, 1947. for short called as the Act), has referred the following dispute

between the workmen's Union and the management of C.C.I. 1.1d. for adjudication to this Court:

'Whether the management of Cement Corporation of India in relation to their Cement Factory/mine at Charkhi, Dadri, Bhiwani are justified in not acceeding to the demand of the CCI Cement Factory Men's Union for payment of Rs. 40 per month as electricity allowance to those workers who have not been given quarters by the management. If not, what relief the workers concerned are entitled to?"

On appearance the workmens' Union submitted the statement of claim and pleaded that Dalmia Dadri Cement Factory Ltd. was taken over by M/s. CCI Ltd. on 23-6-1981 and prior to its take over the management of erstwhile used to pay Rs. 5 and Rs. 4 per month per worker as electricity allowance to such of the workers who were not provided with quarters by the said Company in lieu of 20 units of free electricity provided to such worker who were provided quarter by the Company and the same was continued upto 1-3-1980 the date of its closure and also upto 22-6-1981 in respect of such workers whose services were kept in continuance on closure. Later on on behalf of the workmen's Union an industrial dispute for payment of electricity allowance @ Rs. 40 per month to each of the worker who have not been provided with quarter by the Corporation in lieu of 40 units of free electricity paid to such of the workers who have been provided quarters was raised vide demand notice dated 12-5-1989 from the retrospective effect i.e. their date of appointment but was not accorded to and the Union has therefore, demanded that the workers should be made payment @ Rs. 40 per month per worker retrospective.

The management however pleaded that the conciliation proceedings held by the Assistant Labour Commissioner (C), Rohtak ended in failure. On merits, it was pleaded that the service conditions of the employees are governed by the Arbitration Award for Cement Industry which does not provide for payment of electricity allowance to the workers residing outside the residential colonics of the Cement com-It was also pleaded that practice of free supply of electricity to the workers residing in the housing Colony of the manufacturing Unit has a historical background and as stated in para No. 157 of the Arbitration Award for cement industry, since most of the Units are situated at far of places and housing colonies are not connected to public electricity supply line, the employers have been providing electricity to the houses of the employees free of charges for lighting purpose only and on this anology C.C.J. had also extended the benefit of free supply of electricity upto 40 units ner month to the workers residing in the housing colony attached to the factory. Such employees are available round the clock and they can be called for duty at any time at a short notice for proper operation of the plant. The empa short notice for proper operation of the plant. lovees who are not residing in the CCI Housing Colony are naid HBA at the rates prescribed in the Arbitration Award for Cement Industry and therefore, the benefits of free electricity have been given to the workers strictly in accordance with the Arbitration Award for Cement Industry and in line with the practices obtaining in all cement plants and is not intended to be given as a financial benefit or allowance to the workers who are residing outside the residential colonies of the cement companies.

The Union submitted replication controverting the allegations of the management in the written statement and reiterated its earlier pleas.

Keening in view the rival contentions of the parties, both the workman's Union as well as the management were asked to produce evidence. Workman's Union produced WW-1 I. R. Bagla who tendered his affidavit ex WI broadly supporting the allegations as made in the claim statement. The management produced MWI Raisev Mathur who produced his affidavit Ex. MI also broadly supporting the allegation as to be in the written statement. Both the tenderer of the affidavits were also cross-examined by the respective parties.

I have heard the representatives of both the parties and also scrutinised the entire record of the case carefully.

The act of the mannement is based strictly in accordance with the Arbitation Award for the Cement Industry and is also in line with the practice obtaining in all the Cement plants. This production award is binding on both the management well as workers employed in the Cement Industry. Such employees who are residing in the residential colonies

of the management corporation are available round the clock and they can be called for duty at any time at short notice for proper operation of the plant, whereas the employees residing outside the residential colony are paid HRA at the rates prescribed in the Arbitration Award. In case the plea of the work nen's Union is accepted, this is bound to led to multiplicity of litigation in other units of the corporation and also any other Cement manufacturing Units in the country covered under the Arbitration Award for the Cement Industry besides strain on the scarce financial resources of the Corporation. The action of the management in not acceeding to the demand of the CCI Cement Factory Men's Union for payment of Rs. 40 per month as electricity allowance to those workers who have not been given quarters by the management appears to be legal and just and this reference is bound to be answered against the workman's Union. order accordingly. Appropriate Government be informed suitably.

Chandigarh, 15-2-1996.

S. R. BANSAI., Presiding Officer नई दिल्ली, 15 मई. 1996

का०आ० 1767 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कानेज ऑफ विलिट्टी इंजिनियरिंग खड़की के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्भकारों के बीन, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई नं० I के पंचपट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-14012/22/92-आई आर (डी यू)] के०वि०वी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi the 15th May, 1996

S.O. 1667.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay No. I as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of College of Military Engineering Khadki and their workman, which was received by the Central Government on 14th May, 1996.

[No. L-14012/22/92-TR (DU)] K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1, MUMBAI

PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer. Reference No. CGIT-1/78 of 1993

PARTIES:

Employers in relation to the management of College of Military Englneering, Khadki
AND

-

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Management-Shri R. K. Shetty, Advocate.

For the Workman-Ms. Neelema Gohad, Advocate. STATE: Maharashtra,

Mumbai, dated the 2nd day of April, 1996

AWARD

Shri R. K. Shetty-for management.

2. One Ms. Neelema-Gohad, Advocate appeared in prelunch cell but she did not have any authority of the workman. The workman himself did not appear in the pre-lunch session. Hence, the Tribunal waited for him. He has not appeared in the post-lunch session. Ms. Neelma Gol id has 1292 GI/96—13. also not appeared in the post-lunch session. Hence, the Tribunal is left with no alternative but to proceed ex-parte in the matter. Hence, I have proceeded to hear the matter exparte.

- 3. The facts of the case are not in dispute. Appointment of Lascers in the Military Engineering Colleges are governed by statutory Rules framed by the President of India under proviso to Article 309 of the Constitution of India A copy of the relevant Rules is marked as Ex. 'N' by the management. Entry No. 6 of the Schedule to the Rules lays down the age of recruitment as 'not exceeding 25 years'
- 4. The present workman was admittedly over age when he was initially appointed as a Lasser on 1st June, 1985. This appointment, was thus irregular. The management must thank the authorities that he, who make such appointments, by bye-passing statutory Rules. However, the upshot is that the workman continued to serve till 7th September, 1989, when his services were terminated, without complying with the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act.
- 5. It appears that besides the workman, some other workmen similarly situated had a similar grievance. The matter was referred to competent authorities for regularisation of these appointments. By Ex. 'B' dated 19th March, 1993, the services oft the workman along with certain other workmen, were ordered to be regularised. His name appears at S. No. 15 of this order. By this order, the age limit of recruitment relaxed; it was further spelled:
 - "The intervening period between the termination of services and reinstatement will be treated as dies non for which individuals concerned will not be entitled to pay and allowances. This period will not count as qualifying service for the purposes of pension and leave etc.".

It also provided:

- "Services rendered by the individual concerned prior to issue to this letter will be treated as Ad-hoo service and not to be counted for the purpose of seniority, promotion and confirmation."
- 6. In pursuance of Ex. 'B', appointment letter Ex. 'C' dated 23rd April, 1993 was issued. In this order also, the name of the workman appears at S. No. 15. The workman joined his post in pursuance of Ex. 'B' on 30th April, 1993 (F.N.) vide Ex. 'E'.
- 7. Since the workman was aggrieved by termination of his service, he raised an industrial dispute, which was referred to this Tribunal by the appropriate Government in the following terms:
 - "Whether the action of the employer i.e. Commandant, College of Military Engineering, Khadki, Pune iv terminating the services of Shri Laxman M. Jambhukar, by verbal orders is justified? If not, what is the relief to which the workman is entitled?"
- 8. The workman filed his written statement of claim asking for various reliefs. The management opposed the same and filed a detailed reply to the written statement of claim. It was inter alia pleaded that the College did not constitute an Industry and the claimant was not a workman. The claim was opposed on merits after on various counts.
- 9. I have heard the learned counsel for management in great details and may state at the outset that the contention about the claimant not being a workman and the College not being an industry is not well taken and is negatived by the very rules which admittedly govern the institution and the appointment of the claimant. The very rules designate the various posts covered by the Rules as Industrial Class III and Class IV posts. Hence, I reject this contention.
- 10. Now, admittedly the claimant was a casual, illegally and irregularly appointed workman, who was allowed to continue in job till the impugned termination took place and admittedly without complying with the provisions of Section 2.5F of the Industrial Disputes Act and hence was bad in law.
- 11. However, the claimant accepted the dispensation provided by Ex. 'B' and Ex. 'C'. A workman could always waive

ر الإسلام ا

his rights under law. He accented the appointment Ex. 'C' and joined in pursuance thereof, duly regularised, though his initial appointment was bad.

- 12. True that his services were not terminable due to initial arregularity in his appointment. But, it is equally true that but for the relaxation granted by virtue of Ex. 'B' and Ex. 'C', his services could not have been regularised, keeping in view the fact that the initial appointment was bad.
- 13. In my opinion, the claimant by accepting appointment Ex. 'C' waived his rights and he can not be permitted to blow hot and cool and hence is predueled from claiming any benefits, merely because the impugned termination of services was bad in law.
- 14. In facts and circumstances of the case, the workman has been given a very fair dispensation and now can not ask for anything more than what has been granted to him by Ex. 'B' and Ex. 'C'. The claim is disposed of according and an award is passed as stated above. The management shall get its costs which are assessed at Rs. 500.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई दि: ली, 15 मई, 1996

काण्याण 1668 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1847 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूरभाष के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई के पंचपट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/155/93-आई आर (डी य्)] के बी० बी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1668.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Mumbai as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Telephone and their workman, which was received by the Central Government on 14th May, 1996.

[No. L-40012/155/93-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer.
Reference No. CGIT-1/60 of 1994

PARTIES:

Employers in relation to the management of MTNL, Bombay,

AND

Their workman.

APPEARANCES:

For the Management-No appearance.

For the Workman-Shri B. M. Vaidya, Advocate.

INDUSTRY: Telephones. STATE: Maharashtra.

Mumbai, dated the 30th day of April, 1996

AWARD

Shri B. M. Vaidya, Advocate—for workman, None—for management,

Shri Vaidya has submitted a written application to the effect that the workman does not want to pursue the reference and he may be allowed to withdraw the reference.

In view of the application, there is no dispute to be adjudicated upon. The workman is allowed to withdraw the reference. The matter is closed as 'no dispute award'. The same be got notified in accordance with law.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 मई, 1996

का०आ० 1669 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सांगली बैंक लि० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई नं०-1 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्रान्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/46/94-आई आर वी] के० वी० बी० उण्णी, डैस्क आंधकारी

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1669.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay No. 1 as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sangli Bank Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on the 14-5-96.

[No. L-12012/46/94-IRBI] K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

Present ;

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer, REFERENCE NO. CGIT-1/31 0P 1995

Parties:

Employers in relation to the management of Sangli Bank Ltd., Sangli.

AND

Their workmen

Appearances:

For the Management: Shri M. V. Gaonkar, Advocate, For the workman: No appearance,

INDUSTRY : Banking

STATE: Maharashtra

Mumbai, dated the 11th day of April, 1996

AWARD

None present for union. Shri M. V. Gaonkar management.

Since the union or the workman have not put in appearance, I have no alternative but to proceed ex parte.

M. V. Gaonkar has filed reply of the management. The same is taken on record. Heard Shri Gaonkar.

The appropriate Government has referred the dispute in the following terms:

"Whether the management of the Sangli Bank Ltd. Sangli was justified in terminating the services of Shri Gajanan R. Raut, Driver and if not to what relief the workman is entitled to?"

Admittedly, the case of the union is that though the workman was appointed as a Personal Driver of an Officer of the Bank and the Officer was reimbursed for payment of the salary to the workman, he be treated as an appointee of the Bank. This precise dispute has not been referred to this Tribunal. This Tribunal is a Tribunal of reference and does not function as a Civil Court and can not assume jurisdiction over disputes, not referred to it. The reference is this not proper and has to be rejected as such.

The Union and workman would be free to move the appropriate Government to make a proper reference so that the basic question and dispute in controversy can be adjudicated upon.

I am clearly of the view that in garb of reference pertaining to the question of termination, the basic dispute can not be adjudicated upon because the question involved is not merely incidental but fundamental. The reference is disposed of accordingly. In the circumstances of the case, the parties shall bear their own costs. The order be notified in accordance with law.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 मई, 1996

का०आ० 1670. - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीज, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई नं० 1 के पंचपट को प्रकाणित जो केय सरकार को 14-5-96 को हुआ था।

[संख्या एल--41012/13/92--आई ग्रार बी श्राई] के०वी०बी० उण्णी, डेस्क श्रधिकारी

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1670.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay No. 1, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Rly., and their workman, which was received by the Central Government on the 14-5-96.

[No. L-41012/13/92-IRB-I] K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-1/62 OF 1992

PARTIES:

Employers in relation to the management of Central Railway, Rombay V.T., Bombay.

AND Y

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Management: Shri Vyas, Advocate. For the Workman: Shri Pradhan, Advocate.

INDUSTRY: Railways STATE: Maharashtra

Mumbai, dated the 12th day of April, 1996

AWARD

The appropriate Government has referred the following dispute for adjudication to the Tribunal:

- "Whether the action of the management of Central Railway, Bombay V. T., Bombay in terminating the services of Sri S. P. Damagu, Casual Painter, CTI (SION) with effect from 10-07-1986 is just, proper and legal ? If not to what relief is the workman is entitled to ?"
- 2. Briefly stated, the case of the workman is that he was appointed s a Casual Painter in 1978 and he worked under the respondent for the following periods:
 - (i) 24-3-78 to 18-6-78.
 - (ii) 21-6-78 to 18-8-78.
 - (iii) 25-9-78 to 18-1-85.
 - (iv) 26-8-85 to 29-7-86.
- 3. The case of the workman is that his services were terminated illegally and wrongfully without complying with the provisions of Sec. 25F of the Industrial Disputes Act.
- 4. His further say is that he should have been sent for medical examination after putting in 120 days of service but that was not done and he was sent for medical examination after 4 years at which he was found unfit and the services were terminated.
- 5. Upon such pleas, the workman prayed that termination of his service w.e.f. 50-7-86 be declared illegal and wrongful; he be reinstated in service with back wages and continuity of service and all other benefits.
- 6. The respondent employer has opposed the claim. It was admitted that the workman entered service as a Casual Workman on 24-3-78. It was admitted that workman served the employer for the periods 14-3-78 to 18-6-78; 21-6-78 to 18-8-78 and 25-9-78 to 18-1-85. It was stated that the workman left the job on 19-1-85 and was re-engaged on 26-8-85 and remained in job upto 5-8-86. It was alleged that the workman absented himself from 6-8-86. Efforts were made to explore possibility of re-engaging him but he was found medically unfit and hence it was not feasible to continue on the job. It was asserted that since the workman absented himself from 6-8-86, there was no occasion for terminating his services and complying with the provisions of Section 25F of the I. D. Act. It was pleaded that the workman was not entitled to any relief.
- 7. It appears that on 21-2-84 and without going into merits of this case, my learned predecessor recorded an order to the effect "both the counsel are agreeable to a fresh reference to the concerned medical officer for fresh medical examination and thereafter, it found fit for being re-employed, in any of the category, to take him back in appropriational category in which he is found medically fit,"
- 8. On 30-4-94, the learned counsel for the employer stated that re-appointment on being found medically fit could be considered only if he did not claim back wages. This offer was not acceptable to the workman and the matter was directed to be posted for hearing on merits.
- 9. The matter came up before me for the first time on 22-8-95 when the learned counsel for management sought time to lead evidence on 31-8-95, my attention was drawn to the order dated 21-2-94 passed by my predecessor. However, my attention was not drawn to what had transpired om 30-4-94 and I directed the management to apprise the Tribunal about medical examination of the workman. On 17-10-95. Mr. Vyas for management placed a xerox conv of the report of medical examination and as such I directed the matter to be heard on merits.
- 10. Since the workman had already closed his evidence, the case was posted for evidence of the management. On 08-11-95 both the parties prayed for time. Eventually, the witness of management was cross-examined on 2-2-96.
- 11. The matter was finally heard on 8-2-96 when I reserved the award.
- 12. In this case, the fact that the workman remained in the employment of the management from 24-3-78 to 18-1-85 with some intermittent breaks is not in dispute. However, it is seriously in dispute if the workman worked under the management for the period 26-8-85 to 29-7-86 and his services were abruptly terminated on 29-7-86. The case of the

management is that the workman served under them on reappointment from 26-8-85 to 5-8-86 and absented himself from 6-8-86. I have to see which of the two rival versons

13. The managements claim that the workman voluntarily left the job. On 29-1-85 and was reappointed on 26-8-85 is evident from workmans averment in para 3 of the written statement of craim which reads as follows :-

"The workman states that he worked with respondents for the following period:

24-3-1978 to 18-6-1978, 21-6-1978 to 18-8-1978, 25-9-1978 to 18-1-1985, 26-8-1985 to 29-7-1986."

He does not explain his long absence from 19-1-1985 to 25-8-1985. He was a casual worker. He does not claim that he was on authorised leave from 19-1-85 to 25-8-85. This is not his case that this long break was artificially caused due to victimisation. His statement of claim and his sworn testimony are altogether silent on this aspect of the matter, though in cross-examination he demes the suggestion that he was reappointed on 26-8-85.

- 14. As against this, there is categorical statement of Managements witness P. G. Melkar that the workman was re-engaged on 26-8-86. In cross-examination, he has added that this statement is based on record and he has no personal knowledge in the matter. I have no reason to doubt this statement and it is in accord with the averment of the workman made in para 3 of the written statement of claim which shows that his last spell of service commenced on 26-8-86.
- 15. Now, the next question is if the workman had served from 26-8-85 till 29-7-86 as claimed by the workman or upto 5-8-86. On this point, the cross-examination of Mr. Pradhan contains a very varuable admission, which completely demolishes the case of the management. He says:

"This is correct that the workman had served for a period of more than 240 days in a calendar year preceding the date of his termination i.e. 29-7-86." For this statement, it can be safely concluded that the work-man served till 29-7-86. This also belies the claim of the management that workman worked upto 5-8-86 and absented himself from 6-8-86 and that his services were not terminated.

- 16. The stand taken by the management is that since the workman could not qualify medically, he could not have been regularised and hence his services were terminated and it was not necessary to comply with the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act. In my opinion, the management was within its right not to regularise the workman when he failed to qualify at the medical test. But this did not mean that he was not entitled to carry on in his status as a casual workman till proper termination and his services could have been terminated without complying with the provisions of Section 25F of the I. D. Act, Admittedly, since the workman had failed to qualify at the medical test, he could not be regularised. But this does not and can not mean that his casual services also automatically came to an end. To achieve this object, the employer could very well terminate his appointment but only after complying with the provisions of Section 25F of the I.D. Act, and not without resorting to provisions of the said section.
- 17. Hence, not withstanding the fact that the workman could not qualify medically and was not entitled for regularication, termination of his casual service w.e.f. 29-7-86, with at complying with the provisions of Section 25F of the I.D. Ac' is bad and unlawful and he shall be deemed to continue in the job as a casual workman w.e.f. 29-7-86 and is also entitled to backwages. However, on this basis, he is not entaged to claim regularisation and absorption. It is clarified that the management may still terminate the casual appointment of the workman but only in accordance with the provisions of Section 251 of the LD. Act and not other wise. In the circumstances of the case, employer shall pay costs of these proceeding which are assessed at Rs. 200/. Award is made accordingly. The same be notified in accordance with law.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई विल्ली, 15 मई, 1996

का.आ. 1671.--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनसरण में, केन्द्रीय रकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकोंन और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविध्य औद्योगिका विवाद में, केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, म्यबर्द नं० 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 14-5-96 को प्रध्यत हुआ था ।

[संख्या एल-12012/248/92-आई भार को आई] के० वी० वी० उण्णा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1671.-In pursuance of Section II of the Industrial S.O. 16/1.—In pursuance of Section II of the industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government industrial tribunal, Bombay No.-2 as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SBI and their workman, which was received by the Central Government on the 14-5-96.

[No. L-12012/248/92-JRB-I] K. V. B. UNNY, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 MUMBAT

PRESENT : Shri S.B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/18 of 1993

Limployers in relation to the management of State Bank of India.

AND Their Workmen

APPEARANCES:

For the workmen: Mr. H. G. Pandit, Representative. For the Management—Mr. S. K. Asthana, Representativt.
Mumbai, the 3rd April. 1996

AWARD—PART I The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-12012/248/92-IR (B-I) dated 24-2-1993 had referred to the following dispute for adjudication. It is in

the following terms.

Whether the action of the management of State Bank of India in imposing the punishment of withholding three increments w.c.f. 11-4-91, on Shri L. C. Dias is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

- 2. The State Bank of India and its subsidiary banks union raised a dispute before the Assit, Labour Commissioner on behalf of the worker Shri L. C. Dias. But when the matter came to be referred to the Tribunal the workman became the member of the State Bank of India staff union (Ex-3). It made the applicant to implede itself in the reference (Exhibit-2). The earlier union had no objection in the same. The result is that the State Bank of India Stall Union espouses the cause of the worker Dias.
- 3. L. C. Dias the worker was appointed as a clerk. He put more than fifteen years service without any blemish. On 5-4-1988 the Regional Manager (II) State Bank of India suspended him. It was alleged that the fraud which occurred at banks Nariman point branch resulting in monetary loss of made the applicant to implede itself in the forefence (Ex. Rs. 2 Lacs to it indicated the worker involvement in various acts, oramissions which is found proved constituted misconduct. He was informed that the departmental inquiry will be held against him and he will be paid subsistence allowance during that period (Exhibit-A).
- 4. On 2-6-1988 the worker wrote a letter (Exhibit-B), to the bank and informed that without the chargesheet being issued suspension is illegal. He asked for the chargesheet and documents relied by the bank. He also raised some other objections.
- 5. The chargesheet dated 4-10-1988 (Exhibit-C) served on the worker. It was alleged that on 20-11-86, the worker was working as a teller. He took undue interest in opening fictitious Current Account No. 3170 in the name of M/s. Jay Colours, Mr. Basu Roy was introduced by Mr. Hudalani, who had current A/c. since 2-2-1982. By opening the account the worker prepared payin-slip of Rs. 500 and endorsed on it as "New Account". The voucher was not initialled by supervisors. The worker accepted the amount without following the required procedure and thus committed misconduct. Consequently on 17-12-1986 a spurious telegram representing the remittance by telegraphic transfer of Rs. 2 Lacs puppor-

tedly send by Suri branch on 24-12-1986 in favour of M/s. Jai colours and on the same day a fake list of other originaing credits alongwith T.T. confirmmation purportedly sent by Suri branch was prepared by the workman. He had a fraudulent intention of proving or supporting the fake remittance and therefore committed the fraud on the bank.

- 6. Thirdry on 22-12-86 a fictitious account was opened in the name of M/s. High Constructions in the State Bank of Mysore at Bankman Point branch, M/s. Jai colours introduced proprietor Das as the prophetor of High Constructions. He was allowed to withdraw the amount of Rs. 2 lacs on different cheques. On the bansis of the telegram of Suri branch, The worker alone or with collusion of others prepared credit vouchers for crediting various amounts to the credit of the said account with a view to defraud the bank thus committed misconduct i.e. engaging in trade or business outside the scope of his duties except with the permission of the bank or any of its customers, undue disclosure of information regarding affairs of the bank or any customer or any persons business in the bank which is confidential or disclosure which is likely to prejudice to the interests of the bank and gross negligence which resulted in loss to bank.
- 7. On 2-10 1988 the worker wrote a letter (Exhibit-D) to the bank and asked for different documents relating to the chargesheet to file his say in the matter. On 1-11-1988 the bank informed (Ex E) to the worker that the originals are with the police and lie can see the photo copies of it from the manager Nariman Point Branch of the bank. The worker then called the bank on 10-12-1986 (Exhibit-F) to give him photo copies of all the documents which he asked earlier for sending it to the handwriting expert for interim examination. By the letter dtd. 16-12-88 (Exhibit-6) the bank asked the worker to collect the photo copies of the documents. The branch manager by his letter dtd. 4-1-89 asked the worker to collect the copies on 7-1-1989.
- 8. The worker was telegraphically (Ex-H) informed that Vidvaunsh would conduct the inquiry on 10-1-1989. The venue was also informed. On 9-1-89 the workmen informed that bank that Mr. Pandit the employee of the bank would represent his case (Exhibit-R).
- 9. On 10-1-89 Mr. Pandit the representative of the worker raised different objections to the said inquiry. The inquiry officer directed the representing officer to consider the objections. The inquiry was then adjourned to 12-1-89. On that date the inquiry officer disallowed the request to show the originals unless the name of the hand writing expert is disclosed and he overruled the other objections. The workman plended that the inquiry was started before obtaining say of the worker in respect of the charge sheet. It is asserted that the charges are vauge and issued after a lapse of two years.
- 10. The worker pleaded that the inquiry officer asked the presenting officer to present his case. Thereafter the defence representative was asked to say on the charge. Thereafter the winnesses were carmined. That was opposed by the worker contending that this is not proper practice. But again those objections were overruled.
- 11. The workman pleaded that the management examined the witness Sabnis and produced the documants, Later on the worker examined his witness and both the parties filed written briefs. The inquiry officer then submitted his report.
- 12. On 27-12-89 the inquiry was reopened to examine Wagh, handwriting expert of the bank. He could not be examined. Thereafter again the inquiry officer submitted his report.
- 13. On 24-1-1991 the bank send a show cause notice (Exhibit-K) to the worker contending that why the proposed runishment should not be awarded to him. He was asked to give his roply in the matter. He filed his detailed reply on 15-3-91 (Exhibit-1). On 5-4-91 the disciplinary authority passed the punishment.
- 14. The worker preferred an appeal against the said order which was rejected. It is contended that the personal hearing of the appeal was given by Mr. A. V. K. Poduval but the order was passed by Hemrajani which is illegal.
- 15. The worker pleaded that the inquiry was against the principles of Nauiral Justice. It is averted that the charge sheet was issued at a very last stage. That the statements and deuments on which the bank relied were not given to

him, that there is no evidence to come to the conclusion that the charges are proved. That the Appellate authority did not consider the submissions of the worker, that material questions were disaflowed by the inquiry officer, that no opportunity was given to the worker to give his say to the chargesheet, that the procedure was not followed properly, that Mr. Wagh the handwriting expert report was relied by the inquiry officer without giving an opportunity to cross examine him that the inquiry officer asked for the directions from the superiors which shows that he was not independent.

- 16. The union contended that the findings of the inquiry officer are perverse. They are not consistent with the evidence on the record. It is therefore, prayed that the reference may be answered in favour of the workman, that the period of suspension of the worker till his reinstatement in solvice be treated as on duty and difference in pay with 18 per cent interest thereon with other reliefs.
- 17. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-5. It is averred that Nariman Point Branch was defrauded of Rs. 2 Lacs in December, 1986 through a Take telegram purportedly representing remittance from Suri Branch (West Bengal) of the bank by telegraphic transfer favouring the newly opened fictitious current account in the name of M/s. Jai Colours at the branch. The proceeds of the telegraphic transfer were withdrawn in cash, through newly opened fictitious account with the State Bank of Mysore, Nariman Point Branch in the name of M/s. High Constructions. In the preliminary inquiry Dias was suspected as directly involved in the appropriation of the fraud. He was placed in suspension. There were three charges levelled against him. Even though severe punishment was warranted considering the young age of the employee he was given punishment of stoppage of three increments and the period of his suspension was treated as not on duty. He was reinstate in service and posted at another branch.
- 18. The management contended that the domestic inquiry which was conducted against the workman was as per the principles of Natural Justice. It denied all the allegations in respect of the domestic inquiry which were in the statement of claim. It can be seen that these allegations were denied by parawise denial. The management denied that the findings of the inquiry officer are perverse and illegal. It is submitted that the action of the management is just, legal and proper and the reference may be answered in favour of the bank.
- 19. I have framed issues at Exhibit-7. Issues No. 1 and 2 are to be tried at preliminary issues. The issues and my findings there on are at follows:

Issues Findings

Yes.

No

- 1. Whether the comestic enquiry held against the workman is legal and proper?
- 2. Whether the findings of the Enquiry Officer are perverse?

REASONS

- 20. The workman L. C. Dias examined at Exhibit-6. Ho relied upon the documents which he filed alongwith the statement of claim which I have already referred while innumerating the facts. He had also filed a circular No. 48 of 1960 dated 21-5-1969 alongwith Exhibit-12'. As against this the bank examined M. P. N. Bhatt, the Manager, Disciplinary proceedings section State Bank of India and I. N. Hemrajani, Assistant General Manager who decided the appeal of the workman and confirmed the punishment which was already granted. The bank also relied upon the documents which it filed alongwith Exhibit-6'.
- 21. In short charge No. 1 which was held to be proved against the workman was that the workman helped M/s. Jai Colcurs to open the fictitious account at Nariman Point Branch on 20-11-1986 by filling a pay-in-slip, mentioning the amount of Rs. 500 on it, without having initialled by the superior officers. It resulted into putting the bank to loss of Rs. 2 Lacs, with the help of telegraphic remittance of Rs. 2 Lacs from Suri branch and thus withdrawing this amount from fictitious account. It is not necessary for the to give details so far as charge Nos. 2 and 3 are concerned because they are ready held to be not proved.

22. On April 5, 1988 the workman was suspended. The chargesheet dated 4-10-88 was issued to him. The domestic inquiry was started against him on 10-1-89. The management examined the witness and produced the documents before the inquiry officer. The workman was represented by Mr. Pandit, the representative of his own choice. He examined the witness. Ultimately the inquiry officer send his report holding the workman guilty under charges 1 and 2. When the matter came before the disciplinary authority due to the representation of the worker he send back the proceedings back to the inquiry officer for examination of handwriting expert of the bank by name Mr. Wagh. Thereafter the inquiry officer submitted his second report wherein he came to the conclusion that the workman is guilty under the first charge and found him not guilty so far as other two charges are concerned.

23. In the statement of claim and in the written arguments it is tried to argue on behalf of the workman that the domestic inquiry which was held against him was against the principles of Natural Justice. To substantiate this contention he raised several points. Now I will discuss those points one by one.

DELAY:

24. It is alleged that the chargesheet is issued after a very long time which prejudiced him. I don't find any merit in it. It is because on 5-4-1988 the workman was suspended. On 4-10-88 a chargesheet was issued to him. In the said chargesheet it is mentioned that he had committed a misconduct on 20-11-86, 22-12-86 and 17-12-86. The details of charge I have already discussed while innumerating the facts. Thereafter the inquiry was started on 10-1-1989. From perusal of these dates within 1-1/2 year of the incident the worker was suspended and within 6 months of suspension he has issued a chargesheet. Thereafter within three months the inquiry was started. Looking to the graveness of the misconduct it cannot be said that there was a delay at all. The bank was defruaded of Rs. 2 Lacs. Some investigation was required to be done for coming to a conclusion. Therefore there is no merit in the contention that there is a delay.

VAGUE-CHARGES

25. The another contention of the worker is that the charges are vague. According to him Charge No. 1 for which the workman has been held guilty has not been defined as misconduct anytime anywhere in the declared acts of misconduct defined by Shastry Award of the Bi-partied settlements. It is argued on behalf of the management that Charge No. 1 for which the workman has been held guilty are amptly covered by para 521(4)(j) and para 521(c)(d) of the Shastry Award as clarified in para 2 of the chargeshaet. (i) refers to doing any act prejudicial to the interest of the bank or gross negligence involved or likely to involve the bank in serious loss and (d) refers to breach of any rule of business of the bank or instruction in the running of any department. The charge which I have already discussed above is very detailed. It covers the criteria mentioned in these two categories. After reading the charge I don't find any vagueness in the same.

NO OPPOUTUNITY OF EXPLANATION

26. The worker was served with a chargesheet dated 4-10 88 In paragraph-4 of that letter he was called upon to file his say in respect of the charges within seven days. Failing which it would be presumed that he does not want to give any say in the matter. In reply to the said letter the workman wrote a letter dated 22-10-88 (Exhibit-D) and requested for supply of different documents for filing his say. This letter was replied by the bank and he was informed that the copies of those documents are with the Police and that cannot be given to him. Thereafter by another letter the worker requested for supply of photo copies of those The management agreed to supply those conies documents. and called the worker to collect the same from the manager of the branch on 7-1-1989. It is not in dispute that the worker received the photo copies on that date. The inquiry was to start on 10-1-89. On that dete the inquiry started. The representative of the worker raired different objection on the very day. They were overruled. He did not file any say on the charges on that date. Now it is argued that an

opportunity was not given to him for filing the same. There is no merit in it. It appears that at an earlier stage as no say was field by the workman or on the date of the inquiry also he had not forwarded any application contending that he want to file a say to the alleged charges and it should be aken on the record. Now the contention raised by the workman that without obtaining his say the inquiry was conducted has no merit. For the sake of argument even if it is said that the workman filed his explanation to the charges the management was not precluded from conducting the domestic inquiry. No illegality is committed by not ascertaining or insisting the workman to file a say in the matter. On the contrary in the letter itself it is mentioned that if the say is not filed a domestic inquiry will the proceeded with.

The Learned representative of the union placed reliance on Shri Rasikalal Vamji Bhai Patel and Andhra Municipal Corporation and Anr. 1985 I LLJ 527. The facts of that case are quire different from the facts before me because I have already discussed above how the charges in this present matter are clear in its terms and as per the awards.

INCORRECT PROCEDURE

27. It is tried to argue on behalf of the workman that the inquiry officer did not follow a procedure at the time of domestic inquiry. It is tried to argue that the inquiry officer first asked the presenting officer to submit his case. Then they heard the worker and thereafter he recorded the evidence of the witnesses. I do not find anything wrong in it. In fact for domestic inquiry a procedure is to be laid down by the inquiry officer for the convenience. There is no strict procedure. I do not find any merit in the said contention. After persual of the proceedings of the departmental inquiry which are filed alongwith Exhibit-'6' I do not find that any illegality was committed by the inquiry officer.

SUPPLY OF DOCUMENTS AND COPIES OF STATEMENTS

28. It is argued on behalf of the worker that he demanded various documents which were useful for the purpose of defence. But he was not given the copies of those It is further argued that he was not supplied with the copies of the preliminary investigation report which was the basis of the workers suspension and further departmental inquiry. That resulted in to projudice to the worker. As against this the Learned Representative of the management contended that the copies of documents were supplied to the workers and no prejudice is caused to him. Shri L. C. Dias (Exhibit-9) in his cross-examination categorically stated that he was given all the decuments which he asked for. But they were given only three days prior to the starting of inquiry. By this it is tried to suggest that he could not get an opportunity to study the document and prepare himself in the matter. But this plea was never raised before the inquiry officer. It can be further seen that on the first day of the hearing no proceedings could take place due to the objections raised by Mr. Pandit the representative of the worker. He was also provided with banks hand writing experts report. He affirmed that the T.T. Voucher dtd. 18-10-86 shown to his defence counsel only. But it was not shown to him. When the representative is engaged it was not necessary for the inquiry officer to show that documents to the worker. No illegality is committed because of that. He admits to have received its copy but the scurity Number was blocked. He was als shown the leave ap-plications of Sabnis, Bhosale, DiSouza but the applica-tion of Suttar was not shown to him. Looking to the nature of the inquiry the necessary documents were shown to him. He had not shown how the prejudece was caused him by not showing the leave application of Suttar. He admits the fact that the original documents were not with the management and they were with the police. Naturally the original documents could not be shown, to the worker.

Bhatt and Hemrajani the witness of the bank affirmed that all the necessary documents were given to the worker. I find substance in their testimony.

It is tried to argue on behalf of the workman that he did not receive the statements of the witness, preliminary

investigation report and other documents from the police inquiry. No doubt he did not receive it. But what is to be seen is whether the inquiry officer relied upon. It. The auswer is no. Nodoubt on the basis of the preliminary investigation the management decided to hold a departmental inquiry. On its basis a chargesheet is framed and it was given to the workmen. The inquiry officer never relied upon the preliminary investigation report for coming to his conclusions. His report is based on the evidence and the documents which were produced before him. As these documents are irrelevant, Non supply of all these documents are irrelevant, Non supply of it to him had not caused prejudice to him.

The Learned representative of the bank to substantiate this contention placed reliance on J. N. Mathurji V. Unson of India 1959 I LLJ 11. His Lordships observed that when the inquiry officer did not rely upon the police report of other documents then its non supply to the worker does not vitlate the inquiry.

In TATA Engineering and Locomotice Co., Ltc. V. S. C. Prasad 1969 33 SCC 372 & State of Bombay V. Roj'bhai AIR 1961 Gujarat 130. Their Lordships have observed that ommissions to make available any preliminary report to the delinquent will constitute non observance of rules of natural justice only when the report form part of the evidence before the inquiry officer but not otherwise. The ratio in these authorities aptly apply to the set of facts before me.

NON OPPORTUNITY OF CROSS EXAMINATION OF WITNESS

29. It is tried to argue on behalf of the worker that he was not given an opportunity to cross-examine the witness. But that appeares to be in correct. It can be seen that Sabnis is cross examined. He was the witness for the bank. So far as the handwriting expert of the bank Mr. Wagh is concerned he was not examined when the first enquity report was submitted. It appears that due to the representation made by the worker and after that going through the record the disciplinary authority thought it fit to reopen the inquiry so far as the examination of Wagh is concerned. It was for limited purpose. The argument of the worker that it was reopened for filling up the gaps is without any merit. Infact by that the bank gave an opportunity to the worker in respect of the handwriting expert. It is pertinent to note that Mr. Wagh took several adjorunments to remain present before the inquiry officer. Atleast he was present before the inquiry officer on 19-2-1990. On that date his examination was not recorded nor cross examination could be done because the workman was not supplied with Juxta posed chart prepared by Wayh. It is alleged on hehalf of the worker that effective corss-examination could not be done without the same. That chart was misplaced by Wagh. The result was that there was no examination in chief nor cross examination. of Wagh.

Dias in his cross-examination stated that he was not to examine any of the officers of the State Bank of Mysore, He accepted that they were not his witness. According to him he could not corss-examine them as they were not examined by the bank. In fact so far as charge No. 1 is conceined the testimony of these witness have no relevancy. But further more when there was no examination in chsef there was no question of corss examination. Looking to the inquiry proceedings it could be said that the worker was denied an opportunity of corss examination. There is also a contentson that he was not allowed to put relevant question and they were disallowed. This argument appears to be for the sake of the same.

CRIMINAL CASE

30. It is argued on behalf of the worker that a police case was filed by the bank and after investigation the police asked for 'A' summary. The Asst. Commissioner of Police cranted the same. It is therefore submitted that it was wrong on the part of the bank to issue a chargesheet to the worker and is a violation of para 505 of the Shastry Award.

To meet out this argument the Learned Representative of the bank submitted that it did not violate paragraph 505 of the Shastry Award and granting of 'A' summary dsd not preclude the bank for starting departmental inquiry. Paragraph 505 of the award states that "if there is a acquittal the criminal should not be lightly thrown away when there is no inquiry against that particular accused or worker in the bank. It is well settled law that the findings of the criminal court or the decision therein does not effect the domestic inquiry. It can be seen that the evidence required in a criminal proceedings namely proving the offence is quit different than the evidence required in a domestic inquiry. In a criminal proceedings the guilt has to be proved beyond doubt but so far as the domestic inquiry is concerned it rests on preponderance of probabilities. No illegality is done by the bank while not giving any attention for grating 'A' summary to the criminal case.

CONSIDERATION OF APPEAL

31. It is submitted that the workman preferred an appeal which was heatd by one A. B. K. Pouduval, but the order to that effect was passed by Hemrajani. He is the witness for the bank. He affirmed that he had gone through the proceedings and the written submissions made by the worker and he then passed an order. He admits the position that he had not given personal hearing to the worker. But the personal hearing was given by his predecessor. As the written arguments were there on the record I do not think that it caused any prejudice to the worker by not granting personal hearing by Hemrajani. It cannot be forgotten that this is an appeal and no evidence is recorded before the Appellate authority. He has to disposed off the matter on the basis of the record and the submissions. So far as oral submissions are concerned there are written submissions which he considered. It can be further seen that his order is well reasoned and the centention of the worker that he did not consider his submissions has no merit.

Dias in his cross examination admitted that the charge sheet was issued to him by the competent authority. It is not in dispute that he was represented by the representative of the union by his choice. The representative and the worker were present throughout the inquiry and participated in the same. For all these reasons I find that there is no substance in the argument of the worker that the domestic inquiry which was held against him was against the principles of Natural Justice.

Now it has to be seen whether the findings of the inquiry officer are preverse. It is tried to submit that the inquiry officer was taking instructions from the management. But in the cross exemination the worker had admitted that he had no evidence to show that the inquiry officer was taking instructions from the management regarding the conduct of the inquiry. It is also submitted that the inquiry officer was fally in the hands of the management. But after noing through the inquiry proceedings and the reports on the record I am not inclined to accept this submission.

It can be such by the order dated 14-12-89 the inquiry was remembed with a recrified direction that the handwriting evnert We be descrition has to be recorded and an oncor-tunity has to be given to the worker. But that could not done after viving sufficient opportunity to the management Intermetally the inquiry officer proceeded to submit his report. He made his first second deted 30.9-80 he found the worker unity of the first can charges and all ends of the third charge. But when he submitted his second report on 2-4-90 after renoming of the inquiry as per the direction concluded that the workman is ender of the first charge and not milty of the second and third charge. If really this inquiry officer would have been fully in the hands of the management he could have confirmed his earlier report. But it appears that be (bought it fit to give different findings than the earlier due to the change in circumstances. In fact this reopening the inquiry helped the worker and not the management. It is tried to name on behalf of the worker that there was no change in circumstances therefore the findings are reverse. I may not inclined to accept it. It is because the inquiry officer had given reasons for coming to the conclusion that charge No. 2 is not proved. In fact I am concerned with Charge No. 1 only.

officer has placed reliance on the report of the handwriting

expert. This is in correct. It is because the worker could not get an apportunity to cross examine the expert and to bring on the record the follies he committed. Naturally the reliance placed by the inquiry officer on the handwriting experts report for coming to the conclusion that the worker is guilty under first charge cannot be said to be correct. But the inquiry officer had also given other reasons for coming to the conclusion why the worker is guilty under first charge. Now it has to be seen leaving aside the reasons, leaving aside the experts evidence whether there is sufficient record on material for coming to the same conclusion. If that is so the finding cannot be said to be perverse.

Dias admitted that he wrote on the pay-in-slip "New Account" and "Rs. 500 only" on the cash voucher. He admitted that the teller where he was working was expected to receive the amount only after completion of the formalities of the account opening by the concerned officer. He further deposed that there was no such rule of a concerned officer signing or initialling the pay-in-slip for information that the procedure for opening the account was completed. He further stated that previously there was such a practice but now it is stopped. There is a circular to that effect bearing No. 40 of 1969 (Ex.-12/1). In other words the whole case of this worker is based on this circular by which he wants to contend that he had not committed any negligence as stated to be proved by the bank.

The circular reads as follows: "It has come to our notice that at some Branches it is the practice to accept all cash deposits only after the remtive cash pay-in-slip has been initialled by the concerned counter-clerk. This, we understand, is done with a view to ensuring that the money is deposited for credit of the correct account. The matter has been examined by us. As the depositors find it irksome to move from counter to counter when they come to deposit money in the Bank and as normally the depositors are quit careful while deposition money, it has been decided to direcutinue this practice with immediate effect in so far as only current and savings banks accounts are concerned. This will improve our customer service and eliminate avoidable delay. The practice should, however, continue unchanged in case of cash deposits tendered for issue of fixed deposits, drafts, mail/telegraphic transfers, realisation of bills etc., as complications may arise if the depositors fill in incorrect rates of interest and exchange etc. Please ensure accordingly."

From reading the circular it does not reveal that at the opening of the account there is any need of signing by the concerned counter c'erk. On the contrary there are certain categories such as in the case of cash deposits, for issue of fixed deposits, drafts, mail telegraphic transfers. Realisation of bills such practice was to continue. In fact this is the opening stage of the account. Therefore it appears that this practice was to continue. But the further deposits are concerned there is no need to do so as the customers were affected. At this inneture the workman submitted that in the inquiry proceedings, they have brought on the record that without such initials the accounts were opened. I am not concerned with that. It is because I have to see whether the findings of the inquiry officer are perverse. After considering this circular and from the report of the inquiry office it reveals that he did consider the said circular and came to the conclusion that it has no application. I endorse the view, after persual of the inquiry officers report dated 2-4-1920. It is alonewith Exhibit-6. I do not find any perversity in it. In the result I record my findings on the points accordingly and pass the following Order:

ORDER

- The Demestic inquiry held against the workman is legal and proper.
- 2. The findings of the inquiry officer are not perverse.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 मर्र, 1996

का॰आ॰. 1672:—-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एक सी धार्द के प्रबंधतंत्र के संग्रह नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदर्ध

आंद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार आंद्योगिक अधिकरण सम्बर्द नं 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-5-96 को प्राप्त हुआ था।

> [सं० एत⊶22012/411/एक/91⊸पाई प्रार (सी-2)] राजालाल, डस्क पश्चिकारी

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1672.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay No. 2 as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on the 10-5-1996.

[No.22012]411[F[91-IR(C-II)] RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 MUMBAI PRESENT:

Shri S. B. Panse Presiding Officer

(Old. Reference No. CGIT-2|5 of 1992) Reference No. CGIT-2|15 of 1996

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the workmen: Shri S. R. Wagh Advocate. For the management: Shri B. M. Masurkar, Advocate.

Mumbai, dated 28th March, 1996

AWARD

The Government of India, Minis'ry of Labour by its order No. L-22012(411)|F|91-IR(C-II), dated 29-1-92, had referred to the following Dispute for adjudication.

"Whether the action of the workmen of Bombay Godowns and Manmad Depots of Food Corpn. of India, to prevent 49 workers t ransferred from Kandla to work at Bombay Godowns and Manmad Depot is legal and justified and or amounts to unfair labour Practice? If so, to what relief are the management entitled to?"

- 2. The senior Regional Manager of Food Corporation of India contended that there was on work for the workmen of the Food Corporation of India working at Kandla Port since the year 1980 due to cessation of imports of food grains. The result was that the workers who were handling the food grains became surplus. They were to be kept idle but the management continued to pay them their wages.
- 3. The workers working at Kandla Port were governed by non-registered dock workers (Regulations of employment) since 1968 which was framed

4

5. What Award?

under the Dock workers (Regulations of employment) Act of 1948. Under the said Act the employer is bound to pay the minimum guaranteed wages to the workers even though they remained idle. This situation had to be remeded. It is therefore, in consultation with the transport and dock workers union a scheme was devised for special Voluntary Retirement Scheme.

- 4. At Kandla there were 1590 surplus labourers. Out of them 1541 workers opted for "Special Voluntary Retirement Scheme". In the mean time the Government revoked the Kandla Non-Registered Dock workers Regulation of Employment Scheme. The result was that the remaining 49 workers came out of the said scheme. At this sage the union by its letter dated 17-7-1986 requested to devise a scheme for employing the surplus labourers by transferring them outside Kandla.
- 5. The management pleaded that thereafter the workers were asked their option to be transferred at Bombay or at Manmad depot. 18 workers opted for Bombay and 31 workers opted for Manmad. One worker had not given any option. The result was that he was retrenched following the procedure under section 25-F of the Industrial Disputes Act of 1947.
- 6. The workers were given transfer orders and T.A&D.A. to join their respective posts. The management provided them specific duties in the respective godowns to work from 8-3-88. The workers who were already working at respective depots and members of the Transport and Dock Workers Union. Bombay (herein af er called as the Union) joined the strike without prior notice to the management. The Union had also written another letter dtd. 29-1-90 wherein they mentioned that they opposed these workers who are transferred to Bombay and Manmad from Kandla and to ask the management to retransfer them to Kandla.
- 7. The management pleaded that the action of the union is against the principles of Natural Justice. Now the union cannot go back on their own promises. It is averred that by not allowing the workers to work is unfair labour practice within the meaning of section 25T read with items 1 and 8 of the Fifth Schedule of the Industrial Disputes Act of 1947. It is averred that due to the act of the union the management is put to loss of lacs of rupees. It is therefore prayed that an action may be taken against the union for practicing unfair labour practice and it may be declared that their action is illegal and unjustified.
- 8. The Union resisted the claim by the written statement Exhibit-'3'. It is averred that that Industrial Dispute does not exist between the management and the union. It is therefore, the Tribunal has no jurisdiction to try the reference. It is asserted that the union never consented nor consulted for transfer of 49 workers from Kandla to Bombay or Manmad depost. It is averred that the job of the workers in the Food Corporation of India is non transferable. It is therefore, the transfers are illegal. It is pleaded that the alleged discussion which took place between the management and the Transport and Dock workers Union, Kandla had nothing to do with the union, the opponent. It is submitted that it never indulged 1292 Gl 96—14.

in unfair labour practice. It is submitted that the actions of the workman of Bombay Depot and Manmad Depot of Food Corporation of India in preventing those 49 workers is illegal and justified. It is therefore prayed that the reference may be answered accordingly.

9. My Learned Predecessor framed issues at Exhibit-4. The issues and my findings thereon are as follows:

Issues	Findings
1. Whether industrial dispute existed between the workmen in question the transport & Dock workers union, Bombay and the management of the Food Corporation of India?	Yes.
 Whether the 49 workmen in question were re-eployed at Bombay and Manmad Depot with the prior approval of the Transport and Dock workers Union, Bombay? 	They are not re- employed but they are s transferred from Kandla to Bornbay and Manmad with approval of the Transport & Dock Workers Union Bombay.
3. Whether the action of the workmen of Bombay Godowns & Manmad Depots of Food Corporation of India to prevent 49 worker transferred from Kandla to work at Bombay Godowns and Manmad Depot is legal and justified and/or amounts to unfair labour practice?	The action is not legal. & Justified, It does not amount to unfair labour practice.
4. If so, to what relief are the management entitled to?	As per final order.

~REASONS

As per final order.

- 10. From the testimony of A. Kannapiram (Ex.-'6' The Deputy Manager of the Food Corporation of India, Manohar Gopinath Kotwal (Ex-'18') and Nathu Dadu-Kamble (Ex-9) the Joint Secretary of the Union the following facts could be said to be undisputed. At Kandla the workers were working under the Kandla Non-Registered Dock workers Regula ion employment scheme. Due to the cessation of import of food grains there was no work for the workmen since 1980. A Voluntary Retirement Scheme was introduced. Out of the excess workers 1540 workers opted for Voluntary reitrement under the said scheme. The result was that 49 workers remained there as surplus.
- 11. Out of the 49 workers 18 workers were transferred to Bombay and 31 workers were transferred

to Manmad who opted for the same. One worker who did not opt for transfer nor the voluntary retirement scheme was retrenched. The Government revoked the scheme of Kandla Non-Registered Dock Workers (Regulations of Employment Scheme). The result was that these surplus workers were not protected.

- 12. Manohar Kotwal admits the letters dtd. 17-7-86 and 29-1-90 which are at Exhibit! '7|1', and Exhibit-'5|1' respectively. There was an agreement between the management and the union on 3-5-1986 (Ex-5|2). These workers were transferred to Bombay and Manmad after giving T.A.&D.A. and were asked to start work from 8-3-1988.
- 13. Kotwal affirmed that the letter dated 17-1-86 (Ex-7]1) was written by him as the President of the Transport and Dock Workers Union, Kandla Port, Kandla. It is not in dispute that at the same time Mr. Ko wal was the General Secretary of the Transport and Dock Workers Union, Rombay. It is tried to argue on behalf of the union that these two unions are registered at two different States. There is no dispute over it. It is ried to argue that these are registered under Trade Unions Act and are body corpora'es. These bodies have different views. The Learned Advocate for the union argued that it is likely that one man is the director for two different union i.e. two different body corporates and their approach to a praticular problem may differ. According to him it cannot be said thar as one man is the Director of two bodies his views should be the same. This anology has no meaning. It is because Mr. Kotwal who wrote a letter as President of Transpor and Dock Worker Union, Kandla had categorically stated in the said letters: "Many of the loaders are around 25 years of age. They have worked only for 7 to 8 years. They are willing for transfer to Bombay godowns rather than resigning and getting paid the benefits of the scheme. I welcome their suggestion on the ground that there are already 400 vacancies to be filled at Bombay godowns. Moreover, Food Corporation of India will not be required to pay them under the scheme. They can be transferred alongwith their funds, gra'uity, etc., as departmental labour to Bombay." This has reference to the settlement dated 3-5-85 (Ex-5/2). There were many vacancies at Bombay Port. In the le'ter dtd 17-7-86 there is a reference to these vacancies at Bombay. The whole letter had to be read as one document. There were complaints from the workers to Mr. Kotwal. While dealing with these complaints he had written a lefter. It is tried to argue on behalf of the management that Kotwal welcomed the idea of transfer, meaning the idea was not his but of somebody eles. From the letter it reveals that as he was dealing with the complaints of the employees, the suggestion might have come from them. That suggestion was welcomed by him and he ultimately suggested to the management. It is tried to argue that for the sake of argument it is accepted that Kotwal suggested or accepted the transfer they were only in respect of the loaders. He affirmed that as per his knowledge there are no loaders in those 49 workers. The paragraph which I have refferred to above refers to many of the loaders who suggested the transfer. It does not necessarily

- mean that all of them were loaders. It can be further seen that it is tried to argue on behalf of the union that as the loaders were from Maharashtra, Kotwal consented for such transfer. I am not inclined to accept this.
- 15. As I have already stated above Mr. Kotwals' position is quiet different. No doubt he wrote a letter as the President of the Transport and Dock Workers Union, Kandla, but at the same time he was the General Sec. of the Union. He was aware that there were about 400 vacancies at Bombay which he referred in the letter. From the tenore of the letter it clearly suggests, that he accepted the position that the excess workers a Kandla are to be transferred to Bombay and Manmad. It is because of that letter the management aske for the options from the worker and then their transfers were effected at Bombay and Manmad as per their choice.
- 16. It is tried to argue on behalf of the union that now the management is giving work on contract at Kandla and they can transfer back these workers there. For deciding this reference it is not necessary for me to see whether the work at Kandla is given on contract to not. The Learned Advocate for the union placed reliance on the workmen of Food Corporation of India V.M/s. F.C.I. AIR 1985 SC 670. That case refers to non issuance of notice of change and giving the work on contract basis. The facts before me are quiet different and it has no application.
- 17. One of the argument which is adduced on behalf of the union that the job of these workers is not transferable. This is not in dispute. It is because the loaders and other workers who are from other region are member of the union. It can be seen that when Mr. Kotwal is the President of the Transport and Dock workers union at Kandla he is representing the workers of that region. His status is quie different. He cannot be said to be a man of protecting interest of the loaders of workers of Maharashtra only.
- 18. Exhibit-'5|1' is a letter addressed by Mr. Kotwal as the Secretary of the Transport and Dock Workers Union, Bombay to the Management. In this letter he had suggested that those workers should be transferred back to Kandla as there is sufficient work He has also mentioned that no sons or relatives are taken to employment as per agreement (Exhibit-'5|2') dtd. 3-5-85. That agreement speaks of the employment of some of the workers wherein it is mentioned that the management and the union have to take joint veture to fill up all the vacancies keeping in view all the provisions of law. In this letter Mr. Kotwal have no where stated that as the workers who are transferred are no loaders and they are therefore onposing their transfer. Now the stand which is taken by them appears to be after thought and cannot be accepted. Here in this case there was a letter of the President of the Transport and Dock Workers Union. Kandla. He was the Secretary of the Union when the excess workers could be transferred. Not only that the workers opted for such transfer and thereafter the management effected those transfers. Therefore, I do not find any meri- in the argument that the transfers cannot be effected.

- 18. The 49 workers were not allowed to work. Their right to work is disturbed by the member of the union. It is therefore the management raised the dispute before the Assistant Labour Commissioner which came to be referred to this Tribunal. It is tried to argue that the union had no hing to do with the dispute has no meaning. It is because of their action these workers could not work. And therefore it has to be siad to be an Industrial Dispute and the Tribunal has the jurisdiction to decide i'.
- 19. So far as unfair labour practice is concerned there is no sufficient evidence. From the wirtten argument which is addressed on behalf of the management it can be said that there is no serious challange in respect of unfair labour practice. Manohar Kotwal was examined by the management after the reference was remanded back for hearing by the High Court of Bombay in Write Petit ion No. 2107 of 1991. Nathu Dadu (Ex-9) the Joint Secretary of the Union affirmed that they were not aware of the letter written by Kotwal to the management. Infact they are of the opinion that the President of the Transport and Dock Workers Union, Kandla and their union are different and the action which is taken by Mr. Kotwal does not bind them. It appears to me therefore they had resorted to the present action. Looking to the Fifth Schedule the action of these worker cannot be said to be an Unfair Labour Practice.
- . 20. Before passing the final order I may ment on it here that it appears that at present there is sufficient work at Kandla. To avoid the dispute between the parties and if the workers are now willing to go back to Kandla the management may consider their requests.

ORDER

- 1. The action of the workmen of Bombay godown and Manmad Depots of Food Corporation of India to prevent 49 workers transfer from Kandla to work at Bombay Godown and Manmad Depot is not legal and justified.
- 2. It does not amount to unfair labour practice.
- 3. No order as to costs.

S. B. PANSE, Presiding Officer नई विस्ती, 15 मई, 1996

कारुआर 1673.—-आँखोनिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एघर एस्डिया के प्रबन्धतव के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई नंउ 1 के पंचपट को प्रकाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[एल-11012/13/88-डी-2(ब्री)/डी-3(ब्री)/आईआर मी-<math>1] ब्रज मोहन, डैस्क ब्रधिनारी

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1673.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay No. 1 as shown in the Annexure

in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air India and their workmen, which was received by the Central Government on 14-5-1996.

[No. L-11012/13/88-D.II (B)|D.III (B)|IR (C-I)]/ BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY

PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer. Reference No. CGIT-1/17 of 1989

PARTIES:

Employers in relation to the management of Air-India, Bombay

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the management—Shri A. R. Kulkarni, Advocate.

For the workman-Shri Nabar, Advocate.

INDUSTRY: Anlines STATE: Maharashtra

Mumbal, the 29th day of March, 1996

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour has referred the following dispute to this Tribunal vide order dated 5-4-1989.

- "Whether the action of the management of Air-India in not paying the full wages to Shri M. Ratnakar, Store-Keeper for the period of his suspension from 16-10-80 to 28-10-84 and reducing his basic salary by one stage for a period of one year from 1-11-85 and not clearing his increments from June, 80 to June, 85 and not promoting him to the post of Sr. Store Keeper from 1-1-79 and subsequently to the post of sectional Store Keeper from 1-1-1982 is justified. If not, what relief is the workman entitled to?"
- 2. The workman filed his written statement of claim on 20-7-89. The employer filed its reply to the written statement of claim on 20-11-1989.
- 3. Both the parties took much time in producing documentary evidence. In oral evidence, the workman filed his affidavit on 14-9-1993. It appears that he was not subjected to any cross-examination inspite of the fact that he appeared in person on 13-1-94, 24-3-94, 29-4-94 and 19-10-94. The management stated on 5-9-95 that it did not want to lead any oral evidence. Meanwhile the matter did not proceed further because of pendency of some departmental representation of the workman. Some time was taken in attempts to settle the dispute outside the Tribunal All this took some time and contributed to delay in disposal of this old matter.
- 4. The matter came up before me for the first time on 5-9-1995. Parties took some time in arguing the matter and the arguments were concluded on 22-2-1996 when the matter was reserved for aware. Before the award could be dictated, the sole Stenographer of the Tribunal resigned All this has again contributed to delay in disposal of the case.
- 5. Briefly stated, the facts resulting the disputes referred for adjudiction of this Tribunal are as follows:

Workman Shri M. Ratnakar was working as a Store Keeper under the Air India Corporation since 29-5-1967. In contemplation of a departmental enquiry against the porkman for alleged misconduct, he was placed under suspension by the competent authority vide an order dated 18-4-1980 w.e.f. 16-4-1980. The management, however, did not issue a chargesheet to the workman for almost a period of 4 years. On 6th April, 1984, the workman was served with a chargesheet, the material part of which

detailing the alleged misconduct of the workman reads as follows:

"From

Stores and Purchase Department, A.I., Santa Cruz.

To

Mr. M. Ratnakar, Storekceper, St. No. 12478, B-160 A.I. 2nd Colony, Kalina, Santa Cruz (East), Bombay-400029.

Ref. No. CSP/114-MR

dated 6th April, 1984.

This is in continuation of our letter No. CSP/114-MR dated April 18, 1980, placing you under suspension pending enquiry with effect from April 16, 1980 in view of the position stated therein:

- 2. It is reported that one Dr. (Miss) Sharda Rao, an Indian National, who is residing in London and who is known to you, came to Bombay on 9-2-1980. She stayed in her flat in Bombay and left Bombay on 29/30-3-1980 by Singapore Airlines for London.
- 3. Miss Maria Abranches, a Kenyan National, also came to Bombay from London on 20-2-1980. Thereafter, one Mr. Charles Thyes, a Belgian National came to Bombay on 3-3-1980 from Geneva.
- 4. Both Miss Maria Abranches and Mr. Charles Thyes stayed at Taj Hotel in Bombay and left Bombay on 12-3-1980. You had met all the aforesaid three persons during their stay in Bombay.
- 5. It is reported that while you were working as a Store-keeper in Stores Department during the period from February 1980 to April 1980, you have assisted the persons mentioned in para 2, 3 and 4 above, in booking the consignments declared as tourist purchases with Air India, the details of which are given below, with an intention to obtain pecuniary gain unlawfully to you, in gross violation of Customs Act. You have thus misused your official position as Storekeeper in Air India.
- 6. During her stay in Bombay, Dr. (Miss) Sharda Rao sought your assistance in booking the consignments declared as tourists purchases with Air India and for further expediting their early shipments. It is reported that Dr. (Miss) Sharda Rao booked the following consignments with Air India Cargo Booking Office, Bombay.
 - 1. No. 000051/1,3.80 Exporter: Dr. (Miss) Sharda Rao, Consignee: Dr. Sharda Rao, C/o Mr. M. Bocard, 25, RUE DE L'AL QUERUSE GENEVA SWITZERLAND—one wooden box containing tourist parchases valued at Re. 4,317 (AWB No. 098 28119921 dated 1-3-1980).
 - No. 004086/11-3-80. Exporter: Miss Maria A. Abranches C/o. Dr. Sharda-Raq. '5' Ashwin House, K. A. Subramanian Road. King's Circle, Bombay—! Two wooden boxes contents declared as Tourists purchases valued at Rs. 7849.25. (AWB, Np. 098-28120504 dated 8-3-80). The consignee—Miss Maria A. Abranches C/o. Mr. Albert, Att-Serge Waillound C/o. Daazas S. A. Fort-France, Route Des Scannes, Geneva, Switzerland.
 - One wooden box—contents declared as Tourists purchases valued at Rs. 8,547.00. (AWB. No. 098-28203792 dated 29-3-1980) Consignes Miss Sharda Rao C/o Damzas SA Port France, Route Den Sennes, Geneva, Switzerland, Exporter—Miss Sharda Rao.
 - One wooden box—contents declared as Tourists purchases valued at Rs.: 4,584.75 (AWB: No. 098-28203803 dated 29-3-1980). Exporter: Miss Sharda Rao, Consigne: Miss Sharda Rao, C/o Damzas SA Att. Mr. Serge Wuillound, Port France, Route Des Seannes, Geneva, Switzerland.:
- 7. You had accompanied Dr. (Miss) Sharda Rao to Air India, Cargo Booking Office, Bombay, for bookings

- on all the above mentioned three dates viz. 1-3-1980, 8-3-1980 and 29-3-1980.
- 8. It is further reported that on 1-3-1980 after booking the first consignment, (included in para 6.1 above) you also went to Sahar Cargo Complex and remained present at the time of examination of the said parcel by the Customs Examiner Mr. Baretto. However, you were not allowed by the Customs Examiner to remain present at the time of the examination of the contents of the parcel. After the parcel was passed and cleared by the Customs, it was lying for shipment by Air India (Cargo Complex, Export Section) which was not likely to be shipped due to the heavy backlog. Therefore, you accompanied by Dr. (Miss) Sharda Rao, met Mr. R. R. Puranik, Chief Traffic Asst. of Air India Cargo Complex, Export Section. You introduced yourself as an Air India employee and the relative of Dr. (Miss) Sharda Rao, though in fact, you were not related to her. At the request of Dr. (Miss) Sharda Rao, made to Mr. Puranik, the parcel was taken to the Air India Warehouse for shipment on 1-3-80 and thereafter it was shipped. Dr. (Miss) Rao had told the Customs House Agents representative that you would attend to the matters relating to the shipping of the parcel by Air India after the Customs formalities were observed.
- 9. The second consignment mentioned in para 6.2 above, was booked on 8-3-80 and examined by the Customs on 11-3-80. In this the Exporter was Miss Maria Abranches. The Customs House Agent's representative and you were present when the boxes were examined by the Customs For this consignment also you had met Mr. Puranik, Chief Traffic Asst. for immediate shipment after the customs examination, but he did not accept your request. Thereafter the boxes were shipped in the routine course.
- and 4 in para 6 above, were booked separtely by Dr. (Miss) Rao. You were present at the time of booking at Air India Cargo Office. Three to four days thereafter, you made enquiries with Air India Cargo Booking Office and the Customs House Agent's representative about the position of the said two parcels. You were told that the customs formalities were being observed. You went to Sahar Cargo Complex on 14-4-1980 on which day the said two parcels were being examined separately by the Customs Examiners—M/s. Baretto and Ghule in the presence of the Customs House Agent's representatives. You had earlier on that day met Mr. Puranik, Chief Traffic Asst. and had orally requested him for shipment of the parcels. Mr. Puranik dunted to remain present at the time of the examination of the parcels by the Customs, but the Customs Examiner Mr. Baretto asked you to go out. Thereafter, you left the Customs Examination shed and remained outside. M/s. Baretto and Ghule, the Customs Examiners, detected false bottom in the two wooden cases of parcels and they found silver bars collectively weighing 101.87 kgs., valued approximately at Rs. 2,62,348 at that time. When you came to know about the detection of silver bars in the false bottom as aforesaid, you immediately, left; the place and went home.
- 11. During the search of your residential premises on the night of 14-4-80, the Customs Authorities recovered a diary showing the names and addresses of Miss Sharda Rao, Miss Maria Abranches and Charles Thyes. A cover showing the name and address of Mr. Charles Thyes was also found in your house.
- 12. In your statement dated 16-4-1980 before Supdt. of Customs, Air Intelligent Unit, Bembay, Mr. P. Chakrapani, you have admitted having received Rs. 1500 from Dr. (Miss) Sharda Rao, for providing assistance in booking the packages referred to above, before she left for London. It was not a part of your duty to assist the travelling passengers for observing booking formalities of the parcles and thereafter making efforts for their early shipment through Air India.
- 13. It is clear from the above, that you took personal interest in expediting shipment, of consignments booked by Dr. (Miss) Sharda Rao by approaching the concerned Air India staff, though it was not a part of your duty at all. You thus acted in a manner unbecoming of an Air India

employee by conducing yourself in a manner not conducive to the best interest, credit and prestige of the Corporation.

- 14. You are, therefore, hereby charged with the following acts of misconduct:
 - (i) Aiding in smuggling of silver.
 - (ii) Taking illegal gratification.
 - (iii) Conducting yourself in a manner not conductive to the best interest, credit and prestige of the Corporation.
- 15. You are hereby called upon to submit your written explanation to the above charges within 7 days of the receipt of this letter. If not written explanation is received from you within the stipulated period, it will be presumed that you have no satisfactory explanation to offer and we will proceed to take further suitable disciplinary action against you, in accordance with the provisions of the Air India Employees Service Regulations.

16. If you desire to be heard in person, you may please let us know accordingly.

Sd-

(P. D. Marathe) Controller of Stores and Purchases"

- 6. The workman filed a detailed reply to this chargesheet vide letter dated 24th April, 1984, wherein he denied the allegations and charges levelled against him.
- 7. It appears that meanwhile a criminal case was also registered in connection with the alleged smuggling of the contraband. However, eventually the workman informed the management about this discharge. Upon this, the management revoked the order of suspension by an order dated 25-10-1984. The workman resumed his duties on 26-10-1984.
- 8. Meanwhile, an enquiry committee was appointed to go into the charges levelled against the workman. The enquiry Committee initially met on 12th July, 1984. The enquiry proceedings were concluded sometime in August 1985 and report was submitted by the Enquiry Committee on 948-1985 to the Disciplinary Authority. The Enquiry Committee came to the conclusion that charge No. 1 viz. that the workman aided and abetted in the smuggling of silver as alleged, was not established. However, it found that the workman had taken illegal gratification of Rs. 1500 from Ms. Sharar Rao and assisted her, an outsider, in booking certain cargoes and thereby conducted himself in a manner not conducive to the best interest, credit and prestige of the Corporation. The Disciplinary Authority agreed with the findings of the Enquiry Committee and held the workman guilty of the aforesaid charges (ii) and (iii). He, therefore, by order dated 29-10-85 (Ex. W-9) imposed punishment of reducing the workman in the pay scale to one stage below the basic salary for a period of one year from 1-11-1985. The increment which fell due during the period June 1980 to June, 1985 were also ordered to be withheld for the said period of one year. The relevant portion of this order reads as follows:

The misconduct committed by Mr. Ratnakar is of a serious nature and calls for severe punishment, but having regard to the fact that he was under suspension for a long period pending completion of proceedings, as well as the long interval between his arrest and conclusions of the proceedings of the Enquiry Committee. I feel that the ends of justice are met if Mr. Ratnakar is given the punishment of the reduction of his present basis salary by one stage, for a period of one year with effect from 1-11-1985. Further, the increments which were due during the period June 1980 to June 1985, which have been withheld pending the completion of enquiry proceedings, would also not be released during, this period of one year. The effect of this punishment is that the basic salary of Mr. Ratnakar would be reduced to Rs. 575 with effect from 1-11-85, for a period of one year. On the expiry of this punishment, the basic salary of Mr. Ratnakar would be fixed at a stage which he would have drawn normally i.e. Rs. 830, but for the punishment imposed under this Order,

provided his conduct and work are found-satisfactory during this period.

- Mr. Ratnakar is warned to be extremely careful in future.
 - I order accordingly."
- 9. The workman took the matter into appeal before the Controller of Stores and Purchases; who upheld the order of the Disciplinary Authority and dismissed the appeal vide order June 6, 1986.
- 10. The workman took the matter before Assistant Commissioner of Labour. The claim of the workman was admitted in conciliation. However, the dispute could not be settled and a failure report was submitted whereupon the appropriate Government made a reference as stated above.
- 11. Before, I proceed further, I would like to advert to the findings of the Enquiry Committee upheld by the Disciplinary Authority quasall the three charges. These findings occur in paras 23.1 to 23.3 (both inclusive) of the report of the committee and may be reproduced in extenso. They read as follows:
 - "23.1 Charge No. 1.—Aiding in smuggling of silver.—As per the reasons mentioned above, Committee is of the opinion that as per the evidence with the Committee, there is no direct involvement of Mr. Ratnakar in aiding of smuggling of silver and therefore this charge cannot be sustained. Even though there is evidence about his presence at the time of booking and Customs examination of consignments from which solver was in fact found, these facts by themselves and without any other evidence do not point to the guilt of Mr. Ratnakar Mr. Ratnakar presumably was not aware of the fact that the consignments for which he has requested Cargo Staff for expediting shipments, were containing silver. It has also come on record that when Dr. Miss Sharda Rao requested Mr. Ratmakar to help her in smuggling silver, he refused to do so and informed that he would never do such a This shows the conscientousness of MA Ratnakar that he was not prepared to assist Miss Sharda Rao for exporting the silver slabs. On the contrary, he ignorantly requested the Cargo Staff to expedite the consignments booked by Miss Sharda Rao since she was known to him. The Committee therefore finds him not guilty of this charge.
 - 23.2 Charge No. 2.—Taking illegal gratification.—There is no other evidence except the statement of Mr. Ratnakar recorded by Customs. This statement was introduced by Mr. Pawde of CBI.
 - The Committee did not find it expedient to examine the Customs Officer who had recorded the statement, as the same was counter-signed by Mr. Ratnakar. When this statement was introduced by Mr. Pawde as evidence, the Defence Counsel of Mr. Ratnakar was given opportunity to cross-examine Mr. Pawde if they were not inclined on Committee's acceptance of this as bonafide evidence. By nature of the transaction, there is no possibility of a third person being present when exchange of Rs. 1500 took place between Mr. Ratnakar, and Miss Sharda Rao. Mr. Ratnakar has by his own admission as recorded by Customs, stated that he has taken Rs. 1500 from Miss Sharda Rao. The Committee therefore concludes that this amount is in the nature of illegal gratification, even though, the amount comparatively speaking, appears to be insignificant, nevertheless it is by way of illegal gratification.
 - The Committee therefore finds Mr. Ratnakar guilty of the charge of taking illegal gratification.
 - 23.3 Charge No. 3.—Conducting himself in a manner not conductive to the best interest, credit and pressige of the Corporation.—As per the reasons mentioned in the summary, the 3rd charge is proved against Mr. Ratnakar beyond any shadow of doubt. The

: 1

Committee feels that the conduct of Mr. Ratnakar in helping an outside party who had earlier manifested her inventions to smuggle silver and his approach to Mr. Puranik, Mr. Indulkar and Mr. Subhajivanlal on various occasions at Cargo Booking Office and at Cargo Complex to expedite the shipment of consignments booked by Dr. Miss Sharda Rao, are manifestation of the fact that Mr. Ratnakar did not conduct himself in a manner conducive to the best interest, credit and prestige of the Corporation.

The Committee therefore finds Mr. Ratnakar guilty of this charge also."

- 12. The first and foremost contention of the learned counsel for the workman is that charges No. (ii) and (iii) were dependent upon charge No. (i). When charge No. (j) was held not proved, the workman could not have been found guilty of charges (ii) and (iii). The illegal act attributed to the workman was that he abetted and aided in illicit smuggling of silver and the Enquiry Committee arrived at a positive conclusion that this charge was not proved. Latter, the Enquiry Committee commended the workman for his conscentiousness in the following words:
 - "It has also come on record that when Miss Sharda Rao requested Mr. Ratnakar to help her in smbulling silver, he refused to do so and informed that he would never do such a job. This shows the conscientiousness of Mr. Ratnakar that he was not prepared to assist Miss Sharda Rao for exporting the silver slabs. On the contrary he ignorantly requested the cargo staff to expedite the consignments booked by Miss Sharda Rao since she was known to him."
- 13. It is submitted that during the course of disciplinary enquiry, no other illegal or unlawful act was attributed to the workman, for which he would have received any illegal gratification from Miss Sharda Rae. Even the findings recorded by the Enquiry Committee do not indicate for what illegal motive or object workman received the alleged illegal gratification from Miss Sharla Rao. It is submitted that he very concept of accepting illegal gratification implies that the workman accepted the alleged amount of Rs. 1500 from Miss Sharda Rao for doing some illegal act or for showing some illegal or improper favour. The only illegal act attributed to the workman was to assist Ms. Sharda Rao in smuggling silver and once this charge fell, charge No. (n) could not survive. The Enquiry Committee in its finding on charge No. (n) does not stare explicitly or even by necessary implication as to what was that illegal or improper favour for doing which workman allegedly accepted Rs. 1500 from Mis Sharda Ra.
- 14. Learned Counsel for the management arged that even though charge No. (i) was not established, it could not and would not mean that charge No. (ii) should also tall down. He arges that even though while discussing charge No. (ii), the Enquiry Committee did not expressly or by implication state the alleged illegal or unlawful object of obtaining Ro. 1500 from Miss Shardt Roo, the finding should be read in committee with this alleged illegal purpose for which mane; was allegedly received.
- 15. In this regard, the learned cousel for the workman contested the legality of propriety of the finding of the Enquiry Committee that workman had received a sum of Rs. 1500 from Miss Shatda Rao at all. It is submitted that this finding is based on no legal evidence worth the name; secondly, it is submitted that the finding on this score is based upon an alleged confessional statement of the workman dated 16-4-1980 recorded by customs officials, this alleged confessional statement had been recorded under duress and coercion; the confession was retracted by the workman at the earliest opportunity, who had made even a complaint to the concerned Magistrate regarding this; the Customs Official, who recorded this statement was not examined during the domestic enquiry and this deprived the workman from cross-examination of the customs officials, who had recorded the alleged confessional statement. It is submitted that this has equeed grave prejudice to the

workman and hence the finding recorded on this aspect should be upset.

- 16. I have considered the rival contentions and have perused the material available on record. I may state at one outset that provisions of Evictince Act do no apply to domestic enquiries. Even the proof in respect of a charge is not required to be of the same standard as required in a criminal trial. At a domestic enquiry, the case has to be decided on preponderance of probabilities (kindly see 1994 I CLR 254—S. K. Awasthy Vs. M. R. Bhope and ors.).
- 17. The second principle to be borne in mind to that this Tribunal does not sit in appeal over the findings at a domestic enquiry. It does not reappraise the evidence except when (1) there is want of good faith; (ii) there is victimisation or unfair labour practice; (iii) when the management has been guilty of a basic error or violation of a principle of natural justice or (1v) on the materials, the finding is completely baseless or perverse. If these vitiating factors are absent, then this Tribunal can not reappraise evidence and come to a different conclusion (see 1959 I LLJ 285 (Civil Appeal No. 500 of 1957 dated 17-10-58 between G. Mekenzie and Co. Ltd. and its workmen and others).
- 18. The first contention of the learned counsel for the workman in this regard was that the enquiry was commenced almost after a lapse of four years and this shows want of good fath and bonafides on the part of the management. In my opinion, no hard and fast rule can be laid down that delay vitiates a domestic enquiry in each and every case. It will depend upon facts on an industrial case if the delay has been unreasonable and unfair. In the present case, admittedly the matter was being investigated and remained pending with a criminal Court for a long period. If the enquiry was not commenced immediately, no blame could be attributed to the management on this factor does not show bad faith by itself but only shows abondant precaution on the part of the management.
- 19. The second contention was that the incriminatory confessional statement dated 16-4-1980 recorded by customs was not supplied in advance to the workman but was shown to him on 3-10-1984 during the course of the statement of witness A. D. Pawade. In this context, suffice it to state that the Enquiry Commutee took the precaution of adjourning the enquiry on 3-10-1984 after taking the various documents produced by witness Pawada and gave opportunity of inspection of the documents to workman and recommended the enquiry on 12-10-1984. On 12-10-1984, the workman completed the cross-examination of witness A. D. Pawade. This narration goes to show that the committee observed the basic principles of natural justice and the procedure adopted did not vitate the proceedings.
- 20. This is true that customs official, who is said to have recorded the confessional statement dated 16-4-80 was not produced to prove the statement. The statement admittedly carried the signature of the workman. This is also true that the workman appears to have retracted the confession admitting receipt of Rs. 1500 from Miss Shorda Rao. However, once the signature of workman were admitted on the said confessional statement, the burden had shifted to the workman to establish that the statement had been obtained under coercion and duress. Non production of customs official in this regard by the departmental tepresentative did not and could not vitsate the enquiry on this count. The workman could also have requested the Enquiry Committee to summon such witness and then subject him to cross examination to eliest facts constituting duress and coercion. Burden to prove this element rested on the workman and it was his ispec divst before the Enquiry Committee. It's findings can not be faulted in the ground that the customs official was not examined by the Departmental Representative at the domesthe enquiry. I find that the findings on this court could not be called perverse or based on no evidence.
- 21. It was contended that the workman lodged a complaint dated 22-5-1980 (Exh. D) with regard to alleged torture by AIRFORT CUSTOMS due to which he claimed to have signed the confessional statement. Firstly, the

statement is a self serving admission; secondly, it does not mention the nature, time and place of alleged torture; it is berept of particulars with regard to person|persons who are said to have tortured him. It is an extremely vauge and general complaint of alleged torture and duress. In my opinion, such a self serving admission, without anything more, does not whittle down the admission made by the workman regarding receipt of Rs. 1500 from Ms. Sharada Rao.

- 22. Lastly, this complaint was not made promptly and is said to have been made on 22nd May, 1980 i.e. after more than one month of the confessional statement, on the face of it, it appears to be an after thought. Hence, I find that the finding recorded on this score by the Enquiry Committee can not be branded as perverse or based on no evidence.
- 23. Learned counsel for the workman took me through the statements of various witness qua the allegation that the workman had assisted M/s. Sharada Rao in expediting the booking and clearing of the cargoes and submits that the evidence is contradictory and discrepent and no categorical finding could have been recorded on the basis of such evidence. In my opinion some contradictions and discripancies in the statements of witnesses would not entitle me to discard the categorcial finding that the workman asserted Ms. Sharada Rao, a stranger in looking consignments, claiming her to be related to her, when in fact she was not so related. This finding is based upon evidence which has been discussed by the Enquiry Committee and I would not be justified in arriving at a different conclusion by reappraising the evidence meticulously, as could be done by a Court of Appeal. The evidence of Mr. Puranik R. R. supports the finding of the Enquiry Committee. About the evidence of Puranik, it was urged that Puranik had been examined by Customs and such statement was not made available to him. The Enquiry Committee declined to supply the statement on the ground that it was not relying upon the said statement. Suffice is to say that the workman, if he so wanted could have requested for summoning this statement from Customs for purposes of cross-examination of this witness. It does not appear that any such steps were taken eventhough statement of Puranik had been deferred. Hence this grievance also loses its significance and is of no avail. The evidence of Mr. Indulkar also categorically supports the finding.
- 24. About the evidence of Shri Indulkar, it is urged that his statement was recorded after the statement of the workman had been recorded and hence it could not have been acted upon. I have gone through the proceedings of the Enquiry Committee. This is true that Indulkar's statement was recorded after workman had been examined. But that by itself could not be a ground to reject the evidence of Indulkar. The workman and his representative were afforded opportunity to cross-examine Indulkar but they walked away and did not participate in the enquiry. It was a highhanded attitude on the part of the workman and his representative. The result was that Indulkar's statement remained uncrossexamined. The workman must thank himself for his contumacious audocity in-refusing to cross-examine Indulkar and in staying away from the enquiry. There is no hard and fast rule of law that a new prosecution witness could not be examined after the delinquent Officer has been examined. Principles of natural justice only require that the delinquent workman is afforded a reasonable opnortunity to cross-examire the witness and thereafter is given an opportunity to explain

such evidences and lead his defence, if any. In the prosent case, the attitude adopted by the workman and his representative, resulted in ron-cross-examination of the witness. Proceedings dated 24-5-1984 and 7-6-1985 very clearly recount The Enquiry Committee tried to provide the this position, workman and his representative with a copy of the statement of Indulkar. They declined to accept it. They were called upon to lead defence, if they so liked but they declined this request as well. The workman filed his final reply of defence on 24-6-1985 and he refrained from speaking anything about the statement of Indulkar deliberately. Hence, now he can not be permitted to make a grievance about the testimony of Indulkar. The workman has by his attitude of unreasonable non-cooperation placed himself in this unenviable situation. I think that the challenge to recorded of testimony of Indulkar is entirely misplaced. 24A. This takes me to the consideration of the contention that since charge No. (i) was not established, charges No. (ii) and (iii) should fall to the ground. It would be recalled that charge No. (i) pertained to siding and abetting Ms. Sharada Rao in smuggling of silver. This major charge of abetment and aiding in smuggling of silver failed, not because the workman did not assist Sharda Rao in booking and clearing of the Cargo but because it was not proved that the workman knew about the conten's of the cargo. The Enquiry Committee is quite positive in its findings that the workman did assist Ms. Sharada Rao in booking and clearing of cargoes. Ms. Sharada Rao was a stranger and the errant workman had no business to assist in her aforesaid activities of booking and clearing of cargoes, such conduct being contrary to the relevant conduct rules, Morecvar, when this was done in consideration of monetary reward, which the workman had no business to accept the misconduct becomes all the more reprehensible and non excuseable. To content that this did not amount to misconduct is to misjudge the entire thing. Hence, the contention that exontration from charge of abeting and aiding in smungling resulted in exoneration from charge No. (ii) and (iii) s to misread the whole thing. The contention has, therefore, no legs to stand upon and is rejected.

- 25. A contention was raised that the enquiry report of CBI was not supplied to the workman. I find that the Enquiry Committee has not at all relied upon the report of CBI investigation. When it is so, no grievance could be made on this counts.
- 26. On a conspectus of all the circumstances of the case, I find that findings of Enquiry Committee on charges No. (ii) and (iii) as upheld by Disciplinary Authority are unassailable. There has been no denial of fairplay or of principles of natural justice.
- 27. Now, the question remains about the legality and propriety of the punishment imposed. I find that a very legient view had been taken of the entire matter.
- 28. Officials at the Airport have to be very scruplous about descharge of their duties. Duties at the Airport involve highly sensitive matters. Accepting a monetary reward from a stranger and to assist such stranger in booking of cargoes, leven though the workman did not know of the contraband nature) was highly improper for the workman. To my mind the punishment imposed errs on the side of leniency.
- 29. Payment of full wages during the period of suspension was within the discretion of the Disciplinary Authority. The workman was not found to be blameless. The workman was not entitled to his incrtments during the period of suspension which was wholly justified. His non promotion during the bendency of enquiry to higher posts can not be faulted. Hence, I find the claim of the workman to be devoid of merit—and reject the same with costs.

Award is made accordingly.

नई दिल्ली, 16 मई, 1996

्का॰आ॰. 1674. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुलग्ण में, केन्द्रीय सरकार ज्ञाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के लंबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्मिद्ध औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल⊶ 31012/3/92-प्राई म्राट (विविध)] बी०एम० डेविड, डैस्क ग्रधिकारी

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1674.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jawaharial Nehru Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government of 14-5-96.

[No. L-31012|3[92-IR(Misc)] B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI. (Present)

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-1|38 OF 1993

Parties :-- Employers in relation to the management of Jawarharlal Nehru Port Trust and

Their workmen.

Appearances :--

. For the Management: Shri D'Souza

For the Workman: Shri Jai Prakash Sawant

Industry: Ports & Docks

State: Maharashtra

Mumbai, dated the 3rd day of April, 1996

AWARD

Shri Jai Prakash Sawant for union.

Shri D'Souza for management.

Heard the learned representatives of the parties at length. Shri J. P. Sawant has also filed written submissions and copy has been supplied to the other side. Shri D'Souza has been afforded opportunity to raise contentions qua the written submissions. He has done so.

- 2. The appropriate Government referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:
 - "Whether the action of the management of Jawaharlal Nehru Port Trust in issuing the Administrative order No. 110|2| 89-Secy|30 dated 5-1-90 wherein the workmen were directed to complusorily stay in the J.N.P.T. Township is legal and justified? If, not to what relief the workmen are entitled to?"
- 3. The Union filed its written statement of claim on 25-11-93. The management filed its written reply to the written statement of claim on 27-7-94. Both the sides have filed documentary evidence in support of respective pleas. Both of them have chosen not to lead any evidence as would be evident from ordersheet dated 20-11-95.
- 4. At the outset, I may state that Jawaharlal Nehru Port Trust, for short J.N.P.T. is a huge organisation employing about 1668 employees. It is situated in a remote area which was initially under developed with no infrastructure .Housing and other facilities were not initially available in the vicinity of the J.N.P.T. Hence employees had to stay outside at distant places like Mumbai Panvel, Thane etc. and had to commute daily travelling long distances. This, on one hand sapped their energy and on the other affected their efficiency. Hence, the J.N.P.T. by investing huge amounts constructed a township in the vicinity of the port. This was done as a welfare measure for the benefit of the employees. The employees were allotted suitable quarters to them and it is stated that about 1157 employees are staying in the township.
- 5. It is an admitted position before me that there are two sets of employees in J.N.P.T. One set consists of those employees who joined the trust before construction of the township. Their terms of appointment did not stipulated a condition about their compulsory stay in the township. The union has admitted this position in its written statement of claim para 5 sub-para (v).
- 6. It appears that a term stipulating compulsory stay in the township was inserted in the appointment letters of those employees who joined the employment after construction of the township. This position is also admitted by the union in the self same sub para of the written statement of claim. I may reproduce the said subpara to make the situation abundantly clear. It reads:

"That there is no term regarding compulsory stay in the township in the appointment letters issued to the workman appointed prior to the year 1990.

- The term has been subsequently included in the leters of appointment issued to the workmen appointed after the year 1990, arbitrarily and unlawfully".
- 7. At this juncture, it would be profitable to extract the material portion of impugned circular dated 5th January, 1990.
 - "Employees have to compulsorily stay in Township. Manager Township has been requested to allot accommodation to all employees. The employees who have been allotted quarters must stay in the Township when they are not on authorised leave."
 - "The employees are sternly warned that failure to observe the above rules will constitute miscenduct which will entail disciplinary action."
- 8. Now, the first contention is that this impugned position of the circular amounts to a charge in service condition, which could have been effected only after complying with the formalities prescribed under Section 9A of the Industrial Disputes Act.
 - 9. J.N.P.T. in its reply has traversed this plea.
- 10. Suffice it to say that the Section 9A of the I.D. Act would be applicable only when conditions of service applicable to any existing workmen are charged. It presupposes an existing workman and an existing condition. The expression "without giving to the workman likely to be affected by such change a notice in the prescribed manner" used in sub-section (a) of Sec. 9A of the I.D. Act, by necessary implication means this.
- 11. Hence, the impugned circular would be violative of Section 9A of the I.D. Act qua such workmen only, who were appointed prior to issue of impugned circular and whose letters of appointment did not carry a stipulation regarding compulsory stay in the township. The same would not be the position qua the workman whose letter of appointment specifically stipulated that they shall have to stay compulsorily in the township. In respect of such workmen, there is no change in service condition because they have been appointed subject to such a stipulation.
- 12. The word 'charge' presupposes an existing term, which has been altered and would not embrace within its ambit a term subject to which appointment itself is made.
- 13. Hence, I held that impugned circular is invalid and illegal qua those workinen whose condition of appointment did not stipulate a compulsory stay in the township. However, the circular can not be faulted qua employees, whose conditions of appointment stipulate a compulsory stay in the township.

- 14. On behalf of the union, it has been contended that compulsory stay in the township can not be considered a term of employment. Why it could not be so considered has not been spelled out? When the appointment letter carries such a term, then it has to be construed a term of employment. Hence, this contention is devoid of all ment and must be stated only for the take of rejection.
- 15. Another contention was that employees of other major Port Trusts were not subjected to such a term or stipulation. Suffice, it to say that each Major Port Trust is an independent entity and is an independent employer and can not be compelled to lay down terms of service as laid down by other employers.
- 16. Another contention was that model standing orders prescribed under the Industrial employment (Standing Orders) Act, 1946, which are applicable to the establishment of J. N. P. T. do not provide for such compulsory stay in the township. Suffice, it to say that no such model standing orders have been placed on record to justify the contention and the contention has no legs upon.
- 17. It was contended that the J. N. P. T. has adopted certain rules and regulations of Mumbai Port Trust including House Rent Allowance Rule. The said Rules do not compel an employee to stay in the Port Trust Quarters! township. The argument again overlooks the fact that Mumbay Port Trust is an independent entity and J.N.P.T. has modified the relevant rules etc. it can not be faulted on this account.
- 18. Here. I would pause and state that the union in the garb of the present claim has challenged the legality of two circulars dated 2-11-89 and 17-11-89. No industrial dispute was raised with regard to these circulars. The jurisdiction of this Tribunal is limited to adjudication of the dispute referred to it and since no dispute has been referred qua these two circulars, I refrain from going isto the question of legality of the said two circulars. In my considered opinion, the union can not be permitted enlarge the scope of the reference by raising the question of legality or otherwise of the two said circulars.
- 19. On behalf of the union, two judgments have been quoted—one passed by Central Government Labour Court No. 2 on 29-6-92 and the other passed by the very Labour Court on 7th July, 1994. The first judgment has no relevance to the questions raised before me. The second judgment pertains to a case where the appointment of the employee did not make it complusory for him to stay in a quarter allotted to him by the Port Trust. Para 14 of the said judgment makes this position clear. It may be stated that workman in that case was appointed on 11-5-89. The learned Judge observes in para 14 of his judgment.

- "On the perusal of the appointment order it reveals that there is no condition directing the applicant to stay in the Port Trust Residence."
- 20. Thus, this was a case of an employee who fell in the category with regard to which I have held the impugned circular to be invalid.
- 21. Learned Representative of the union referred to me certain subsequent developments v.z. Notice of management dated 24-4-95 and annexure annexed thereto and submitted that the J.N.P.T. has now withdrawn the condition grading compulsory stay in the township and has also allowed benefit of House Rent Allowance: to those, who are not staying in the querters allotted to them. It is submitted that in view of these developments, the dispute does not survive. In particular, reference has been made to resolution No. 207 of 95 of J.N.P.T. and the circular No. 2098 dated 08/13-6-95 of J.N.P.T. In my opinion, these documents do not clinch the issue finally and are liable to be considered prospectively,
- 22. Learned representative for the management referred to the claim of the union that an employee though not staying in a quarter al lotted to him, is still entitled to claim House Rent Allowance and submitted that such a claim could not be sustained in view of the apex Court Judgment in Director, Central Plantation Crops Research Institute 1994 II LL. 1032. He has, in particular referred to the following observations of the Apex Court.
 - "It must be remembered in this connection that the Govt, or the organisation spends huge public funds for tructing quarters for their employees both for the convenience of the management as well as of the employees. The investment thus made in constructing and maintaining the quarters will be a waste if they are to lie unoccu-The House Rent Allowance is pied. not a matter of right. It is in lieu of accommodation not made available to the employees. This being the case, it follows that whenever the accomodation is offered the employees have either to accept it or to forfeit the house rent allowance. The management can not be saddled with double liability viz. to construct and maintain the quarters as well as to pay the frouse rent allowance."
- 23. Learned representative for the union tried to distinguish the case on the ground that it turned upon the wordings of the particular rule. I am afraid, this contention can not be accepted because the Apex Court has made the aforesaid

- observations on the basis of first principles which should govern grant of house rent adlowance.
- 24. To sum up, I find that the impugned circular is legal and justified so far as those employees are concerned whose term of appointment stipulates a compulsory stay in the township. It is not legal and justified our he employees whose terms of appointment did not stipulate a compulsory stay in the quarter allotted to them in the township and their failure to stay in a quarter allotted to them in the town ship would not constitute a misconduct in as much as change qua them was not affected after following provisions of Section 9A of that Act. However, such employees, who have been allotted offered a house in the township and refused to do so would not be entitled to claim House Rent Allowance on the principle enumeiated by the Apex Court in the realing cited above.
- 25. I may make it clear that this shall not affect the subequent situation brough about by J.N.P.T. by its resolution No. 207 of 35 and circular No. 2098, dated 08-6-95 13-6-95 issued by the J.N.P.T. In the circumstances of the case, the parties shall bear their own costs. Award is made accordingly.

R. S. VERMA, Presiding Officer नई दिल्ली, 16 मई, 1996

का ० आ ० 1675. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अध्यर्ध जोक लेवर बोर्ड के प्रबन्ध-तिम्न के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-31011/11/89-प्राई प्रार (विविध)] बो॰एम० डेबिड, डेस्क ग्रीधकारी

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1675.—In pursuance of Section 17 of the triddstrial D sputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure In the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Dock Labour Board, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-5-1996.

[No. 1-31011|11|89-IR(Misc.)] B. M. DAVID. Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGJT-1|6 OF 1990 PARTIES:

Employers in relation to the management of Bombay Dock Labour, Board, Bombay.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Management: Shri P. Ramaswamy, Advocate. For the Workman: Shri M. B. Anchan, Advocate. INDUSTRY: Ports & Docks STATE: Maharashtra

Mumbai, dated the 9th day of April, 1996

AWARD

Appropriate Government has referred thte following dispute for adjudication to this Tribunal:

- "Whether the action of the Bombay Dock Labour Board, Bombay is justified in refusing to register 117 senior most workmen as GPMs (Registered General Purpose Mazdoors) with effect from 1-6-1983 when 2103 General Temporary workmen under various Stevedoves were registered as GPMs by the Bombay Dock Labour Board. If not, to what relief the workman concerned are entitled to?"
- 2. The National Dock Workers' Union (INTUC). hereafter known as the Union, submitted the written statement of claim on 23-4-1990 inter alia pleading that various stevedoring forms and contractors. operation in Bombay Docks, employed in all about 3000 casual and temporary workers. There was no security of service in respect of these workmen, they being unorganised. In the year 1981, the Transport and Dock Workers' Un'on started an agitation for regularising these workers. As a result the Government decided to register these workers with the Dock Labour Board under Bombay Dock Workers' (Regulation of Employment) Scheme, 1956 as amended from time to time. The Chief Administrative Officer of the Bombay Dock Labour Board was authorised to complete the process of registering these workers before 1-4-1983. This process was completed some time in June, 1983.
- 3. The case of the Union is that while submitting the names of workers for this purpose M/s Robinsons and M/s. R. Sharp and Sons (Pvt. Ltd.) did not submit the names of 117 wokers and due to this Bombay Stevedoring Association did not submit their names to the Bombay Dock Labour Board and hence their names were not registered with the said Board.
- 4. The Union espoused the cause of the said 117 workmen with Labour Contractor, Shri Palaniappan, for the said firms, Since both the firms aforesaid did not respond, the union took the matter in conciliation. Eventually a failure report was made and the appropriate Government referred the dispute as aforesaid.

- 5. The case of the union is that the said 117 workers, whose case the union was espousing were workers of M/s. R. Sharp and Sons P. Ltd. and M/s. Robinsons since 1976. Both these stevedoring firms did not submit the name of the 117 workers to Bombay Stevedoring Association Ltd. and in turn the said Association did not send their names to the Bombay Dock Labour Board and hence their names could not be registered with the said Board and this has deprived the 117 workers of their livelihood. It was prayed that the said Board be directed to register the names of the 117 workers w.e.f. 1-6-1983.
- 6. The Bombay Dock Labour Board (for shift B.D.L.B.) submitted its reply to the written statement of claim inter alia pleading that the workmen in question were not the employees of B.D.L.B. Hence, the dispute referred to the Tribunal was not a dispute between the employer and the employees and for this reason the reference was liable to be rejected. It was also pleaded that B.D.L.B. was not an industry, the employers of the workmen in question were not parties to the dispute, hence the reference was not maintainable.
- 7. It took the stand that under the original scheme for registration, Dock Workers were registered as per classification mentioned in Rule 16. This classification did not include general purposes Mazdoors. However, this scheme was modified by the Government of India on 23-1-81 and the amended classification did include General Purpose Mazdoor. But this did not include the casual and temporary general purpose mazdoor.
- 8. However, the B.D.L.B. in its meeting held on 30-12-82 decided that temporary workers employed by sevedors through contractors, whose names are on mutually agreed lists and who have been issued photo identity cards b ythe Bombay Stevedors Association Ltd. should be included in the scheme as General Purpose Mazdoors (Ex. T.) A committee was formed for the said purpose. The concerned Stevedors were directed to furnish lists forms of casual workers working with them of through contracts. The names of thet 117 workers Were included in the 1'sts submitted and hence they were not registered. It prayed that reference be rejected.
- 9. Both the parties have filed some documentary evidence but it appears that the union prayed time and again for opportunity to lead oral evidence. Eventually, on 22-2-96 Shri Anchan, Advocate for the union pleaded no instructions. Hence, the matter was heard ex-parte. It may be stated that affidavits of three witnesses viz. N. Maran, P. Murugean and N. Palaniappan were filed by the union. But, they were not produced for cross-examination inspite of opportunities. Hence, these affidavits can not be read in evidence and have to be rejected on this short ground.
- 10. Learned counsel for the B.D.L.B. Shri P. Ramaswaray has submitted that on the showing of the union itself, 117 workmen, whose claim the union was espousing, were not employees of the B.D.L.B. and hence the dispute raised was not an industrial dispute and on this short point this reference deserves to be rejected.

- 11. I find that this contention is not without force and has to be considered in the correct perspective. Admittedly, the 117 workmen, whose cause the union is espousing, were at no point of time employees of the B. D. L. B. There never existed a relationship of master and servant between the B.D.L.B. and the said workman, who were admittedely employees of the two firms viz. M|s. R. Sharp & Sons Ltd. and M|s. Robinous. Both these employees are not parties to the present proceedings. hence, the present dispute is not an industrial dispute at all.
- 12. Moreover, under the scheme as medified only Dock Workers could be registere. For this purpose, the union was required to establish that the 117 workers were serving under the two stevedoring firms named above. Such a decision could not be recorded at the back of the said two firms and for this reason also the reference is incompetent.
- 13. Even on merits, the union has failed to make out any case by leading any cogent evidence. As already stated, affidavits filed by it can not be looked into as the deponents were not produced for cross-examination and as such the affidavits are not worth anything.
- 14. The documentary evidence placed on record has not been proved at all and hence can be of no help to the union.
- 15. Last but not the least, I find that claim is a highly belated one. I am aware that there is no law of limitation for 'Industrial Disputes'. However, stale claims do not deserve to be entertained. The union claims that 117 workmen be directed to be registered w.e.f. 1-6-1983. Claim was filed before this Tribunal on 23-4-90 i.e. after about seven years. On this count also, workmen are not entitled to any relief.
- 16. I, therefore, reject the claim of the union and make an award accordingly. The got published as required by law.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 मई, 1996

का०आ० 1676. --- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बम्बई पोर्टट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 1, मुम्बई के पंचपट को प्रकाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्ते हुआ था।

> [सङ्या एल-31012/30/92-प्राई म्रार (विविवा)] बी०एमः डेविड, डैस्क ग्रधिकारी

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1676.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Apt, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial d'spute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-5-1996.

> [No. L-31012|30|92-IR(Misc.)] B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma. Presiding Officer. REFERENCE NO. CGIT-1|51 OF 1993 PARTIES:

Employers in relation to the management of Bombay Port Trust.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Management: Shri Nargolkar, Advocate. For the Workman: Shri S. R. Wagh, Advocate. INDUSTRY: Ports & Docks STATE: Maharashtra Mumbai, dated the 11th day of April, 1996

AWARD

Shri S. R. Wagh for union.

Shri Nargolkor Advocate for management.

Heard the learned counsel for the parties and perused the record.

- 2. The workman in this case Shri G. G. Shelkar was in employment of the B.P.T. He had been allotted residential accompodation by the management. He allowed a friend to share this accommodation without obtaining proper prior sanction. He was chargesheeted and a domestic enquiry was held against him, the legality, propriety and fairness of which is not under challenge before me and is rather conceded that the same was quite legal, fair and proper.
- 3. It appears that eventually a show cause notice (Ex. 'D' filed by management) was issued to him, which inter alia stated:
 - "I, therefore, in exercise of powers conferred on me under Regulations 8 and 10 read with Sr. No. 5 of the Schedule of the BPT Employees (CCA) Regulations, 1976, hereby propose to impose on Shri Dhondu Ganpat Shelar the penalty of dismissal from service if he fails to vacate the quarters within 3

months from the date of receipt of the notice. If he vacates the quarter within the stipulated time, I propose to impose penalty of reduction of his pay by two stages without prejudice to his future increment."

- 4. It appears that the workman received this notice but did not reply to the same; nor did he vacate the quarter within the stipulated time. As a consequence, the major penalty of dismissal was passed upon him. However, it appears that he vacated the quarter on 21st September, 1989. This led the competent authority to pass an order of dismissal upon the workman. He moved a mercy petition before higher authorities and eventually by order dated 4-7-91, his dismissal was converted into an order of compulsory retirement, Aggrieved, an industrial dispute was raised which after due formalities was referred by the appropriate Government to this Tribunal for adjudication.
- 5. As already stated, the legality, fairness and propriety of the domestic enquiry has not been challenged. The only contention of Mr. Wagh is that the workman had been in long employment. Even the Disciplinary Authority proposed an alternative and minor punishment of stoppage of two increments if the workman vacated the quarter within stipulated time. However, to secure an alternative accomodation is a very difficult task; this led to delayed vacation of quarter resulting in a very severe punishment. The punishment is harsh and excessive and deserves to be modulated looking to the otherwise clean and blemishless record of the workman,
- 6. Shri Nargolkar contents that the conduct of the workman in not vacating the quarter as stipulated in the show cause notice was contumacious and defiant and hence the Tribunal should not interfere with the punishment.
- 7. I have considered the rival contentions and considered the circumstances of the case. To obtain an alternative accomodation in Bombay is a Herculean task. Merely, because the workman could not vacate the quarter in time, his conduct can not be branded as contumacious. Non-availability of housing accomodation must have contributed to the delay and I may take judical notice of this fact, which is well known to those who live in Bombay.
- 8. Ofcourse, the workman acted very foolishty in not responding to show cause notice and in not making a request for extension of time. However, it would not be just and proper to impose the harsh penalty of compulsory retirement on an employee, who has otherwise clean record.
- 9. I, therefore, deem it proper to substitute the punishment of compulsory refirement by one of stoppage of two increments. Rest of the order of the Chairman shall stand as it is. Award is made accordingly. Parties to bear their own costs. Award be notified as per law.

R. S. VFRMA, Presiding Officer

عديم المستعدين مناه ومصيحة منحصص من أوره ربو مأور جانبا موجد عداميا المدعديين المدعد عواموا عواموا مواكر أأفي مراب The matter was mentioned by Sarza Shri Nargoliar and S. R. Wagh and it was requested that it may be clarified as to from which date the order of stoppage of two increments in substitution of the order of compulsory retirement be effective. Obviously, the order of stoppage of two increments shall be effective from the date the order for compulsory retirement was passed. However, in the circumstances of the case, the workman shall not be entitled to claim back wages from the date of compulsory retirement till date and shall be reinstated forthwith Clarification made and shall be a part of the award.

R. S. VERMA, Presiding Officer

मर्क दिल्ली, 16 मई, 1996

का०आ०1677. --अधिर्गिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनमरण में, केन्द्रीय मरकार बम्बई पोर्ट इस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्घ नियोजकी और उनके कर्नकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट आँद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 14-5-96को प्रत्यहुआ थः।

> [संख्या एल-31011/2/94-प्रार्व आर (विविध)] बी० एम० डेविड, डैम्क अधिकारी

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1677.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1. Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-5-96.

> [No. L-31011[2]94-IR(Misc.)] B. M. DAVID. Desk Officer

ANNEXURE

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. J, MUMBAI PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-1|9 of 1995

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bombay Port Trust.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Management.—Shei M. B. Anchan, Advocate.

For the Workman,--No appearance.

INDUSTRY: Ports & Docks STATE: Mahatashtra Mumbai, dated the 2nd day of April, 1996

AWARD -

Shri M. B. Anchan for the management.

None present for the union inspite of service of notice.

The dispute referred to the Tribunal is whether the action of the management of Boinbay Port Trust in terminating the service of Shii Sadanand Dhondu Surve Mazdoor, Chief Mechanical Engineers Deptt. of B.P.T. w.e.f. 26-8-1989 is legal and justified. If not, to what relief the workman is entitled.

The union or the workman have not filed any written statement of claim which may go to show that the action of the management in terminating the services of the workman is illegal, improper or invalid. Hence the claim is without substance and is rejected and exparte award is made accordingly.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 मई, 1996

कार आर 1678. — आँद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वन्बई पोर्डड्स्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट आँद्योगिक विवाद में। केरद्रीय सरकार अँद्योगिक अधिकरण नंद 1, मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केरद्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-31012/18/92-प्राई प्राप्ट (विशिध)] बो० एम० डेविड, डैस्क ग्रीधिकारी

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1678.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-5-96.

[No. L-31012|18|92-IR(Misc.)] B. M. DAVID, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO: 1, MUMBAI PRESENT:

Shri Justice R₅ S; Verma, Presiding Officer, REFERENCE NO. CGIT-1/22 OF 1993

Employers in relation to the management of Bombay Port Trust.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

PARTIES:

For the Management: Shri Nargolkar, Advocate For the Workmen: No appearance.

INDUSTRY: Ports & Docks STATE: Maharashtra Mumbai, dated the 11th day of April, 1996

AWARD

Shri Nargolkar, Advocate for the management. None for the union even though Shri V. Narayanan appeared for union on 18-10-95.

The matter is to proceed exparte.

The dispute referred to the Tribunal is:

"Whether the action of the management of Bombay Port Trust, Bombay is justified in terminating the services of Shri M. W Kedar, an Office Attendant unilaterally w.c.f. 31st May 1984 and whether the management is justified in appointing S\Sh. S. P. Jamasandekar and Patekar? If not what reply the workman is entitled to?"

Admittedly, as per written statement of claim, the workman was appointed on 10.5-84. He served 1st June, 1984 when his services were abruptly terminated. Thus, he served for about 22 days in all.

The case of the management is that the workman was appointed in a leave vacancy. On cessation of the vacancy, his services were terminated.

In my opinion, the termination could not be said to be bad. The workman had no indefeasible right to continue on the post to which he was appointed. Admitteldly, he had not put in continuous service for a period of more than 240 days perior to his termination.

Hence, I find no mer't in the claim. So far as appointments of Iamasandekar and Patekar are concerned, they are not parties to this lis. No orders can be passed on this score,

To sum up, the claim of workman is without merit, termination of his service can not be said to be illegal or improper. He is not entitled to any relief. Award is made accordingly. The same be notified and publisshed in accordance with law.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 मई, 1996

का० आ० 1679. — आँखोगिक विवाद अधिनियम: 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीर सरकार में ० ए० बी०सी० एंड मन्म लि० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण नं० 1, मुम्बई के पंचपष्ट को प्रकाशिक करती है, ओं केन्द्रीय संज्ञार को 14-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल--31 01 1/2 4/92-आई.आर (विविध)] वीरुएमरु डेबिड, डेस्क प्रधिकारीः

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1679.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1,

Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M.s. A. B. C. & Sons Ltd. and their workmen, which received by the Central Government on the 14-5-96.

> [No. L-31011]24[92-IR(Misc.)] B. M. DAVID, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-1114 of 1993

PARTIES:

Employers in relation to the management of Ms. A.B.C. & Sons Ltd.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Management: Shri J. P. Cama and Ms. S.V. .Kher, Advocates.

For the Workmen: Shri S. R. Wagh, Advocate,

INDUSTRY: Port & Docks STATE: Maharashtra Mumbai, dated the 24th day of April, 1996

AWARD

The appropriate Government has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal:

- "Whether the action of the Management of M/s. ABC & Sons Ltd., Bombay resorting to closure of their Clearing and Forwarding Deptt. under Sec. 25-FF(A) of I D. Act, 1947 and retrenching 70 workers whose names have been given in the Annexure are justified? If not to what relief the workmen are entitled?"
- 2. Transport and Dock Workers union Bombay (hereinafter the union) espousing the cause of the workmen submitted its written claim of statement on 4-8-93. Shorn of unnecessary details, the case of the union is that MIs. Ardesir B. Cursetjee and Sons (Private) Ltd., hereinafter the company. closed its clearing and forwarding Department and retrenched 64 employees working in the said department w.e.f. 1-6-92. It is submitted closure and the retrenohment were effected when conciliation proceedings were pending between the parties qua the preposed closure. It was pleaded that such a closure during pendoncy of concilation proceedings was in violation of Section 33 of the Industrial Disputes Act and hence was improper, unjustified and illegal. On the same ground, the legality of retrenchment of 64 employees was assailed. Besides, this, it was pleaded that services of the employees of the company were transferable from one department to another and hence there could be only one and one seniority list for all the employees but the company instead prepared a seniority list for clearing and forwarding department and such a seniority list was not a correct one and retrenchment on basis

- of such a seniority list was bad. It was also pleaded that if there was excess staff in clearing and forwarding departments, it should have been absorbed in other department. Alternatively, it was pleaded that retrenchment compensation paid to the employees was not correctly computed. On such pleas and others, it was prayed that all the 64 emplyees retronched by the company be directed to be reinstated with back wages.
- 3. The company filed its reply to the written statement of claim on 21-12-93 and inter alia pleaded that once closure of the forwarding and clearing department of the company was an admitted fact; this Tribunal can not go into the question of justifiability or otherwise of the closure. It was submitted that the issue appropriate Government was also not competent to refer the dispute of justifiability or otherwise of the closure to this Tribunal. Hence, the reference be rejected.
- 4. The proceedings dragged on for some time. Eventually on 23-2-1996, this Tribunal passed the following order:

"Ms. S. V. Kher for management,

Shri Wagh for union.

The agreed position between the parties is that Supervisors, Assistant Supervisors, Clerks and Peons constituted the workmen which had to go on account of closure of the clearing and forwarding department of the company.

The case of the workmen is that employees in all the aforesaid categories were transferable from one department to another department of the company and as such there should have been a common integrated seniority list of Supervisors in all sections, likewise similar integrated seniority lists Assis ant Supervisors and Clerks and Peons. Shri Wagh submits that with this closure junior persons were retained and seniors were given marching orders. However, this position has not been properly adumbrated in the pleadings. Both the parties may, therefore, file their respective affidavi's within 25 days with copies exchanged with each other within the aforesaid period; in case any counters are required may also be filed within next 25 days of receipt of the copies and copies of counters be also exchanged with each other. Matter to come up on 8-4-1996 for oral hearing in the light of the affidavits and counters.'

- 5. The case could not be taken up on 8-4-96 because the Presiding Officer was on tour. matter eventually came up before me on 18-4-96 when learned counsel for the company prayed that the question of legality of reference and jurisdiction of the Tribunal to go into the question of legality of the closure may be decided as a preliminary issuc.
- 6. Since this question went to the root of the matter, I allowed both the sides to argue this preliminary point, which was purefy a question of law.

- 7. The basic question is that when closure of the forwarding and clearing department of the company was an admitted fact, the justifiability or otherwise of the closure could have been referred to this Tribunal by the appropriate Government and this Tribunal could go into such a question on such a dispute being referred to it.
- 8. I have heard the learned counsel for both the sides. Admittedly in this case, a closure of a department of the company is admitted on both the hands. The factum of closure is not in dispute. The genuinness and bona fides of the closure are not in dispute. When it is so, can the appropriate Government refer the dispute regarding justifiability/legality of the closure and can this Tribunal hear such a dispute.

The question is no longer res integra and has been settled in AIR 1963 Supreme Court 569—Management of Express Newspapers (P) Ltd. and 1983 (I) LLJ 232 Pottery Mazdoor Panchayat.

- 9. In express newspapers (supra) the apex Court laid down the law as follows:
 - "If the action taken by the appellant is not a lockout but is a closure bona fide and genuine, the dispute which the respondents may raise in respect of such a closure is not an industrial dispute at all on the other hand, if in fact and substance, it is a lockout but the said action has adopted the disguise of a closure, and a dispute is raised in respect of such an action, it would be industrial dispute which industrial adjudicator is competent to deal with."

It further observed:

- "If the Industrial Tribunal proceeds to assume jurisdiction over a non industrial dispute, that can be successfully challenged before the High Court by a petition for appropriate Writ and the power of the High Court to issue an appropriate Writ in that behalf can not be questioned."
- 10. In Pottery Mazdoor Panchayat, this precedent was considered and followed and it was observed:
 - "We are, therefore, of the view that the High Court was hight in doming to the conclusion that the two Tribunals had no jurisdiction to go behind the references and inquire into the question whether the closure of business, which was in fact effected was decided upon for reasons which were proper and justifiable. The proprety of or justifiable for the closure of a business in fact and truly effected can not raise an industrial dispute as contemplated by the Central and Sales Acts."
- 11. In the present case, there is no allegation that closure had not been effected in a genuine or bona fide manner. There is not even faintest suggestion that closure had not been effected or it was a cloak or an action in disguise. Rather, the averment was that the closure was illegal because it had been effected during the pendency of the concilla-

- tion proceed ags. I am of the view that such a dispute was not at all an industrial dispute and the reference in this regard by the appropriate Government is bad. Not only this, the dispute not being an industrial dispute, could not have been referred at all nor could be adjudicated upon by this Tribunal.
- 12. It may be stated that the retrenchment of 64 employees as a consequence of the said closure has been challenged but it is extremely doubtful if this part of the reference can be served from the main reference and can be adjudicated upon. Learned counsel for the union could not show any law which may warrant adoption of such a counsel by this Tribunal. To my mind reference has to go in its entirety, lock, stock and barrel. There is no jurisdiction in the Tribunal to adjudicate upon a part of the reference, while rejecting its basic plank.
- 13. Hence, I am of the furn view that the present reference is incompetent and deserves to be rejected. It is so rejected hereby. In the circumstances of the case, parties are left to bear their own costs. The order be notified and published as per law.

R. S. VERMA, Presiding Officer. नई दिल्ली, 16 मई, 1996

का०आ०. 1680 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भें अर्स गांगवी णिपराईट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 1, वस्त्रई के पंचपट को प्रकाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-31012/20/91~पाई प्रार (विविध)] वी०एम० डे विड, डैस्क प्रधिकारी

New Delhi, the 16th May, 1996

S.O. 1680.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Sanghvi Shipwright and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-5-1996.

[No. L-31012/20/91-IR (Misc.)] B. M. DAVID, Desk Officer, ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-1/3 of 1993
PARTIES:

Employers in relation to the management of M/s. Sanghvi Shipwright, Vasco-da-Gama, Goa.

Their workmen,

APPEARANCES:

For the Management: Shri N. C. Bose.

For the Workman: Shri P. Goankar, General Secretary.

INDUSTRY : Shipping.

STATE: Goa.

Camp: Goa.

Goa, dated the 15th ady of April, 1996

AWARD

Shri P. Goankar General Secretary of the union viz. Gomantak Mazdoor Sangh. He admits that settlement dated 24-4-1995 has been entered into between the union espousing the cause of workmen and the management. He verifies his own signature marked A to B on the two sheets of the settlement, He also verifies the signatures of the concerned workman on 2nd sheet of the settlement viz. C to D of Shankar Salgaonkar C-1 to D-1 Sentosh Kadam, C-2 to D-2 Regional Godinho, C-3 to D-3 Gopal Kerkar and C-4 to D-4 Shyam Naik. He also identifies signatures of the Manager Shri N. C. Bose, marked today as E to F. He also identifies signatures of witness Shri A. Machado marked G. H. He admits that stylement has been duly arrived at between the parties.

He further states that in pursuance of the said settlement, each one of the workmen above named, have received the amount of compensation paid to them as per statement of payment dated 25-7-1995. The statement has been marked today at Ex. 'A' and the statement of payment marked Ex. 'B'. He also verifies signatures A. B. on Ex. C. as that of Shekar Salgaonkar, A. B. on Ex. D. as that of Santosh Kadam, A. B. on Ex. E. as of Regional Godinba, A. B. on Ex. F. as that of Gopal Kerkar and A. B. on Ex. G. as those of Shyam Naik. He states that the settlement arrived at between the parties settles the claim of the workman once for all and no dispute now survives.

Shri N. C. Bose for the management. He verifies the settlement and states that payments have been made as agreed to by the parties. The dispute is settled in terms of agreement, which shall be a part of this order. Award is made accordingly.

R. S. VERMA, Presiding Officer.

मई दिल्ली, 17 मई, 1996

कार आर 1681. --- औद्योगिक श्रिवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्नेंग के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोज कों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार ओद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्त नुआ था।

[संख्या एल--12011/17/91--प्रार्थ०प्रारः (गी० 2)] बाल्एम० डेविड, डैस्क ग्रधिकारी New Delhi, the 17th May, 1996

S.O. 1681.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribuna. New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Oriental Bank of Commerce and their workmen, which was received by the Central Government on 14-5-96.

[No. L-12011]17[91-IR(B-II)] B. M. DAVID, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESID-ING OFFICER. CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 79|91

In the matter of dispute between:

- 1. Shri Rameshwar Prasad
- 2. Shri Jaipal Singh
- 3. Shri Raju Gomes
- 4. Shri Gobar Singh
- 5. Shri Hari Singh
- 6. Shri Shakti Singh
- 7. Shri Ranber Singh
- 8. Shri Gopal Singh
- 9. Shri Arjun Singh Rana
- 10. Shri Pana Lal
- 11. Shri Dumi Chand
- 12. Shri Balwant Singh
- 13. Shri Liladhar
- 14. Shri Arjun Singh Bisht
- 15. Shri Nandan Singh
- 16. Shri Harbak Singh
- 17. Shri Thaneshwar Sharma
- 18. Shri Jai Singh
- 19. Shri Bhim Singh
- 20. Shri Tej Singh
- 21. Shri Charna Singh

Versus

Oriental Bank of Commerce, Harsh Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi.

APPEARANCES:

Mrs. Kitty Kumar Mangalam for the workman.

Shri Jagat Arora for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12011/17/91-IR(B-II), dated 21-6-1991 has referred the following industrial dispute to this tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Oriental Bank of Commerce by not regularising Shri Rameshwar Prasad and 20 others (in the Annexure) as drivers though performing the duties of driver since their deployment in the bank is justified? If not to what relief is the workman entitled?"

- 2. In the statement of claim, it has been alleged that the workmen in dispute, have been in the employment of the bank as per details specified in Annexure-A with the statement of claim. It has been averred that they were employed by the Bank and given the job of driving the car of the Bank. They also have identify cards of the Bank designating them as drivers. The Bank on employing them allotted them the job of driving the car of some senior officials of the Bank. It is further alleged that the bank decided as to which driver would drive which officials car. The petrol, repair complete maintenance of the car is looked after by the bank. It has been further alleged that the system of operation in the bank is that after the Bank employed these workmen it placed the workmen with one of its respective officials whom these workmen served from morning to night. The mode of payment to these workmen was that the Bank did not pay to them directly, but gave separate cheques of the workman salary to the concerned officials, who signed at the reserve of such cheques and thereafter handed it over to the concerned workmen driving his car for eneashment. In this manner, the Bank created a veil and facade and thus hide the true relationship between the workmen and the Bank. It has been further alleged that after minimum of 4 years service in the said fashion the Bank appointed these workmen as Peon-cum-Driver on probation for six months and on completion of this period the workman confirmed in the said post and received salarv directly from the Bank.
- 3. Thus, the case of the workmen is that prior to their appointment in 1986 as Peon-cum-Driver, these were in the employment of the Bank and as such are entitled to regularisation of their services from the date of their initial appointment mentioned in Annexure-A to their claim statement. The management, however denied the claim of the workmen on the plea that there was no relationship of master and servant between the Bank and the claiments prior to 1986, i.e., the respective dates of appointment of claiments as Peon in the Bank in 1986.
- 4. It has been averted by the management that the claiments were appointed as Peons as per appointment letters issued to them. Prior to appointing the claiments as Peon, there never existed employer and employee relationship between the claiments and the Bank. Prior to the dates of appointments of the claiments, they were not in the employment of the Bank and the Bank did not exercise the power of control and supervision over the claiments. They were personal drivers of the executives of the Bank and were controlled and directed and also paid salary by the executives of the Bank. The executives of the Bank were only en-

- titled to an allowance as prescribed for employing their drivers, as per circular dated 7-3-1977, which provides for reimbursement of salary of car drivers to the executives. Under this circular, the executive, who has engaged driver to drive vehicle would be entitled to rate of amount prescribed.
- 5. The management has filed 44 documents, as per their list of documents dated 15-2-1992 and have examined Shri R. S. Deswal as MW1. While on behalf of the workmen, Shri Rameshwar Prasad has been examined as MW1.
- 6. I have heard representative for the parties and have gone through the record.
- 7. Out of the pleadings of the parties, as stated above, the basic question arises as to whether their existed any relationship of employer and employee between the claiments and the defendant bank prior to the date of claiments' appointment in the Bank in 1986.
- S. I have thoroughly gone through the documents filed by the management, amongst them there is a circular letter dated 7-3-1977 under which an executive is entitled to be reimbursed of the salary of the driver up to 300 per month, engaged by him for official purposes and for services in his personal employment. The management has placed reliance on the case of Punjab National Bank Vs. Ghulam Dastgir, reported in 1978 (36) FIR, Page 198.
- 9. After having gone through the evidence on record, both documentary and oral led by the parties, it is undisputably clear that the claiments prior to their appointment as Peons in the Bank, were serving as personal drivers of the executives by whom they were engaged and their salary was being paid, not by the Bank, but by the executive who engaged them. It is also evidently clear that there was no supervision and control of the Bank over the claiments as they were under the absolute control and supervision of the executives, who had engaged them. There is nothing on record to show that prior to the date of their appointment in the Bank in 1986 as Peon, they were appointed by the Bank.
- 10. On the basis of evidence on record before me, I find that the executives of Scale-IV and above were provided car as perquisite and the claiments were the personal drivers of the respective executives and were not employees of the Bank. The case law, as referred to here-in-above, fully applies in the present case. In the said case, it has been held that it is not unusual for public sector industry or a nationalised banking institution to give allowances to its' high level officers, leaving it to them to engage the services of drivers or others for fulfilling the needs for which allowances are meant.
- 11. Therefore, it is held that prior to their appointment as Peon in 1986, the claimants were personal drivers of the respective executives of the

Bank and were not employees of the Bank, as a result of which the claiments are not entitled to regularisation of their services prior to the dates of their appointment in the Bank as Peon in 1986. Parties shall, however, bear their own costs.

12. The Award is given accordingly.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 9th April, 1996.

नई दिल्ली, 17 मई, 1996

कारुआर 1682 अधि। भिक्त विवाद असिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 17 के अनुसरण में, के दी। सरकार सेन्द्रन वैक ऑफ इंडिया के प्रवस्थान के संबद्ध नियोगकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिद्द श्रीबोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अंखोगिक अधिकरण, 1, मुम्बई के पचपट की प्रकाशित करनी है, जो केन्द्रीय सरकार की 4-5-96 की प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12025/7/92-प्राटंश्यारश्यी० 2)]ः । गण्डीर बोल्एम० डेनिड, इंस्क स्रविकारी

New Delhi, the 17th May, 1996

S.O. 1682.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, 1 MUMBAI as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CENTRAL BANK OF INDIA and their workmen, which was received by the Central Government on 14-5-1996.

[No. L-12025]92[IR-(B-II)]
B. M. DAVID, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-1/11 OF 1993 PARTIES:

Employers in relation to the management of Central Bank of India, Bombay.

AND

Their workmen

APPEARANCES:

For the Management: Shri Ramaswamy, Advocate For the Workman: Shri Nargolkar, Advocate

INDUSTRY: Banking STATE: Maharashtea Munabai dated the 18th day of April, 1996

AWARD

This case has a chequered history. It appears that on 9th and 10th June, 1991 heavy rains took place in Bombay. It is alleged that this resulted in disruption of traffic and many employees of Central Bank of India located at Bombay could not reach their office. The union of the said Bank's employees, espousing the cause of such employees proposed that for absence on the said dates, the management may grant special leave to its employees, who could not so attend their offices. The Bank declined to accede to this request relying upon its earlier circular dated 3rd March, 1988, wherein pursuance of guide lines issued by Indian Banks' Association, a decision interalia had been taken as follows:

"B. Absence of Bank Employees due to natural calamities or civil commotion or any other cause beyond the control of the Bank.

If the closure of the Bank is necessitated for reasons of natural calamities as fire, tain, deluge or civil disturbances such as riots or any other cause beyond the Central Bank of India, only appropriate leave including casual leave, but not special leave should be given to bank employees in terms of paragraph 511 of the Sastry Award."

- 2. It would be interesting—to note that special leave aplications were submitted by such employees in format Ex. F annexed to the written statement of claim but the management by its letter dated 14th August 1991 declined to grant special leave.
- 3. It appears that the union espousing the case of the Bank employees in question filed a Writ Petition in the matter viz. No. 242 of 1991 in the High Court of Bombay which was rejected by a learned single Judge of the High Court. But, in appeal the parties agreed that the dispute be got referred for adjudication. The apepal pending before D.B. of the High Court was disposed of accordingly and the Government of India in the Labour Department made the following reference:
 - "Whether the demand of the Central Bank Employees Union, Bombay that the employee of the Central Bank of India employed in Bombay, who could not attend their duties on account of heavy rains and consequent total disruption of transport system in Bombay on June 10, 1991, should have been granted special leave for the said day, is justified? If so, to what relief are the concerned employees entitled?"
- 4. The union has filed its detailed written statement of claiming justifying its demands. The management has contested the vision by filing a written reply. Both the sides have filed some

documentary evidence but have chosen not to lead any oral evidence.

- 5. I have heard the learned counsel for the parties in great details and have perused the pleadings and the documents filed before me.
- 6. At the outset, I may state that a similar dispute was raised by the employees of this very Bank in respect of refusal to grant special leave for 17th, 25th and 26th June, 1985 and the dispute was subject matter of Reference No. CGTT-1/24 of 1990. Therein, I have after going through the entire material taken a categorical view that the demand of the employees for grant of special leave was not justified and proper. An award has been made only few days back viz. on 4th April, 1996.
- 7. Now, in the present case, I do not find any regulation, circular, award or settlement binding on the parties which may conter a right on the Bank employees to demand special leave for the days they remained absent due to disruption of traffic due to heavy rains. The Sastry Award already makes provisions for grant of casual leave for its employees, which they can always avail of, 'f exigencies so require. Right to grant of special leave does not flow from any regulation or binding settlement or award between the parties.

8. A plea was taken that refusal to grant special leave amounted to a change in terms and conditions of service. The argument has to be noticed only for the sake of rejection. A change takes place when an existing condition is altered. It is not so in the present case. Hence, this contention

is devoid of merit and is rejected.

- 9. Much reliance was placed by the union on an order of Maharashtra Government dated 20th June, 1991 whereby it declared special leave for 10th June, 1991. Likewise, reliance was placed by the union on the order of the Food Corporation of India dated 29-11-90 in respect of special leave made admissible for 24-9-1990 and 24-10-1990. So far as 24-9-1990 is concerned, it was said that this was due to disruption of suburban trains due to heavy rains.
- 10. In my opinion, reliance upon these two orders is quite misplaced. Each employer has right to choose and decide in which particulars exigencies, which kind of leave shall be made admissible to its employees. How a particular industry has dealt with the situation in a particular region is more relevant and germane for deciding a dispute like this. I may take judicial notice of the fact that a large number of Banks exist in Mumbai. The union has not cared and dared to place before the Tribunal material to show how different Banks in Mumbai dealt with this situation. In absence of such materail advanced by the union, union can not contend that the management be directed to act in the manner in which the Maharashtra Govermnent or the Food Corporation of India dealt with the situation.

- 11. The management has placed before the Tribunal copy of letter dated October 17, 1995 issued by the Indian Banks Association, a general and apex body of Banking Institutions of the country, having a large membership which shows that no other bank referred the question of grant of spcc'al leave to employees of Banks for 10th June, 1991. Then, I have before me a letter of Bank of India dated 24-11-1995 stating that this Bank did not grant any special leave to its employees for 10th June, 1991. The same is the tenor of the letter of Punjab National Bank dated 25-11-1995. Thus it is abandently clear that the Banking Industry itself did not deem it proper to grant special leave to its employees who could not attend the various banks due to disruption of transport because of heavy rains on 21-6-1991. The relevant Indian Banks Association guidelines applicable to the contingency in hand has already been reproduced above and does not help the union.
- 12. I may here state that the regulation of leave is a managerial function and this Tribunal can not interfere with this function unless it is in contravention of any law or is contrary to any binding settlement, award or regulation. It has not been shown that in the present case, the management contravened any law or acted contrary to provisions of any binding settlement, award, regulation or rule of law.
- 13. I may state that I had an occasion to deal with a similar matter in Reference No. CGIT-1 24 of 1990 disposed off by me on 4th April, 1996, wherein I have taken this very view. I find no good, cogent or justifiable reason to take a different view. I thereford, find that the claim of the union is not justified and it is not entitled to any relief. Award is made accordingly.

[No. L-12011|37|86-D-H-A|IR(B-II)] R. S. VERMA, Presiding Officer

नर्ह विरुलं ।, 17 मई, 1996

का० आ०. 1683-— आँद्योगिक विवाद अधिनित्रम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्द्रल बीक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के शंबाह नियोजको और उनके कर्मकारी के में निविष्ट औद्योगिक जिवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 1, मुम्बई के पंचपट की प्रकाशिन करती आंबकरण, है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/37/86-डी॰ 2ए/म्राई श्रार (वी 2)] बी०एम डेबिड, डैस्क ग्रधिकारी

New Delhi, the 17th May, 1996

S.O. 1683.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 14-5-1996.

> (L-12011|37|86 DHA/IR(B-H)) B. M. DAVID, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAL

PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma. Presiding Officer

Reference No. CGIT-1/24 of 1990

PARTIES:

Employers in relation to the management of Central Bank of India

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Management: Shri Rele, Advocate. For the Workman: Shri Dharap, Advocate. INDUSTRY: Banking STATE: Maharashtra Mumbai, dated the 4th day of April, 1996.

AWARD

Heard both the sides extensively and perused the pleadings and the record.

The appropriate Government by its order dated 21-3-90 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :--

- "Whether the demand of Central Bank Workers Organisation, Bombay that those employees of the Central Bank of India, Chander Mukhi, Nariman Point, Bombay who could not attend to their duties on 17th, 25th and 26th June, 1985 on account of heavy rains and consequent total disruption of transport system in Bombay should be granted special leave for those days is justified? If so, to what relief are the concerned workman entitled?"
- 2. The union filed its written statement of claim on 27-6-90 wherein its inter alia averred that reference to employees of the Central Bank of India, Chandra Mukhi, Bombay in the order of reference was not correct and the organisation was approaching the appropriate Government for appropriate rectification. It appears that no such steps for rectification of the above quoted schedule have been taken; at least the Tribunal is not aware of any such rectification. Learned Counsel for the parties have also argued the matter, as coined to those

employees of the Central Bank of India, Chandra Mukhi, Nariman Point, Bombay, who could not attend to their duties on 17th, 25th and 26th June, 1985. Heace, in spite of the averment that the written statement of claim was being filed on behalf or all the employees of Central Bank of India at banday, who could not attend to their duties on the said dates, the Tribunal confines the award to the employees of Central Bank of India, Chandra Mukhi, Nariman Point, Bombay who could not attend to their duties on the said dates.

- 3. Here, I would pause and state that the union has not cared to state as to how many employees could not attend to their duties in the said dates even at Chandra Mukhi, Nariman Point, Bombay. However, much does not there upon this factor, hence no more of this.
- 4. Now, the case of the union is that heavy rains took place in Bombay on 17th, 25th and 26th June, 1985 and there was a total disruption of the transport system on the said dates; hence the employees could not attend to their duties on the said dates. A demand was made for grant of special leave with regard to the employees who would not attend to their duties on the said dates for reasons aforesaid but the management declined to eccede to this request. The matter was taken up in conciliation but to no effect. The appropriate Government refused to make a reference with regard to the dispute, whereupon the organisation filed Writ Petition No. 799 of 87 in the High Court of Bombay. The High Court vide its judgment dated 5-1-88 directed the appropriate Government to refer the dispute for adjudication, where upon the present reference was made.
- 5. The case of the union is that the Maharashtra Government had allowed special leave to its employees who could not attend to their offices on the said dates due to heavy rains and total disruption of transport. Reliance was placed on a circular of the Maharashtra Government issued in this regard on 5th August, 1985.
- 6. Likewise reliance was placed on a circular of Synd-cate Bank, Bombay Zonal Office dated 15th January by which the said Bank allowed special casual leave to its employees, who could not attend to their duties on the dates under reference due to heavy rains and disruptions of transport.
- 7. Reliance was also placed on a circular dated 4th March, 1985 issued by Indian Banks Associa-
- 8. Some other pleas were also taken but not pressed at the time of arguments. It was prayed that the Tribunal may held the demand of the organisation justified.
- 9. The management has opposed the claim. It has challenged the assertion of the union that there was a complete disruption of transport on the dates in question due to heavy rains. It is submitted that

the union represents only a microscopic minority of the total employees of the Central Bank of India. In Bombay, it had a membership of 39 out of 3796 employees. There were other unions of the employees of the Central Bank of Bombay. No other union had raised such a demand. A very large number of employees had attended to their duties on the said dates. It was asserted that Bombay office and other establishments of the Bank were open on the dates under reference.

- 10. It was pleaded that circular of the Maharashtra Government had no relevance. Decision taken by the Syndicate Bank was not binding on the Central Bank of India Circular dated 4th March' 85 issued by the Indian Bank Association had no relevance. A specific decision was taken by the said Association on this very specific issue as would be evident by Ex. 'B' dated 17th July, 1985.
- 11. It was pleaded that the demand of the union was not justified and deserved to be rejected.
- 12. During the course of arguments, the union relied upon the provisions of the Shastry Award, Desa Award and Bipartite Settlement dated 19th October, 1966. It also relied upon the circulars of Maharashtra Government and those issued by the Indian Banks Association and the Syndicate Bank. Management has urged that since Bi-partite Settlement of 1966 was applicable, reference to Sastry Awards and Desai Awards was not of much consequence. It is urged that grant of special leave is not a right of an employee and it is in the discretion of the management and the management has exercised the discretion properly.
- 13. I have considered the rival contentions and have perused the material available on record. I have also gone through the relevant provisions of Shastry Award, Desai Award and the Bipartite Settlements.
- 14. It appears to be true that heavy rains did take place in Bombay in the three dates mentioned in the reference viz. 17th, 25th and 26th June, 1985. However, it has not been established satisfactorily that there was total disruption of the transport system. The zerox copies of various attendance registers of the dates in question go to show that office of Central Bank, India in Bombay were attended to by and large number of employees. Assuming, but not holding that there was a total disruption of transport system, can it be said that the employees were entitled to claim special leave on this account? To my mind, the circular of Maharashtra Government in this regard, is not of any help. Each individual employer has a right to take its own decision as to under what circumstances, special leave would be granted to its employees. This is equally true of the circular issued by the Syndicate Bank.

- 15. Now, I may refer to March 4 (1985) circular of the Indian Banks Association suffice it to say that the circular was issued to cover contingencies of a different type altogether and is not attracted to a situation like the present one. Indian Banks' Association in its letter dated 17th July 1985 itself opined that there was no case for grant of special leave for absence of employees on 17th, 25th and 26th June. Certain other Banks also did not consider it a fit case to grant special leave. Letter of Central Bank of India dated 28-10-1995, of Punjab National Bank dated 31-10-1995, letter of Union Bank of India dated 28th October, 1995 show that these Banks did not deem it proper to grant special leave to their respective employees, who did not attend offices due to heavy rains in the three dates undue reference. The Premier Bank of the country viz. the State Bank of India also acted likewise and did not grant special casual leave to its employees for the said dates.
- 15. I have carefully gone through the relevant provisions of Shastry Award, Desai Award and Bipartite Settlement of 1966 and I do not find any specific provision which may entitle the employees of grant of any special leave, as of right. Shri Dharap did concede very frankly that there was no direct provision to govern the situation and urged that when Maharashtra Government and at least one Bank considered proper to grant special leave for the dates under reference, the demand of the union can not be said to be unfair.
- 17. I have considered this asptet of the case. Each individual employer is entitled to deal with its employees in matter of grant of special leave according to its own policies. If in the present case, the management did not consider it proper to grant special leave for the three dates-question, it can not be faulted.
- 18. I. therefore, find no merit in the claim and reject the same. Award is made accordingly.

R. S. VERMA, Presiding Officer नई दिल्ली, 17 मई, 1996

का०आ०. 1684 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बस्बई नं० 1 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[सं ०एल – 30011/10/92 – आई स्रार (विविध)/स्राईस्रार (मी-1)] के बी बी उसी, डैस्क स्रिधकारी

New Delhi, the 17th May, 1996

S.O. 1684.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award

of the Central Government Industrial Iribunal Bombay No. I as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bharat Petroleum Corpn. Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on the 15-5-96.

[No. L-30011 10 92-IR(Misc) IRCI]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI PRESENT:

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer Reference No. CGIT-1/76 of 1992

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bharat Petroleum Compn. Ltd.

AND

Their workmen

APPEARANCES:

For the Management: S|Shri Rele and Pota, Advocates

For the Workman: Shri Devdas, Advocate INDUSTRY: Petroleum STATE: Maharashtra Mumbai, dated the 24th day of April, 1996

AWARD

1. Workmen before me, represented through their union Pttroleum Employees Union, Tel Rasayan Bhawan, Tilak Road, Dadar, Bombay are employees of Bharat Petroleum Ltd. Bombay, for short company and fall in the category of Retail Outlet Fitters or Technicians Retail, as they are known now. Each workmen is assigned a certain number of Petrol Pumps for maintenance, be they within municipal limits of a town or partly within and partly outside municipal limits of a town or wholly outside the municipal limits of a town. Admittedly, the Corporation advances loans to these workmen to purchase their own conveyances with a view to facilitate their movements. These workmen have to attend to complaints received from these petrol pumps within their geographical jurisdiction. They are required to do routine maintenance of the potrol pumps and have also to repair breakdown reported to them. The nature of the work is such that no uniform hours can be maintained. The number of petrol pumps to be attended to, depends upon the complaints received and a break down may be repaired in half an hour but the other may take even six hours to be repaired. A diary is maintaintd by each workman in this regard. There is also a job report and an imprest account to be maintained by them. There are days when the services of a workman may not

be wholly unfixed but then there are days when he may have to work for hours,

- 2. Now, all these petrol pumps do not belong to the Bharat Petroleum Ltd. Admittedly, there are three categories of petrol pumps. A category outlets are owned by the company. In 'B' category, the land belongs to the individual dealer and the installed equipment belongs to the company. In 'C' category, the land as well as the installations belong to the individual dealer.
- 3. The undisputed position is that these workmen do not have a fixed office or factory premises. They operate from their individual residences and cover the various petrol pumps where maintenance or repair work is undertaken.
- 4. The further undisputed position is that for going out, a travelling allowance is paid to each workman. Each workman is also paid a Bhatta to cover his outdoor expenses like lunch, dinner, etc.
- 5. The grievance of the union is that the company has failed to stipulate fixed working hours for these technicians with the result that they are being compelled to work overtime with no compensation. Under the relevant legal provisions, the company ought to have stipulated fixed working hours for these workmen so that they are not exploited.
- 6. It appears that the demand of the union was not acceded to by the company and the matter was taken into conciliation but the same failed and eventually, the appropriate Government referred the dispute in the following terms for adjudication to the Tribunal:
 - "Whether the action of the management of Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Bombay in not stipulating the working hours of Retail Outlet Fitters now designated as Technician Retail, is legal and justified? If not what relief the workmen are entitled to?"
- 7. The union filed its written statement of claim on 22nd March, 1993 and alleged that under various legal provisions, to what I shall refer at the appropriate place, the company was under an obligation to stipulate the working hours of these workmen; In not doing so it was acting illegally and was also subjecting these workmen to long hours of work without adequately compensating them upon such pleas is inter alia prayed for the following reliefs:
 - "It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal direct the management of Bharat Petroleum Ltd. to
 - (1) fix up and stipulate daily working hours of Technicians (Retail);
 - (2) compensate these workmen for working beyond eight hours daily since

- their joining the service of the Corporation as Technicians (Retail) old designation: Retail Fitter."
- 8. The claim has been resisted by the company on a number of grounds and has filed a detailed reply to the written statement of claim. The union filed its rejoinder to the reply of the company. Both the sides have produced documentary as well as oral evidence in support of their respective averments and pleas. I have also heard the learned counsel for the parties in extenso. Both the sides have filed written submissions also.
- 9. To complete the narration it would not be out of place to mention that during the pendency of these proceedings, the union moved an application for interim award on 4-2-94. This application was opposed by the company by filing a written reply. This application was rejected by my predecessor vide order dated 16-12-94.
- 10. During the course of final arguments, Shri Devdas Learned Counsel for the union did not press the claim qua relief No. 2 reproduced above and confined his arguments to relief No. 1.
- 11. The contention of the learned counsel for the union is that all the retail outlets viz. the Petrol pumps the maintenance and repairs whereof are undertaken by the workmen fulfill the character of a 'factory' as defined in Section 2(f) of the Factories Act, 1948. Section 31 of the said Act lays down that no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than 48 hours in any week. Section 54 of that very lays down that subject to the provisions of the Act. No adult worker shall be required or allowed to work in factory for more than nine hours in any day. Section 59 of this very Act makes a provision for payment of extra wages and provides that where a worker works in a factory for more than nine hours in any day or for more than 48 hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate of twice his ordihary rate of wages. The workmen are covered under Industrial Employment Standing Orders, Act, 1946. The company has its own certified The schedule to the Industrial standing orders. Employment (Standing Orders Act) at item No. 6 provides for manner of intimating the workmen the reriods of hours of works, holidays, pay days and wage days but the company has not complied with this provision. It was incumbment on the company to fix and stipulate the working hours of these workmen. It was submitted that the retail outlets were covered by the provisions of the Factories Act and a notification dated 9th July, 1985 issued by the Government copies whereof where endorsed by the company to all the retail outlets directed the letter to get them registered under the relevant provisions of the Factories Act in order to carry out the diverse statutory obligations imposed by the provisions of the Factories Act,

- 12. It is submitted that non-compliance with these provisions has resulted in exploitation of the workmen and they are made to work for more than 9 hours a day and for more than 48 hours a week without entitling them to overtime wages. Hence, the company be directed to fix and stipulate exact working hours of these workmen.
- 13: I have considered the rival contentions and have perused the record. There is no doubt that the Petrol Pumps have been covered under the Factories Act and the management issued circular Ex. A. annexed to the application for interim relief, by the union. This position is not in dispute before me.
- 14. However, it is contended on behalf of the management that the workmen in question are not employed in the petrol pumps. The provisions of Sections 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63 and 64 of the Factories Act, occurring in Chapter VI of the Act are applicable to workers' working in the Factory. Hence, these provisions are not applicable to the present workmen.
- 15. To my mind this contention is well founded and deserves to be accepted. All the Sections aforesaid are applicable to workers 'working in a Factory'. The present workmen can not be said to work in any particular petrol pump, which is assigned to a particular workman, though he does work of repairs and maintenance at such petrol pumps which are assigned to him. I think expression 'working in a factory' has to be contradistinguished from 'working at a factory'. The concept of a worker working in a factory would involve that he is employed in a factory. The present workmen are not at all employees of any particular petrol pump and do not work in any petrol pump but have to move from one petrol pump to another petrol pump, keeping in view the exigencles of work. For this very reason, fixing, notifying and publishing of the working hours is simply impracticle and non-workable in actual practice. It is an admitted position that the workmen operate from their respective residences. There is a great deal of flexibility in their work schedules. There is no precise control on their movements; which petrol pump is to be visited at what time is left to their discretion, of course depending upon the expensies of work. Today, it may be petrol pump A demanding attention in early hours of the day tomorrow, it may be petrol pump B, on another day, it may be petrol pump C and so on, when such is the position, how can precise work hours he fixed? Hence, in my opinion, the various provisions of the Factories Act are not attracted to there workmen.
- 16. Now, it is an admitted position that long term settlement have been entered into between the management and the various employees unions, representing the workmen and these settlements

govern the terms and conditions of the employment. Earlier, there was a long term settlement dated 22-8-1986 and this long settlement was operative from 1-6-1985 to 31-5-1989. This was replaced by a long term settlement signed on 25-3-1991. However, understanding between the parties had already been reached on 8-10-1990 and 10-10-1990. Since, an approval was granted by Government of India on 8-3-91, the settlement was signed on 25-3-1991. Meanwhile, the present demand had been raised by the union, which was a party to the said settlement. Clause 18 of the settlement pertained to working hours. These settlements replaced on still earlier settlement dated 50-4-82 which inter alia provided

"Retail Fitters listed in Annexure 22 will continue to be allowed overtime as per practice prevalent immediately prior to the effective date of this settlement. It is specifically understood between the parties that this will not be admissible for any other Retail Fitter who is not listed in the said annexure."

Amexure 22 listed only five employees, who were employees of erstwhile Burma Shell Co. This clause in the settlement excluded specifically other Retail Fitters.

- 17. Learned counsel for the union urged that this was a discriminatory clause and hence was improper. In my opinion, reasonable classification is always permissible. Before the management, there was a category of erstwhile Burmah Shell employees and the other category of the managements' own employees. The terms and conditions of employment of employees of erstwhile employees of Burmah Shell Co. coult not have been changed to their detriment. This explains and justines two different treatments, meted out to two distinct categories and can not be a ground for any genuine grievance on the part of the union, which was a signatory to the settlement.
- 18. Clause 4(d) of Part III of the settlement dated 30-4-82 was not modified for superseded by the subsequent settlements and hence the said clause is still extant and applicable to the present workmen. This position has been squarely admitted by the union in its application for grant of interim relief.
- 19. On behalf of the union, it was contended that there was no estoppal against law and hence the union is entitled to claim fixation of working hours in spite of the long term setlement and consequently the workmen are also entitled to overtime wages. I have already said that the provisions of the Factories Act were not applicable to the present workmen. Hence, there is no question of estoppal against law. The terms of the long term settlement is binding between the parties and in the peculiar circumstances of the case, the union can not demand fixation of working hours.

- 20. Union contended that under item No. 6 of the schedule to the Industrial Employment (standing Orders) Act, 1946, which schedule was applicable to the present workmen, the management was bound to inform the workmen of their hours of work, helidays, pay days and wage rates and this has not been done and the management be directed to do so. I have already held that in the very nature of things this was not practicable and workable. Hence, this contention is not valid in the peculiar circumstances of the nature of work of these workmen.
- 21. The contention was reinforced by an argument that these workmen were subjected to excess to do of work without compensation of overtime and hence they deserve to be compensated for the overtime done by them, suffice it to say that claim for overtime was abandoned during the course of arguments, as would be evident from endorsement dated 18-4-96 made on page 9 of the written arguments of the union.
- 22. Certain precedents were cited before me on behalf of the union to show that stipulations of in the long term settlement in violation of law can not bind the workmen. I need not encumber the award by citing these precedents because the rates of the decisions cited before me and detailed at pages 8 and 9 of the written arguments, is unexceptionable. However, as discussed already, there is no violation of law in as much as the workmen herein do not work in any factory.
- 33. For the self same reason, the precedents deaded at page 11 of the written arguments of the union do not alter the position.
- 24. Here, I may state that the present union under clause 1(a) of the settlement dated 25-3-91 had agreed not to raise any demand involving directly or indirectly any additional financial burden during the period of operation of the settlement z. 1-6-1989 to 31-5-1993. To my mind, this chause precludes the union from willings a demand of the present nature, even though claim for overtime compensation has been abandoned by the union.
- 25. The management relied upon the fact that the dispute pertaining to rationalisation of the working bours had been referred by the appropriate Government to CGIT II, Bombay and the claim of the union has been negatived by the said Tribunal. Suffice it to say that the full text of the award has not been placed on record and hence it would not be proper for me to make any comments on this aspect of the matter.
- 26. Taking an overall view of the circumstances of the case, I am of the view that the claim of the union deserves to be rejected. It is so rejected.

I make on award accordingly. The same be duly submitted and notified.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 मई, 1996

कारुआर 1685. ---- श्रीचोधिक विवाद अधिनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जीतमं एप पी ती एग के प्रवच्यतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निधिष्ट आंचोधिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आंचोधिक अधिकारण, बम्बई गेर्र 1 के पंचएट की प्रवचीजन करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 15-5-96 की प्राप्त हुआ था।

[सं॰ एल-30012/11/85 डो 3(बी)/ब्राई आर (सी-1)] के॰बो॰बी॰ उसी, डैस्क ब्रधिकारी

New Delhi, the 17th May, 1996

S.O. 1685.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay No. 1 as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M|s H.P.C. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 15-5-1996.

[No. L-30012]11;85-D-IV(B) [IR(CI)] K.V.B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI PRESENT

> Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer

MISC. APPLICATION NO. 9 OF 1994 (Atising out of Ref. No. CGIT-10 of 1987) PARTIES:

Hindustan Petroleum Corpn. Ltd. Bombay-74.

: Applicant

 V_{S} .

Petroleum Employees Union, Bombay.

: Opponent

APPEARANCES:

For the Applicant: S|Shri Rele & R. N. Shah, Advocates.

For the Opponent: Shri Gopal Krishan and Ms. Shobha Gopal, Advocates.

Industry: Petroleum.

State: Maharashtra.

Mumbai, dated the 28th day of March, 1996.

JUDGMENT

Shri Rele for management along with Shri R.N. Shah.

- 22. Shri Gopal Kishnan for Union along with Ms. Shobha Gopal.
 - 3. Heard the learned counsel for both the sides.
- 4. By this application, the management seeks review medification of award made by my learned predicessor on 15th September, 1994.
- 5. The admitted facts of the case are that the workman was subjected to a domestic enquiry in consequence of which he was dismissed from service w.e.f. 21st September, 1984.
- 6. An industrial dispute was raised and was referred by the appropriate Government to this Tribunal vide letter dated 6-4-1987.
- 7. Before this Tribunal, the union interalia challenged the legality, propriety and fairness of the domestic enquiry. Evidence was led by both the sides and by the award in question, my worthy predecessor found that the domestic enquiry was legal, fair and proper. However, he held that purishment of dismissal deserved to be set aside. In this view of the matter, he set aside the order of dismissal and directed reinstatement of the workman with 25 per cent of back wages.
- 3. The contention of the management is that the matter had been heard only on the question of legality, propriety and fairness of domestic enquiry. When the learned Presiding Officer agreed with the contentions of the management, he should have a ven opportunity to the management to show that in particular circumstances of the case, penalty of dismissal was proper. This opportunity was not given to the management. Secondly, the workman in the normal course would have superannuated on 31-8-1989 and hence there could have been no question of his reinstatement.
- 9 The application has been opposed with great vehemence by the union. It is submitted that there is no power in this Tribunal to review the award already passed. It was admitted that workman would have normally superannuated on 31-8-1989 and hence there was no question of reinstatement. However, it was submitted that the management in the first instance should have led evidence regarding the propriety of punishment as well and was not entitled to place any fresh evidence once the Tribunal had found that domestic enquiry was fair, legal and proper.
- 10. I have considered the rival contentions. I may state that the parameters of the power of review exercisable by this Tribunal have been laid down by the apex Court in the case of Grindlays Bank 1980 I LLJ 327. In para 13 of the said Judgment, the apex Court has recognised the types of different situations. It was held that there was no power to review on merits when the error

sought to be corrected is one of law and is apparent on face of record. However, it was held that a procedural review was permissible when the order under review was passed under a misapprehension by it. Learned counsel for union tried to suggest that this ruling pertaining to setting aside of an exparte award and can not be construed to lay down a general proposition of law. With respects, I do not agree with this proposition and I find that this Tribunal has jurisdiction to rectify a palpably erroneous order, if it has been passed on some misapprehension of facts.

- 11. Now, this raised the question as to at what stage, the employer should place material before the Tribunal to sustain its action of dismissal or discharge when the Tribunal is considering a case under Section 11A of the Industrial Disputes Act.
- 12. Shri Rele submitted that this could be done only after the Tribunal has recorded the finding on the legality, fairness and propriety of the domestic enquiry. Till finding on this preliminary issue is recorded, there is no shape for the management to lead evidence.
- 13. In my opinion Section 11A of the I.D. Act does not contemplate two distinct stages where enquiry is legal, fair and proper. The foundation for such a contention has to be laid in reply of the employer to the written statement of claim of the workman and all such material as was available to the management in this regard, should be plac-

- ed on record along with pleadings. When the issue of legality, propriety and fairness of domestic enquiry has been raised, and the legality and propriety of termination dismissal or discharge had been challenged, the entire material must be placed on record. Then, the Tribunal may consider if in totality of circumstances, the dismissal or discharge could be justified or not and if any modulation in the punishment was required.
- 14. Such a plea that the punishment deserved to be upheld could be taken as one alternative additional plea. In the present case, this has not been done. No material has been placed on record in justification of the penalty of dismissal.
- 15. However, I find that two mistakes which have admittedly crept in the impugned award deserve to be rectified. The workman was dismissed w.e.f. 27-9-1984 and would have superannuated normally on 31-8-1989. There is no dispute on this aspect. Hence, there could be no reinstatement as directed by the award. Secondly, the 25 per cent of wages could be payable only from the date of dismissal i.e. 27-9-1984 to his normal date of superannuation i.e. 31-8-1989. Application for review is thus partly allowed and the impugned award shall stand modified as indicated above. In the circumstances of the case, parties shall bear their own costs of these proceedings.

R. S. VERMA, Presiding Officer